(1100/GG/NKL)

(प्रश्न 221)

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों के संबंध में है। माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आया है। महोदय, देश में वर्तमान में 5028 जन-औषधि केन्द्र संचालित हैं, यह माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में 206 केन्द्र संचालित हैं। 714 दवाइयां केन्द्रों में उपलब्ध हैं। केन्द्रों में सस्ती दवाई 50 से 90 प्रतिशत सस्ती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी देश में मंहगी दवाइयों की वजह से सालाना लगभग 6 करोड़ लोग गरीब से और गरीब हो जाते हैं। आज भी देश के बहुत से सामुदायिक केन्द्रों में प्रधान मंत्री जन-औषधि केन्द्र संचालित नहीं हैं। बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बहुत से सामुदायिक केन्द्रों में आज भी जन-औषधि केन्द्र संचालित नहीं हैं। ऐसे केन्द्रों में कब तक संचालित किया जएगा? इसी के साथ प्रधान मंत्री जन-औषधि केन्द्रों में सभी दवाइयां सस्ती नहीं होती हैं। सिर्फ मल्टी-विटामिन, दर्द की दवाइयां और कुछ साधारण सी दवाइयां ही सस्ती होती हैं। शेष महत्वपूर्ण दवाइयां भी ब्रांडेड दवाइयों से मंहगी होती हैं। ऐसा क्यों है? सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, ताकि उनके लिए सस्ती दवाइयां मिल सकें?

श्री मनसुख एल. मांडविया : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मोदी-वन सरकार बनी थी, तब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मेरे देश में किसी की बिना दवाई से मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरी सरकार गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचितों के प्रति समर्पित रहेगी। इस बात को चरितार्थ करने के लिए सारे देश में जन औषधि-केन्द्र चलाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य जी ने जो कहा है, देश में 3 करोड़ 8 लाख व्यक्ति, मतलब 75 लाख परिवार हर साल दवाइयों का खर्च बढ़ जाने से, घर में बड़ी बीमारी आ जाने से, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। उस परिवार के पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है और परिवार में मुश्किल होती है। ऐसी स्थिति में देश में 5410 जन-औषधि केन्द्र आज के दिन में हमने

शुरू कर दिए हैं। दूसरा, जन-औषधि केन्द्रों पर मैक्सिमम 50 प्रतिशत और मिनिमम 80-90 प्रतिशत से कम रेट पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दवाइयों के रेट ब्रांडेड दवाइयों से ज्यादा हैं। किसी भी जन-औषधि स्टोर पर, हमारा मैन्डेट ही यही है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा प्राइस हम नहीं ले रहे हैं। 50 प्रतिशत से कम प्रतिशत पर हम जन-औषधि केन्द्रों के माध्यम से दवा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए आज 5410 जन-औषधि केन्द्र सारे देश में हैं।

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 5 साल में सिर्फ 5018 जन-औषधि केन्द्र संचालित किए हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी ने 714 दवाइयों का उल्लेख किया है। आज भी उन केन्द्रों में 714 दवाइयां उपलब्ध नहीं रहती हैं। सिर्फ सामान्य सी दवाइयां ही उपलब्ध रहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ब्रांडेड दवाइयों की कीमत क्या दवा कंपनी तय नहीं करती है? दवाइयों की कीमत ड्रग्स कंट्रोल ऑर्डर तय करती है। क्या डीपीसीओ के तहत दवा कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से लगातार ब्रांडेड दवाइयां महंगी होती जा रही हैं, जो लोगों की पहुंच से दूर हैं?

(1105/KN/SRG)

दूसरा, केन्द्र सरकार सरकारी व प्राइवेट डॉक्टरों के लिए सरकारी सस्ती दवाई जेनरिक दवाई की पर्ची लिख सकें, इसके लिए एमसीआई के तहत नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। वह नियम आपने जारी किया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। आज भी डॉक्टर लगातार महंगी दवाई लिख रहे हैं। क्या इसके लिए सरकार अनिवार्य कानून बनाएगी, जिससे कि सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर पर्ची लिख सकें?

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, महत्वपूर्ण विषय यह है कि जेनरिक मेडिसिन क्या है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या है? जेनरिक मेडिसिन यह शॉर्ट नेम है और शॉर्ट नेम से दवा सस्ती होती है एवं ब्रांडेड से खर्च ज़्यादा हो जाता है। फोर एग्जाम्पल, आपने एक लीटर पानी लिया। इस पानी की कीमत शायद 2 रुपये है। वही पानी एक लीटर बिसलरी में चला गया तो उसकी प्राइस 12-15 रुपये हो जाती है और वह ब्रांडेड एक्वाफिना में चला गया तो 24 रुपये हो गया। यह शॉर्ट नेम है,

लेकिन वह तो पानी ही है। जेनरिक मेडिसिन मतलब शॉर्ट नेम है। पेरासिटामोल एक शॉर्ट नेम है। पेरासिटामोल ड्रग है, वह कभी कैलपोल के नाम से बेचते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। आज अमरीका में जाइए तो अमरीका में अगर पाँच टेबलेट्स लोग लेते हैं तो उसमें से एक टेबलेट इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। सारी दुनिया सिक्स टेबलेट्स लेती है तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। जेनरिक मेडिसिन से लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध होती है और यह सस्ती दवा उपलब्ध हो। जेनरिक मेडिसिन का प्रचार हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमने टोकन नहीं किया है, हमने टोटल किया है। यह स्कीम जब वर्ष 2008 में शुरू हुई थी, जब हमारी सरकार आई तब छ: साल के बाद केवल 72 जन औषधि स्टोर्स थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और देश में जन औषधि स्टोर्स की श्रृंखला चलाई। उसका फायदा यह हुआ कि जो पहले जेनरिक मेडिसिन का शेयर मार्किट में केवल दो परसेंट था, वह आज बढ़कर आठ परसेंट तक पहुँच गया है। आठ परसेंट जेनरिक मेडिसिन का शेयर बढ़ जाने से देश के गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को दो हजार करोड़ का फायदा हुआ है। यह गरीब लोगों के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, उसका यह नतीजा है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): फेक मेडिसिन भी मिलती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको एलाउ नहीं किया है। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं एलाउ करूँगा। श्री अधीर रंजन चौधरी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपका अगर जेनरिक के बारे में इतना ध्यान है तो आप एक्ट में क्यों नहीं लाते? आपके एक्ट में यह जेनरिक की डेफिनिशन है? आप अपने से बोलते हैं कि यह बिसलरी में भाव बढ़ जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। आपकी कोई डेफिनिशन है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण मत दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल. मांडविया : यह डेफिनिशन का सवाल नहीं है। यह कमिटमेंट का सवाल है और लोगों को सस्ती मेडिसिन मिले।...(व्यवधान) सवाल यह है कि देश की जनता को सस्ती हेल्थ केयर मिले। उसके लिए प्रधान मंत्री मोदी जी का कमिटमेंट है, वह जन औषधि स्टोर के अलावा देश में 10...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिये। आप इनकी हर बात का जवाब मत दो। जो पूछा है, उसका जवाब दीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, इनको जिसकी वकालत करनी है, करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कमिटमेंट गरीबों के प्रति है और हम गरीबों के लिए सस्ती दवाई उपलब्ध करवाते हैं। देश में दस लाख कार्डियक पेशंट्स होते हैं। हमने कार्डियक स्टैंट की प्राइस कम की और गरीबों की मदद की, उससे 4547 करोड़ रुपये देश की जनता को फायदा हुआ। हमारा कमिटमेंट है। हमने 1032 मेडिसिन की सीलिंग प्राइस फिक्स की, उससे देश की जनता को 2422 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। मोदी जी का गरीबों के प्रति कमिटमेंट है। इतना ही नहीं, गरीब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको नी-इम्प्लांट कराना था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता था और वह नी-इम्प्लांट नहीं करवाते थे। मोदी सरकार ने नी-इम्प्लांट का प्राइस कैप किया।...(व्यवधान) इससे 1500 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। दूसरा, हमने इनिशिएटिव लिया है कि देश में कैंसर की दवाइयाँ बहुत महँगी होती हैं और यहाँ जो बात हो रही थी कि जन औषधि स्टोर्स पर ज़्यादा रेट होता है।

(1110/CS/KKD)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कार्डियक पेशेंट को कौन सी दवाई लेनी पड़ती है। उसे लोसार्टन 25 एमजी की दवाई लेनी पड़ती है। मार्केट में उस दवाई का मूल्य 33 रुपये है, हमारे जन औषधि स्टोर पर वह दवाई 5 रुपये में मिलती है। कैंसर की दवाई, एंटी कैंसर दवाई डोसेटैक्सेल 80 एमजी मार्केट में 17 हजार रुपये में मिलती है और हमारे जन औषधि स्टोर पर यह दवाई 1,800 रुपये में मिलती है। यह गरीबों के प्रति हमारा कमिटमेंट है।

महोदय, मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से विनती करना चाहता हूँ कि वे अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पर इस जन औषधि स्टोर को खुलवायें, क्योंकि आज देश में मोदी जी की दुकान के नाम से यह मेडिसिन और यह जन औषधि स्टोर प्रसिद्ध हो रहा है। इससे जनता को जो लाभ होता है, मैं उसका एक उदाहरण यहाँ बताना चाहता हूँ। 1 जून, 2018 को मोदी जी ने बेनिफिशरीज के साथ बात की थी। उन लाभार्थियों में ओडिशा के मिस्टर सुभाष मोहंती एक लाभार्थी थे। वे मधुमेह और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। उन्होंने मोदी जी के साथ बात करते हुए कहा था कि मुझे हर महीने 3 हजार रुपये की मेडिसिन चाहिए होती थी, लेकिन मेरे क्षेत्र में जन औषधि स्टोर ओपन हुआ, तो मुझे यह मेडिसिन 400 रुपये में मिल रही है। यह सेवा भी है और रोजगार भी है। इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में सभी माननीय सांसद हर ब्लॉक पर जन औषधि स्टोर ओपन करें। उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को सस्ती दवाई भी मिलेगी। आप बीपीपीआई की वेबसाइट पर जाकर, उसका फॉर्म डाउनलोड करके, फॉर्म फुलफिल करके मेरे ऑफिस में मुझे पहुँचा दीजिए, मैं आपके ब्लॉक स्तर पर जन औषधि स्टोर ओपन कर दूँगा। उससे गरीबों को फायदा होगा, आपको यश मिलेगा और जनता का काम होगा। धन्यवाद।

(इति)

(Q. 222)

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Hon. Speaker, Sir, first of all I convey my thanks to Lord Venkateswara Swamy. It is my maiden Question. I also convey my thanks to hon. Speaker for allowing me this Question.

Sir, Tirupati Balaji is our God. I also convey my thanks to our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy and the people of Tirupati Parliamentary Constituency.

Coming to my Question, first of all, let me say the answer given by the hon. Minister is not satisfactory. If there is no complaint about the DRDAs, why have the Committee been formed twice, and their recommendations were also received? The cost implementing the recommendations to reform DRDA was estimated at about Rs. 12,000 crore. Then, the Government dropped this proposal of modification.

If there was no complaint, why was the Andhra Pradesh State Government as on 11.4.2019 indebted to take to the tune of Rs.27,000 crore?

Sir, you know pretty well that our Chief Minister and the new Government of Andhra Pradesh started functioning 40 days back. All of a sudden, we are not in a position to pay a huge amount. My request is that the Government of India, under the leadership of our beloved PM, Narendra Modi, should bear 50 per cent of the debt on behalf of State Government.

As you said, latest reforms, women empowerment and everything is there in the Budget. So, as a part of that, I would request you to clear it on our behalf.

Sir, secondly, there are lots of problem in our State.

माननीय अध्यक्ष : आप दूसरा सप्लीमेन्टरी पूछिएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, माननीय सदस्य ने डीआरडीए पर प्रश्न खड़ा किया है। यह संस्था बहुत पुरानी है। शुरूआती दौर में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उपशमन की दृष्टि से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, उनका संचालन किस प्रकार से हो, इसके लिए 1969 और 1980 में कुछ चुनिन्दा ब्लॉक्स में कुछ मैकेनिज्म खड़ा किया गया था।

(1115/RV/RP)

बाद में वर्ष 1980-81 में यह अस्तित्व में आया। जब डी.आर.डी.ए. अस्तित्व में आया, तब भी यह विषय था कि इसके खर्च की जो व्यवस्था है, वह कैसे होगी, तो जो परियोजना संचालित होगी और उस परियोजना के मद में जो पैसा होगा, उसी से इसकी प्रशासनिक लागत पूरी की जाएगी। आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम देखेंगे तो जिला पंचायतें 73वें संविधान संशोधन के बाद अस्तित्व में आ गईं। आज जिला पंचायतों का एक अच्छा ढाँचा बन गया है और जिला पंचायतें सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। इसलिए अनेक राज्यों ने डी.आर.डी.ए. का जिला पंचायतों में विलय कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की जो योजनाएं संचालित हैं, उनका अपना प्रशासनिक बजट है, उनके अपने कर्मचारी हैं, इसलिए अब डी.आर.डी.ए. की प्रासंगिकता सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देती और इसी कारण से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

SHRI BALLI DURGA PRASAD (TIRUPATI): Hon. Minister has explained everything about DRDA. We have formed the Government for the first time in the State. We want Rs. 27,000 crore for SHG women. I would like to know whether the Government is going to provide 50 per cent of the cost. You are talking about women empowerment schemes and other things. It is a part of the DRDA Scheme. This is my question.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन की या अन्य प्रकार की उत्थान की जो योजनाएं थीं, उनका संचालन ठीक प्रकार से किया जा सके, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके, उनका मार्गदर्शन किया जा सके, इसलिए डी.आर.डी.ए. की व्यवस्था थी। आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत सड़कें बन रही हैं तो उनका अपना ढाँचा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की दृष्टि से अगर एन.आर.एल.एम. चल रहा है तो उसका अपना ढाँचा है, जिला पंचायत के अपने कर्मचारी हैं। इसलिए आज जो स्थिति है, उसमें हम लोगों ने वर्ष 2016 में सुमित बोस कमेटी का गठन किया था और उन्हें ये सभी विषय दिए थे कि इसे कैसे ठीक करें। सुमित बोस साहब ने भी यह कहा है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, उसमें हर योजना में प्रशासनिक व्यय है, हर योजना के क्रियान्वयन के लिए ढाँचा है, इसलिए अब डी.आर.डी.ए. का कोई औचित्य बचता नहीं है।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डी.आर.डी.ए. का विलय करने के बारे में वर्ष 2016 में सुमित बोस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उसके बारे में आगे की योजना क्या है?

दूसरा, एमपीलैड के सारे कार्यक्रमों की देखभाल डी.आर.डी.ए. करता है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग डी.आर.डी.ए. को एमपीलैड से शुल्क अदा करते हैं और 'दिशा' का भी अनुपालन वही करता है। इसलिए उसकी ज्यादा रुचि योजनाएं बनाने में नहीं, बल्कि 'दिशा' की बैठकों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा खर्च करने में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे कोई ऐसी गाइडलाइन दें, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोगों को रिपोर्ट मिलने में एक-एक साल का समय लग जाता है। एम.पी.आर. सही समय से नहीं मिलता है, जिसके चलते हमारी निधि खर्च नहीं हो पाती है और अखबारों में और बाकी ज़गहों पर यह आता है कि सांसद ने खर्च नहीं किया जबकि खर्च करने का काम उनका है। इसलिए डी.आर.डी.ए. का विलय करने के स्थान पर कोई ऐसी योजना

हो कि भारत सरकार अपने अधीन कर ले और हम उन्हें शुल्क देते हैं, पैसे देते हैं तो वे हमारे कार्यक्रमों को सीधा-सीधा करें, अगर ऐसी कोई योजना है तो मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय डी.आर.डी.ए. के सम्बन्ध में है। अभी जहां डी.आर.डी.ए. अस्तित्व में है, उसके बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, वह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल में अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी निर्णय ले लिया है कि डी.आर.डी.ए. का जिला पंचायत में विलय कर देंगे।

(1120/MY/RCP)

आज सांसद निधि के खर्च का जो सवाल है, उसके लिए निश्चित रूप से जिला कलेक्टर जिम्मेवार हैं। वहां सभी प्रकार का ढांचा है। आज डीआरडीए में अगर कोई इंजीनियर अस्तित्व में है, वह हमारा एस्टिमेट नहीं बनाता है। वहां निर्माण का जो काम है, चाहे वह सड़कों की दृष्टि से हो, बिल्डिंग की दृष्टि से हो, उसका काम लोक निर्माण विभाग करता है। अगर सिंचाई की दृष्टि से कोई योजना है, तो इरिगेशन विभाग उसका काम करता है। अगर अन्य विभाग की कोई योजना है तो उसके लिए वहां विभागीय व्यवस्था है। मैं सांसद महोदय की चिंता से वाकिफ़ हूं। सांसदों को इस मामले में कोई तकलीफ़ नहीं आए, यह निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी माननीय सांसद श्री सुनील जी ने यह बात उठाई। आज भी कुछ राज्यों में चाहे एमपीलैड हो या विधायक निधि हो, इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन डीआरडीए ही करती है। 16वीं लोक सभा में माननीय सांसदों द्वारा दिए गए समय से पूर्व जो प्रस्थाव थे, उन प्रस्तावों की स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी सांख्यिकी विभाग से पैसा नहीं गया है, जबकि 17वीं लोक सभा आ गई है, लेकिन अभी तक 16वीं लोक सभा के उन सांसदों के एमपीलैड का पैसा नहीं पहुंचा। इस संबंध में अभी क्या कार्रवाई हो रही है?

दूसरी बात, डीआरडीए की अस्तित्व में आने की जो बात कही गई है, यू.सी. मामले के बावजूद भी राज्य सरकारों से प्रस्ताव या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय से नहीं आता है, जिसके कारण कार्य पूरा नहीं हो पाता है। जबकि एक एमपीलैड में कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद इतना सवालिया निशान लगता है। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई ऐसा मेकनिज़म तैयार करने की कोशिश करेंगे या डीआरडीए में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है? आज भी उन राज्यों में पूरे एमपीलैड के कार्यों का उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। ये दोनों बातें एक-दूसरे से कान्ट्राडिक्ट करती हैं। हम चाहते हैं कि एमपीलैड के लिए समय से उनकी योजनाएं, डीपीआर, क्रियान्वयन, यू.सी. और फिर दूसरी किस्त मिले, इसके लिए आप कौन-सा मेकनिज़म करेंगे? इस बारे में आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ने जानकारी चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सांसद निधि का सवाल है, सांसद निधि की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिल्ली आए और किस समय रिलीज हो, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं संबंधित मंत्रालय को अवगत कराऊंगा। लेकिन, जहां तक डीआरडीए का सवाल है, जहां अब डीआरडीए अस्तित्व में नहीं है, वहां भी काम ठीक प्रकार से चल रहा है। अभी भी केन्द्र सरकार डीआरडीए को संचालित करने के लिए आपकी राशि यहां से आबंटित कर रही है। अभी भी हम इसके मूल्यांकन की स्थिति में हैं, लेकिन ऐसी ध्वनि नहीं जानी चाहिए कि केन्द्र सरकार डीआरडीए बंद कर रही है। इसकी प्रासंगिकता कितनी बची है? क्योंकि, रामचन्द्रन समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उस पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च आ रहा था। इसको व्यय समिति ने एग्री नहीं किया, इसलिए ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं। अभी इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या लगभग 15,000 है। हम उनकी तनख्वाह के लिए पैसा दे रहे हैं। आज की जो परिस्थिति है, उसमें हमें प्रासंगिकता पर जरूर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आधा देश इसके विलय के पक्ष में है और कुछ लोग इसको संचालित करने के पक्ष में हैं।

(इति)

(Q. 223)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Sir, I thank you for giving me an opportunity and I thank the hon. Minister and congratulate her for giving a detailed answer.

Non-availability of skilled manpower for food processing is a big challenge. Industrial training institutions which are providing skill-based training and diploma courses are limited. There is a requirement of exclusive food technology for skilling the nation and for bridging the gap in the food processing sector. Has the Government taken any step in this regard?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, although the answer is about cold chains, I would still like to tell the hon. Member that under my Ministry there are two institutions. One is the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), the only one of its kind, which is in Kundli in Haryana; the other one is the Indian Institute of Food Processing Technology which is in Thanjavur in Tamil Nadu. Both these institutions are premier institutions where M. Tech, B. Tech. and Ph. D. courses are being run.

(1125/MMN/CP)

I am happy to say that all the students, who pass out, get 100 per cent placement because of the kind of quality education which is being given over there. Along with this, there is also an Incubation Centre where training is provided. In fact, all the students, who are studying in these institutions, have to go for a village adoption programme in which each of them adopts a village so that what they are learning in the lab is also be practised on the ground. So,

they get to know what the ground realities are. So, along with the Incubation Centres of which there is one in Bathinda and there is one in Assam, for skill development, there is a special package also under the Ministry of Skill Development where all kinds of courses are being run in the various sectors of food processing technology.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): I would like to ask a question to the hon. Minister. The Mega Food Park Scheme requires a minimum of 50 acres of land and it does not promote smaller or individual food processing and preservation unit. The Committee on Doubling of Farmers' Income, in its Report in August, 2017, recommended establishment of processing and value addition units at strategic levels. What steps have been taken by the Government to implement the recommendation of the Committee to expand the cold chain infrastructure?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, the hon. Member is correct that when our Government inherited this Ministry, there were only two schemes. One was the Mega Food Park Scheme which required 50 acres of land and another was the Cold Chain Scheme. But after seeing that acquiring 50 acres of land was a big problem, over the last five years, 7-8 schemes under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana have been brought. Sampada is to supplement agriculture, modernise food processing and decrease agri-wastes. I can happily tell this House that anybody, who has any kind of food cluster in his constituency, and wants to preserve or give value addition, under the Sampada scheme, from the smallest farmer to a Self-Help Group, from a

farmer producer organisation to an entrepreneur, from a big industrialist to anybody, all of them can take advantage of this scheme. There are 5-7 schemes under this. Under the Mega Food Park Scheme, 50 acres of land is required for big people. Under the Mini Food Park Scheme or for the agro-processing cluster, only 10 acres of land is required. Also, we give a grant to people who want to set up units inside these food parks. That is how, the unit schemes are there. As the hon. Member was saying there was nothing to encourage the units but we give a grant to people to put up units.

There is also a backward and forward linkage scheme where if a farmer wants to now start an agro-processing business, he can take a grant to link up. If a retailer now wants to start manufacturing and link it up with the farmer, he can also take a subsidy and work towards it. If there is a processor, who now wants to start growing and start selling, he can also do so. So, in the entire value chain, there is some scheme which is available for anybody who wants to promote food processing. They are all on the website, and I would be happy to assist you.

I would also like to tell this House that I think on Friday, from one o' clock to two o' clock, here in the Parliament House Annexe, my Ministry is holding a special session for the Parliamentarians regarding World Food India, 2019. In that, all the schemes are also going to be discussed. So, if there is any Member, who is interested in value-adding to something which is being grown or which is getting wasted, he is most welcome to attend and most welcome to ask questions.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, in my Nandurbar constituency in Maharashtra, which is predominantly a tribal area, the people are engaged in farming activity. Most of the crops that they grow there are onion, chilli, banana, papaya and custard apples. These are perishable items and due to lack of cold storage facility, the farmers are compelled to sell their produce at a very low price. Since setting up of cold storage involves a huge investment, I would like to know from the hon. Minister, through you, whether the Government will provide financial aid for setting up a cold storage facility in my Nandurbar constituency.

Also, I would like to ask another question.

माननीय अध्यक्ष : एक प्रश्न ही पूछिए।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I would like to assure the Member that we would be happy to assist in any way. As I mentioned in my answer setting up stand-alone cold storages is not part of the mandate of my Ministry; that is done by the Agriculture Ministry.

(1130/NK/VR)

In my Ministry, we assist in setting up of cold-chain units. The aim of my Ministry is to create a cold chain grid throughout the country for seamless transfer of food from production to consumption, which means that there should be some farm-level infrastructure – a storage, a minimal processing unit, washing, cleaning, grading at the farm gate level and reefer vehicles to transport it. Even one can do some processing there. So, a grant is given for all these things. If anybody wants to apply, we would be happy to assist.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य सदन में पहली बार सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं।

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Thank you, hon. Speaker, Sir. Through you, I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to build a small-scale cold storage plant in Thalaivasal farmers' market which comes under my Kallakurichi constituency. It is the second largest farmers' market in Tamil Nadu. Around 2000 small farmers sell their produce here and the daily turnover is around Rs.40 lakh. If there is no such proposal, I request the hon. Minister to consider this proposal.

I also request the hon. Minister to build a cold storage plant with a capacity of 25 tonnes storage for the benefit of farmers in my constituency.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: I thank the hon. Member that he has asked me his first question.

I would be happy to help him. As I said earlier, my Ministry does not build only cold storages but we build an entire chain. There is something for everybody. If you have got these farmers' organisations over there or as you said, you have a *mandi* in your constituency which sells many things, I would like to say that anybody is welcome to apply for these storage and processing facilities. The Ministry itself does not set up a unit. But when people apply for these facilities, we give them subsidies. If they are small farmers, we assist by handholding them in every way, make them into farmer-producer organisations, help them keep their books, make their DPR, and so on. We assist them in every way because the aim of the Ministry is to encourage food processing so that food can be saved, it does not go waste, farmers get better

income, and inflation is under control, which is also better for the consumers as well.

माननीय अध्यक्ष: श्री रवनीत सिंह जी। माननीय सदस्य आप लंबा क्वेश्चन पूछते हैं, संक्षेप में क्वेश्चन पूछें। आप किसान हैं।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पंजाब से हैं। आपने मौका दिया है इनसे कोई न कोई फायदा ले लें, मेरे ख्याल से वह नाराज भी नहीं होंगे, कई बार नाराज हो जाती हैं। चूंकि ये लुधियाना विजिट करती रही हैं। लाडोवाल में एक मेगा फूड पार्क है। यह फूडपार्क सौ एकड़ में बना हुआ है। तकरीबन 47 एकड़ लैंड कॉमन फैसिलिटी के लिए है। 53 एकड़ लैंड पर अलग-अलग कंपनियों को अपनी फैक्ट्री लगानी थी। वहां फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कई इश्यूज थे लेकिन now they have been sorted out. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां बड़ी कंपनी आ सकें, आज वहां केवल दो ही बड़ी कंपनियां गोदरेज और बालाजी फूड हैं। पंजाब को फायदा हो जाएगा, मेन किसानों की बात है, डाइवरसिफिकेशन की बात है। मंत्री जी का हम लाभ उठाएं, इससे पंजाब को फायदा होगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, मैं माननीय मेंबर का शुक्राना करती हूं और विश्वास दिलाती हूं कि इनसे मेरी नाराजगी नहीं है लेकिन इनकी सरकार से जरूर नाराजगी है।

माननीय अध्यक्ष: आप सरकार से नाराज मत हों, आप केन्द्र में मंत्री हैं।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, मेरी नाराजगी इसलिए है क्योंकि पंजाब के किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कि जरूरत है। जब मैं पूरी मेहतनत करके प्रोजेक्ट्स लगाती हूं और सरकार उस प्रोजेक्ट को साल-साल भर आगे बढ़ाती नहीं, कोई मदद नहीं करती तो अंडरस्टैंडेबली नाराजगी होती है। मैंने लगातार इनके मुख्य मंत्री को छह चिटिठयां लिखी हैं कि लाडोवाल मेगा फूड पार्क जिसका इन्होंने जिक्र किया है।

माननीय अध्यक्ष: इनके मुख्य मंत्री नहीं, पंजाब के मुख्य मंत्री कहिए। आपकी नाराजगी डेवलपमेंट करने के लिए है।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, मैं इनसे मदद मांगूंगी क्योंकि इनके ही कंस्टीट्यूएंसी में लाडोवाल मेगा फूड पार्क को पिछले साल कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, ईंधन आने के बाद मैंने फूड पार्क को सैंक्शन किया, उसे पूरा सपोर्ट दिया। ...(व्यवधान) आपको हैरानी होगी कि फूड पार्क के लिए आईक्यूएफ की मशीन ही नहीं लगी है और टेंडर भी नहीं किया गया है।

(1135/SK/SAN)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यहां पंजाब सरकार की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इस तरह की कोई बात उठाना सही नहीं है।...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: यहां तक कि वहां जो ट्रांसफर्मर लगना है, ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा।...(व्यवधान) यह अकेला फूड पार्क है जहां युनिट लग चुकी है और फूड पार्क का इनऑगरेशन नहीं हुआ। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य द्वारा मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी ही सरकार से हमारी मदद करवाएं ताकि जल्द से जल्द फूड पार्क इनऑग्रेट हो, इससे लाखों किसानों को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा।...(व्यवधान)

महोदय, मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हमारे मंत्रालय की तरफ से पंजाब में 42 प्रोजेक्ट्स 1200 करोड़ रुपये के लगाये गए हैं। अगर पंजाब के सांसद और लगवाएंगे, मैं खुशी से और देने के लिए यहां खड़ी हूं, मैं उनकी पूरी मदद करूंगी।...(व्यवधान)

(इति)

(Q. 224)

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Sir, I have gone through the detailed reply given by the hon. Minister. It is really exhaustive and I thank the hon. Minister for this detailed reply. In this regard, I would like to put a question about insurance.

Though 'Agriculture' is in the State List and not in the Concurrent List, the hon. Prime Minister, through Prime Minister Fasal Bima Yojana, has come up with an insurance scheme where 50 per cent premium would be paid. In Andhra Pradesh, there were initiatives wherein the balance 50 per cent is being paid by the State, in addition to what is paid by the Centre. The Ayushman Bharat has been showered by the hon. Prime Minister on the kisans, who are the backbone. Is there any proposal to pay the full insurance premium to the farmer under something like Ayushman Kisan? It would be a good thing. Is there any proposal in this regard?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सवाल उठाया है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के रिस्क मैनेजमेंट करने के उम्दा आशय के साथ वर्ष 2016 में प्रस्तुत की थी। यह योजना वर्ष 1985 से चल रही है। इस योजना में कई परिवर्तन हो गए हैं, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों के रिस्क मैनेजमेंट के लिए उपयोग में ले रहे हैं। कल ही करीब 12 राज्यों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और 20 से ज्यादा राज्यों के वरिष्ठ एग्रीकल्चर अफसरों के साथ बैठक थी। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तोमर जी ने की थी। इसमें इस विषय को लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और अधिकारियों से राय ली गई है। आपका उद्देश्य है कि पूरा प्रीमियम केंद्र सरकार की ओर से सजैस्ट किया जाए। ऐसे कई सुझाव, एग्रीकल्चर कन्सर्न्स स्टेट के मिनिस्टर्स, कई

माननीय सांसदों और पिछले दौर में मोहन भाई कुंदरिया जी ने भी दिए थे। इन सारी चीजों को लेकर हमारा मशविरा चल रहा है। इसमें अभी यह तय नहीं है कि 100 परसेंट केंद्र सरकार स्वीकृत करेगी, लेकिन इसे मॉडिफाई करने की एक प्रक्रिया चर्चा में जरूर है।

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Thank you so much, Mantriji.

Recently, the Government has increased the Minimum Support Price for 16 crops, which is a very welcome step. In this regard, M.S. Swaminathan Committee has given some recommendations, according to which in the formula adopted, the labour input by the family of the farmer has also to be taken into consideration, which would further improve the Minimum Support Price as a remunerative price. This is a very good suggestion extended by Swaminathan Committee. Is the Government considering, in the interest of the farmer, the recommendation made by Dr. M.S. Swaminathan?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किसानों की फैमिली के श्रम का मूल्य इसकी लागत के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान में लागत इवैल्युएट करने का जो सिस्टम है, उसमें पूरे किसान परिवार का श्रम मूल्य शामिल कर दिया गया है। यह सुझाव स्वीकृत कर लिया गया है।

(1140/MK/RBN)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य से मैं आती हूं, उस राज्य का जो सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि रोज आठ किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है, I would like to quote the Government document. It is from the Government of Maharshtra's Economic Survey. You can verify it. In the reply it has been said – I know it is a State subject – "The

Government has reoriented the agricultural sector by focussing on the income-centric approach against the earlier production-centric approach. This focusses on achieving high productivity, reduced cost of cultivation."

My pointed question is this. With the petrol and diesel prices going up and nothing specific being there for this sector in the Budget, how are you going to reduce the cost of cultivation, increase the income of farmers and reduce farmers' suicides not just in Maharashtra though my State is highly drought affected?

Even if it is a State subject, which I am aware, what specific intervention is this Government doing? In the UPA regime, under the leadership of hon. Manmohan Singh ji, Rs. 70,000 crore loan waiver was given. Do you intend to do something similar like this in the interest of my State of Maharashtra?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय सदस्या ने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और उन्होंने चाहा है कि लागत को कम करने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा कौन-से स्टेप उठाए जा रहे हैं? उन्होंने यह भी जिक्र किया कि डेब्ट वेवर का एक बड़ा काम उनकी सरकार के द्वारा डॉ.मनमोहन सिंह जी की रिज़ीम में किया गया था। हम सबको यह पता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मगर हम आपके संज्ञान में इस सवाल के जवाब के संदर्भ में यह जरूर लाना चाहते हैं कि हम पूरे देश के किसानों को जिन्होंने ब्याज लिया है, उनको ब्याज मुक्त करना है ऐसा नहीं है। मगर, प्रत्येक किसान को हर साल 6000 रुपये इनके एकाउंट में डालने का प्रयोग कर रहे हैं और 11000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किसानों को मिलने वाले हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हुई कि पहले कुछ राज्य इसके लिए संकोच करते थे, लेकिन कल ही सारे राज्यों के एग्रीकल्चरल मिनिस्टरों ने इसके लिए अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और उनके द्वारा डेटा भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

अब उनकी दूसरी मूल बात कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए इस सरकार द्वारा क्या किया गया? हमारे विजनरी प्रधान मंत्री जी ने जब डबल फार्मिंग की बात रखी थी, उसका मूल आधार था- Scheme for cost reduction, scheme for risk mitigation, scheme for productivity, and scheme for right prices. इसकी लागत कम हो, उसके रिस्क का मैनेजमेंट हो, उसको सही दाम मिले, इसी संदर्भ में हमने सॉयल हेल्थ कार्ड के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम पूरे देश में इन्वाल्व किया है। इसके उपयोग से किसान अपने खेत में जितना आवश्यक है उतने फर्टिलाइजर का उपयोग करे, जितनी मात्रा में करना चाहिए, उतना ही करे। हमारी सरकार ने उसी फर्टिलाइजर को 100 परसेंट नीम कोटेड करके यूज करने का प्रावधान किया है। पहले के समय में यूरिया लेने के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती थीं, आज पूरे देश में कहीं से भी यूरिया की डिमांड के लिए कोई कम्प्लेन नहीं आ रही है। सभी को समय से यूरिया मिल रहा है। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से उसकी मात्रा भी यूज में कम लगती है और नीम कोटिंग से किसान खेत में ज्यादा समय तक फर्टिलिटी भी बनाए रखता है।

दूसरा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के तौर पर 'पर क्राप मोर ड्राप' वाला जो हमारे प्रधान मंत्री जी का विजन है, उसके चलते हम किसानों को माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देते हैं। Mission for Organic and Value Chain Development for North-Eastern States.खासकर, नार्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, वहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने से भी एग्रीकल्चर की कॉस्ट कम होती है। हर पेड़ के साथ मेढ़ लगाने की एक योजना सरकार की ओर से लागू की गई है।

(1145/YSH/SM)

हम परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इन सारी योजनाओं को किसान अपने खेत में लागू करे तो अवश्य ही इनकी लागत में कटौती होगी।

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि लगभग 75 हजार करोड़ की जो कर्जा माफी की घोषणा की गई थी, उसमें कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है? उसमें क्या-क्या विसंगतियां ऑडिट रिपोर्ट में आई थी? जिस वर्ष कर्जा माफ हुआ, क्या उसके अगले वर्ष आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई थी या कमी आई थी यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे यह कर्जा माफी वाले इश्यू से रिलेटेड नहीं है, मगर राधा मोहन सिंह जी मेरे सीनियर मिनिस्टर भी रहे थे और मैं इनके संरक्षण में हाउस में जवाब दिया करता था। उनकी यह बात सही है कि कर्जा माफी करने के बाद के वर्षों में भी आत्महत्याओं की घटनाओं में बढोतरी हुई थी। यह रिकॉर्ड पर था। मैं मानता हूं कि किसानों की आत्महत्याओं को राजनीतिक रंग से देखने की जरूरत नहीं है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप चौधरी जी का जवाब न दें। आप सिर्फ राधा मोहन जी का जवाब दें। मैंने आपको एलाउ नहीं किया।

...(व्यवधान)

श्री परषोत्तम रूपाला : सर, उसमें एक यह भी जिक्र किया था कि जो ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में ऐसे मामले भी सामने आए थे कि उन लोगों का भी कर्जा माफ हो गया था, जो किसान ही नहीं थे।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, सदन और देश के किसानों को आपका संरक्षण चाहिए। पांच पेज का उत्तर है, पांच पेज के उत्तर में जो प्रश्न है,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। आप सदन में पहली बार तो आए हैं, लेकिन प्रश्न काल में ऐसे खड़े नहीं होते हैं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, पांच पेज के इस उत्तर में जो प्रश्न है वह किसान आत्महत्या के ऊपर है। इस पर पांच पेज में एक भी आंकड़ा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो प्रश्न पूछिए।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष जी, प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि देश में किसानों की कितनी आत्महत्याएं हुई है, उसके बारे में उत्तर में लिखा ही नहीं है। हम इसलिए जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न किसान आत्महत्या नियंत्रण का है, तो सदन को कैसे पता चलेगा कि नियंत्रण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंत्री जी छिपा रहे है कि देश में कितनी आत्महत्याएं हो रही है। अभी-अभी उन्होंने खुद कहा है कि पिछली यू.पी.ए. सरकार के बाद वहां जो लोन वेवर हुआ, उसके बाद किसानों की आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी हैं, तो उसका यहां पर विस्तार क्यों नहीं है? आज यहां की केन्द्र सरकार पांच पेज के उत्तर में देश के किसान की आत्महत्याओं को नजरअंदाज कर रही है, उसका डेटा नहीं रख रही है। पी.एम. ने किसानों को कितना दिया इसका तो रिकॉर्ड है, लेकिन कितने किसानों की आत्महत्या हुई उसका रिकॉर्ड नहीं है।

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब हमने दिया है, उसमें ही लिखा हुआ है और आत्महत्या के बारे में सारे डेटा इसमें लिखे हुए भी है। वर्ष 2015 के बाद ये डेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट और होम डिपार्टमेन्ट की ओर से प्रकाशित होता है। क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो से जो प्रकाशन होता है उसके आधार पर हम कृषि विभाग के जरिये यहां रखते हैं। वर्ष 2015 के बाद में राज्यों के साथ उनका कंसिलियेशन चल रहा है तो इसके चलते राज्यों से यह डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। वे प्रकाशित नहीं हुए है। वर्ष 2015 के डेटा के आधार पर आत्महत्या में वृद्धि के बारे में बताया था।

(इति)

(प्रश्न 225)

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी विभाग भारतीय खाद्य निगम द्वारा 563 डिपो गोदाम संचालित होते हैं और केन्द्रीय भण्डार निगम द्वारा 421 भण्डार प्रचलन में हैं। कुल 984 भण्डार देश में प्रचलन में हैं। मैं बहुत प्रसन्नता से कहना चाह रहा हूं कि आपने इन भण्डारों की सारी प्रणाली को ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

(1150/RPS/AK)

इससे निश्चित ही लीकेज रोकने में बड़ी सफलता मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन मॉनीटरिंग में लीकेज तो रुकेगी, मगर डिपो में रखा हुआ खाद्यान्न अगर गुणवत्ता खो चुका हो तो उसकी गुणवत्ता बचाने के लिए देश में क्या प्रयास हो रहा है? जो खाद्यान्न गुणवत्ता खो चुका है, कितने प्रतिशत खाद्यान्न प्रतिवर्ष खराब होकर मानव उपयोग योग्य नहीं रहता है और इस खराब खाद्यान्न का क्या उपयोग होता है?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, यह बात सही है कि 1 जून, 2019 के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 563 गोदाम हैं, जिनमें से 532 गोदाम प्रचलन में हैं और 31 गोदाम प्रचलन में नहीं हैं। सीडब्ल्यूसी के 185 गोदाम हमारे पास हैं, जिनमें से 144 प्रचलन में हैं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि उसका रखरखाव कैसे होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास गोडाउन में जो अनाज होता है, उसका रखरखाव करने के लिए सरकार पूरा बन्दोबस्त करती है। आज हमारे 3 लाख 40 हजार मीट्रिक टन का स्टॉक है और हमारी क्षमता 4 लाख 81 हजार मीट्रिक टन है। आज की तारीख में उसमें से कोई भी खाद्यान्न खराब नहीं है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, उसमें हम लोगों ने पांच उपाय किए हैं। एक, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दूसरा, हम लोग डिपो का औचक निरीक्षण करवाते हैं। तीसरा,

वहां सुरक्षा स्टाफ की तैनाती होती है, गोदाम परिसर में हाई-मास्ट लाइट्स लगाई गई हैं और कांटेदार चारदीवारी लगाई गई है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब जो अनाज वगैरह उसमें से निकाला जाता है, सिर्फ उतना ही डैमेज हो रहा है, जिसकी परसेंटेज 0.1 या 0.2 है। इसलिए वह नगण्य हो गया है। पहले जो इस तरह की सूचनाएं आती थीं, अब वे सूचनाएं आनी भी बन्द हो गई हैं।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। विशेष रूप से मैं माननीय मोदी जी के साथ-साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने देश में 'वन नेशन, वन राशनकार्ड' जैसी अभिनव प्रणाली देश को दी है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां औद्योगीकरण नहीं पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्र के किसानों एवं व्यापारियों ने वेयरहाउसेज का निर्माण करने में रुचि ली है। क्या मंत्रालय इन वेयरहाउसेज को किराये पर लेकर, क्षेत्र के वेयरहाउसेज को संरक्षण प्रदान करने की किसी योजना पर विचार करेगा?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, अपने पास जो क्षमता है, वह 4 लाख 81 हजार मीट्रिक टन की क्षमता है और अभी हमारे पास स्टॉक 3 लाख 40 हजार मीट्रिक टन है। कुल मिलाकर देश भर में जितने अनाज की खरीद होती है, उस क्षमता के अनुसार हमारे पास पूरे गोडाउन्स हैं। सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, पीईजी और एफसीआई को मिलाकर जितनी क्षमता होती है, हमारे पास उतने गोडाउन्स हैं। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो इसके लिए कोशिश की जाएगी।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष जी, एफसीआई के बोरिवली और पनवेल डिपो के कारोबार के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, फरवरी, 2017 में बोरिवली डिपो से 275 मजदूरों का स्थानांतरण पनवेल डिपो में करके बोरिवली डिपो में ठेकेदार प्रथा की शुरुआत की गई। इस बारे में मंत्री जी के साथ बैठक करके, निवेदन देकर मैं यह बात उनके ध्यान में लाया था, लेकिन एफसीआई अधिकारी कांट्रैक्ट

करने में मशगूल थे, कैसे मुझे कांट्रैक्ट मिलेगा और उसमें मेरा हिस्सा कैसे मिलेगा, इसमें ज्यादा मशगूल थे, लेकिन माने नहीं। मंत्री जी समझते थे, लेकिन अधिकारियों पर रोक नहीं लगा पाए। वर्तमान समय में पनवेल डिपो की क्षमता 96 हजार मीट्रिक टन है और उसकी आउटपुट कैपेसिटी 18 से 20 मीट्रिक टन प्रति महीना है। वहां इन मजदूरों का स्थानांतरण होने के बाद, अब मजदूरों की कुल संख्या 600 हो गई है। इस समय पनवेल डिपो में 100 से 150 मजदूर बिना काम किए वेतन प्राप्त करते हैं। जहां काम है, वहां से उनको उधर भेजा गया है। वहां उनके लिए काम नहीं है और एफसीआई द्वारा उनको वेतन दिया जाता है, क्योंकि वहां उनको कांट्रैक्ट चाहिए। बोरिवली डिपो की क्षमता 2 लाख 50 हजार मीट्रिक टन है और आउटपुट 50 से 60 मीट्रिक टन प्रति महीना है। वहां कांट्रैक्ट मजदूर समय पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एक बड़ी धनराशि बोरिवली के खाद्य निगम अधिकारियों को ओवरटाइम के रूप में, रेलवे को डैमरेज चार्जेज के रूप में और पनवेल में मजदूरों को बिना काम के वेतन देने के लिए खर्च होती है। अत: मैं माननीय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बोरिवली डिपो से पनवेल डिपो में स्थानांतरित किए गए मजदूरों को वापस बोरिवली डिपो में स्थानांतरित करने पर विचार करेगी? यह इसलिए भी करना चाहिए कि अधिकारियों का जो कांट्रैक्ट व्यवस्था में इंट्रेस्ट है, वह कांट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। आउटसोर्सिंग से ये अधिकारी पैसा लेते हैं। इस तरह से एफसीआई को जो नुकसान किया जाता है, क्या उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे और पनवेल स्थानांतरित किए गए मजदूरों को क्या आप वापस बोरिवली लाएंगे? यही मेरा मंत्री जी से सवाल है।

(1155/RPS/SPR)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय सदस्य को अलग से प्रश्न पूछना चाहिए था। फिर भी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, अगर यह उनकी जानकारी है और इस बारे में हमें चिट्ठी लिखते हैं तो मैं उनको सभी जानकारी दे दूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बैठ जाइए, आपने बहुत लम्बा प्रश्न पूछ लिया है।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री श्री रामविलास पासवान और श्री दानवे रावसाहेब दादाराव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इस विभाग का मंत्री होने के नाते बहुत अच्छा सहयोग मिला। जब चोरी का सवाल पैदा होता है, आपने बहुत सारे प्रबन्ध किए हैं, जैसे दीवार बांधना, सीसीटीवी कैमरे लगाना आदि सब किया गया है। वहां जीपीएस सिस्टम भी लगाना चाहिए, क्योंकि चोरी अंदर नहीं होती है, चोरी गोडाउन से ट्रक बाहर जाने के बाद होती है। अगर आपने जीपीएस सिस्टम को एडॉप्ट किया तो बहुत सारी ऑनलाइन इन्फार्मेशन स्टेट को मिलती है, कलेक्टर को भी मिलती है और ठेकेदारों की पेमेंट जीपीएस क्लियरेंस होने के बाद ही करने का प्रबंध हो तो चोरी और भी कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पर ध्यान और इसे बंधनकारी करे तो इसमें चोरी कम होने की संभावना अधिक है।

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किया है, वह बिल्कुल सही है। जहां तक डिपो ऑनलाइन करने की बात है, आप देखेंगे कि जो गोडाउन सीडब्ल्यूसी और एफसीआई के हैं, वे 100 प्रतिशत ऑनलाइन हो गए हैं। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास कुल 2018 डिपो हैं, बाकी डिपो राज्य सरकार के हैं। राज्य सरकारों में भी सात राज्य ऐसे हैं, जिनके डिपो ऑनलाइन चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों का ऐसा समन्वय हो कि हम अपने ऑफिस से बैठकर देख सकें, कहीं से भी कोई भी देख सके कि अनाज कहां से जा रहा है, ट्रक कहां से जा रहा है और कैसे जा रहा है, इसका पता लगाया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने छ: महीने का समय दिया है। जनवरी के पहले सप्ताह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक जीपीएस सिस्टम का सवाल है, रेल से भी सामान आते हैं, ट्रक से भी सामान आते हैं। हमने कहा है कि एक महीने के अंदर और मैक्सिमम तीन महीने के अंदर, चाहे रेलवे हो या ट्रक हो, जीपीएस सिस्टम लागू करें, जिससे बिल्कुल पारदर्शिता रहे।

(इति)

(प्रश्न 226)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद है। बिहार की स्वीकृत 17,734 सड़क परियोजनाओं में से 15,860 सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सुपौल में भी 224 सड़कों में से 167 सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, गत 14 वर्षों में बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास हुआ है।

(1200/RAJ/UB)

गली, नाली और गांव से मुख्य सड़क पर मिलाने वाली सड़कों का भी काफी विस्तारीकरण हुआ है। महोदय, सुपौल कोसी क्षेत्र है। उस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती है, जिसके फलस्वरूप काफी सड़कें टूट गई हैं और सड़कें बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के अंतर्गत सड़कें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए सर्वे करने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 'प्रधानमंत्री सड़क योजना' के अंतर्गत सुपौल जिला में कितनी सड़कों की स्वीकृति के लिए सर्वे तथा डीपीआर हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो वह कब तक होगा? इसके बारे में आश्वासन देने की कृपा करें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने कैबिनेट मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे आज उत्तर देने का अवसर दिया है। माननीय सांसद जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 'प्रधानमंत्री सड़क योजना' के अंतर्गत बिहार में जो सड़कें वहां से प्रस्तावित होकर आई थीं -17,734, उनमें से 15,808 पूरी हो चुकी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहती हूं। मैं गांव से आती हूं। मेरे समय में वहां कोई सड़क नहीं थी, लेकिन जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए तो उन्होंने 'प्रधानमंत्री सड़क योजना' चला कर गांवों को जोड़ने का काम किया। इसलिए मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए, आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे उत्तर देने का अवसर दिया। (इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। **श्री जी. किशन रेड्डी** ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, on behalf of Shri Amit Shah, I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Volume I) for the year 2019-2020.
2. Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Union Territories) (Volume II) for the year 2019-2020.

*****

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

******

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 394 of the Companies Act, 2013:-
   (i) Review by the Government of the working of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year

2017-18.

(ii) Annual Report of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2017-18, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

3. A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ahmedabad, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

4. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

5. A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

6. Statement (Hindi and English versions showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

7. A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2019-2020.

8. A copy of Notification No. G.S.R.1705(E) (Hindi and English versions)

published in Gazette of India dated 8th May, 2019 order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Kharif, 2019 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

*****

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(दो) भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

*****

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

*****

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (कठिनाई को दूर करना) आदेश, 2019, जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1557(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2019, जो 29 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2017-18, alongwith Audited Accounts.

   (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2017-18.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

3. A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 23 of the Enemy Property Act, 1968:-

   (i) The Guidelines for disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2019 published in Notification No. G.S.R.201(E) in Gazette of India dated 8th March, 2019.

   (ii) The Procedure and mechanism for Sale of Enemy Share Order, 2019 published in Notification No. G.S.R.885(E) in Gazette of India dated 18th February, 2019.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2019, जो 21 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 13 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1728(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 24 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1817(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2019, जो 12 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1954(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बोरिक अम्ल के लिए मानक) आदेश, 2019, जो 17 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1766(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1767(अ) जो 17 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में 25 कीटनाशकों को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजीव बालियान): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धरा 66 की उप-धारा(3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता दिए जाने और उनकी मान्यता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2019 जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 197(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

*****

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड कम्युनिकेशन सर्विस (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 74 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) असम राइफल्स नायब सूबेदार (इलैक्ट्रीशियन मोटर यान) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असम राइफल्स (समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.36 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) असम राइफल्स नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) असम राइफल्स सिविल स्टाफ समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) असम राइफल्स (पैरा मेडिकल संवर्ग) समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी, कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 273 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) असम राइफल्स सूबेदार मेजर स्टोर कीपर टेक्निकल (इंजीनियर्स), समूह 'ख' पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) असम राइफल्स नायब सूबेदार (धार्मिक अध्यापक) कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 15 सितम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) असम राइफल्स नायब सूबेदार (अध्यापक) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) असम राइफल्स वारंट आफिसर (रेडियो मैकेनिक) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 18 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) असम राइफल्स सूबेदार मेजर (भवन और सड़क) (इंजीनियर्स) समूह 'ख' पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) असम राइफल्स पैरा-मेडिकल स्टाफ (फार्मासिस्ट) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37 में प्रकाशित हुए थे।

(3) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2018 जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 11 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, (कम्बैटाइज्ड स्टेनोग्राफर्स काडर), समूह 'क' और समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 18 मई, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 118 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) तथा हेड कांस्टेबल (मंत्रालयी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, पैरा वेटरिनरी स्टाफ, समूह 'ख' और समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित) पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती नियम, 2019, जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 147(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(1205/KMR/IND)

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1205 बजे

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th July, 2019 agreed without any amendment to the Dentists (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd July, 2019."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th July, 2019 agreed without any amendment to the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th July, 2019."

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया।

1206 बजे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'चक्रवात ओक्खी-मछुआरों पर इसका प्रभाव और इससे हुई क्षति' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 216वें प्रतिवेदन के अध्याय-तीन और चार में श्रेणीबद्ध पैरा के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कल शून्य काल में आपको बोलने के लिए अलाऊ किया था।

श्री हरीश द्विवेदी।

…(व्यवधान)

विशेष उल्लेख

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती (उत्तर प्रदेश) के जिला मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित संत रविदास वन बिहार पार्क, जो वर्ष 1988 में स्थापित हुआ था, की ओर दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान) स्थापना काल से ही यह पार्क बस्ती सहित इसके आस-पास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। पूर्व में यहां आकर्षक बाल उद्यान, झीलें, फव्वारा, झूला, नौकायान आदि की व्यवस्था थी।...(व्यवधान) साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों व कुवानो नदी के घाट पर बसे होने के कारण यहां आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण प्राप्त होता था। किंतु महोदय, पिछले कुछ वर्षों से यह पार्क अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पूरा पार्क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ चुका है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस पार्क की महत्ता को देखते हुए इसे आधुनिक रूप में विकसित करके इसके पुराने स्वरूप में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, आप बैठ जाएं। आप यदि शून्य काल में किसी विषय पर बोलना चाहते हैं, तो मुझे लिख कर दे दीजिए। मैंने आपको हमेशा बोलने के लिए अलाऊ किया है। मैंने कल भी आपको पूर्ण रूप से बोलने के लिए अलाऊ किया था। सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया था। आपको यदि कोई सवाल शून्य काल में उठाना है, तो आप विषय लिखकर दें। मैंने आउट ऑफ टर्न भी आपको मौका दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैंने लिखकर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आपने शून्य काल में बोलने के लिए लिखकर नहीं दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हमने एडजार्नमेंट मोशन दिया है।

माननीय अध्यक्ष : एडजार्नमेंट मोशन मैंने डिसअलाऊ कर दिया है। आप शून्य काल में दोबारा लिखकर दीजिए। मैं विचार करूंगा।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, जीरो ऑवर में दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता, यह रूल है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने जवाब दे दिया है।

श्री विजय कुमार दूबे।

…(व्यवधान)

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के किसान गन्ने की खेती पर आश्रित हैं। मैंने पूर्व में सदन में एक मुद्दा उठाया था कि बढ़ती पैदावार और घटती हुई चीनी मिलों के कारण गन्ना किसान घोर संकट में हैं।…(व्यवधान) गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों के अलावा उनकी खेती का मुख्य स्रोत सिंचाई है। सिंचाई की व्यवस्था में उन्हें मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की सुविधा मिली है।…(व्यवधान) मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की सिंचाई का स्रोत मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के दोनों बैंक जगह-जगह से टूटे हुए हैं और रजबहा हेड से टेल तक इतने माइनर हैं, जिनमें हैड से टेल तक पानी नहीं पहुंचता है।…(व्यवधान) इनके अलावा गन्ना किसानों को गन्ना पर्ची की समस्या भी आती है, क्योंकि निरंकुश अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था के चलते पर्ची का संकट भी गन्ना किसानों के सामने है।…(व्यवधान)

(1210/VB/SNT)

हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने, गन्ना टिकट आबंटन का जिम्मा मिल वालों के पास जब तक था, तब तक गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों का शोषण करने का

क्रम चलता रहा।...(व्यवधान) इस क्रम को बंद करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज ने कमान संभालते ही गन्ना किसानों की सुविधा के लिए गन्ना टिकट आबंटन का जिम्मा मिल वालों से हटाकर सोसायटी के जिम्मे कर दिया।...(व्यवधान) इसके कारण, गन्ना माफियाओं द्वारा जो गन्ना किसानों का आर्थिक शोषण किया जाता था, उस पर पूर्ण विराम लग गया।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि गन्ना मूल्य भुगतान समय से चल रहा है, लेकिन हमारे कुशीनगर जनपद के कुछ गन्ना किसान विशेष संकट में हैं।...(व्यवधान) लक्ष्मीगंज और छिटौनी मिलें, जो आज बंद हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं है। इनको पुन: चालू करने और कुशीनगर जनपद में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विजय कुमार दुबे द्वारा उठाए गए विषय से संबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ...(व्यवधान)

आज देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ चुनकर आए हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र भीड़तंत्र के माध्यम से खत्म हो जाएगा, तो यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ...(व्यवधान) मैंने जो लिखकर दिया है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप भूमिका मत बाँधिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। आपको एप्रीशियेट करना चाहिए कि हाउस शांत है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में मॉब लिचिंग हो रही है, देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।...(व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिचिंग के विरुद्ध कानून बनाने के लिए बक़ायदा वर्ष 2018 में फैसला दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, लोक सभा के उप नेता यहाँ मौजूद हैं, …(व्यवधान) क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत मॉब लिचिंग के खिलाफ कोई कानून बनाने वाली है? तबरेज़ अंसारी की हत्या होती है, उसके खिलाफ……(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Cosme Francisco Sardinha -- Not present.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Speaker, Sir, in Nagapattinam constituency, people are agitated over the long hours of train journey in the trains service from Thiruvarur to Karaikudi.

1213 बजे

(इस समय श्री हिबी इडन, श्रीमती डॉ. तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

To cover a distance of 140 kms., the train takes 6 to 8 hours. The delay is due to the 72 railway crossings, which have no gate-keepers. Before the train reaches the gate, the driver stops the train and the guard closes the gate. Once the train crosses the gate, the guard again opens the gate. This process is being done in all 72 gates. This unnecessarily waste the valuable time of the passengers. Patients who are going to hospitals, students, and office-goers are the worst affected. So, the people in my constituency are very angry.

(1215/PC/GM)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाह रहा हूं। …(व्यवधान) एक रोग है ड्यूकेनेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, यह ऐसी बीमारी है, जिसमें लगभग दस साल तक बच्चा स्वस्थ रहता है। …(व्यवधान) उसके बाद उस बच्चे के अंग

सिकुड़ने लग जाते हैं। …(व्यवधान) 20 साल की उम्र में जाकर वह बच्चा पूरी तरह चारपाई पकड़ लेता है। …(व्यवधान) कोई भी रोगी 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं जी पाता है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, भारत में इस बीमारी के इलाज के लिए एक संस्था है - इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर। यह संस्था एक मात्र संस्था है, जो इस बीमारी पर काम कर रही है। …(व्यवधान) इस बीमारी पर अमेरिका में दो से तीन करोड़ यूएस डॉलर खर्च हो जाता है। …(व्यवधान) हमारी यह संस्था इस पर काम कर रही है। …(व्यवधान)

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के रोगियों को बचाने के लिए भारत सरकार इस संस्था को उसके रिसर्च अनुसंधान के काम में मदद करे, ताकि इस प्रकार के रोगियों को लाभ मिल सके। …(व्यवधान) मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इस विषय पर ध्यान देगी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं श्री नारणभाई काछड़िया को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 14 रह गया था - श्री नित्यानन्द राय।

समिति के लिए निर्वाचन
राजभाषा संबंधी समिति

1216 बजे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : महोदय, श्री अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु राजभाषा समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु राजभाषा समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

विशेष उल्लेख - जारी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कागज़ सदन में नहीं लाएंगे। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह आपका राइट नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप सदन में कागज़ लाएंगे, तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Speaker, Sir, as per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, a Member cannot repeat the same matter in any form. Under Rule 197 sub-section (iv), "In case the number of members giving notices on a subject that is admitted by the Speaker…", it cannot be repeated. Even according to *Kaul and Shakdher*, a matter which has already been discussed by the House during the same Session cannot be raised again through the Adjournment Motion or by any other motion. I want to clarify, Sir, that they have already raised the issue and the hon. Deputy Leader and hon. Raksha Mantri has responded to it. As far as the Government at the Centre is concerned, we do not have any role as far as the Karnataka issue is concerned. This is because of Rahul Gandhi's call that this is happening in Karnataka. There are so many important Bills and important issues before the

country which they can raise. I appeal to them not to disturb the House. This the first Session of the House. Let them allow the House to run.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश में बड़े पैमाने पर नकली एवं मिलावटी दूध बिक्री जैसे अति लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए इजाज़त प्रदान की, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दूध एक ऐसी दैनिक उपयोग की वस्तु है, जिसका हम सभी के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। …(व्यवधान) हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सेहत क्रांति लाने के लिए गोकुल मिशन के अंतर्गत देशवासियों को शुद्ध दूध उपलब्ध करा रही है। …(व्यवधान) सरकार बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन नकली, मिलवटी दूध के कारोबार को रोकना भी इतना ही ज़रूरी है।

(1220/SPS/RK)

थोड़े दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था द्वारा सरकार को भेजी गई एक एडवाइजरी में कहा गया कि यदि भारत में मिलावटी दूध और उसकी उत्पादकता को तत्काल नहीं रोका गया तो साल 2025 तक भारत की 87 फीसदी जनसंख्या कैंसर जैसे जानलेवा रोगों की गिरफ्त में आ जाएगी। मिलावटी दूध यूरिया और खतरनाक रसायनों से बनता है।…(व्यवधान) देश के बड़े-बड़े शहर और डेयरी उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोग इस कारोबार में शामिल हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे बदमाशों के लिए सरकार कड़े से कड़े कानून का प्रावधान करे और फूड सेफ्टी एक्ट को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी करे। धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री नारणभाई काछड़िया और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को रखने का अवसर दिया। मैं कैराना लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारा शामली

जनपद केन्द्रीय विद्यालय से वंचित है। …(व्यवधान) सरकार की योजना है कि जनपद स्तर पर केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हो। वहां के बच्चे आस-पास के जनपदों में पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक होते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि कैराना क्षेत्र के जनपद शामली में केन्द्रीय विद्यालय की जल्द से जल्द स्थापना हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाइए, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं।

1222 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य
अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण प्लीज सिट डाउन।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। आप बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण आपके द्वारा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। मैंने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था में आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया। मैंने इस सदन में हर माननीय सदस्य को आउट ऑफ टर्न होने के बाद भी बोलने का मौका दिया है। जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि इस सदन की गरिमा को हमें विशिष्ट स्तर पर ले जाना चाहिए। यह सदन सब का है। यह सदन आप सब का सदन है। इस सदन को आप नारेबाजी और तख्तियों की ओर मत ले जाइए। मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि इस सदन के अंदर आप को जितना वाद-विवाद या संवाद करना कीजिए, मैं सत्ता पक्ष से भी कह रहा हूं कि जिन सवालों का जवाब देना

हो आप उनका जवाब दीजिए। अगर सब माननीय सदस्य सहमत हों तो इस सदन के अंदर तख्तियां और नारेबाजी को बंद करने की आवश्यकता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। आप जितने विषय उठाना चाहेंगे, मैं हर विषय पर आपको आउट ऑफ टर्न भी अलाउ करूंगा। आप विषय उठाइए। लेकिन मेरा आग्रह है कि दुनिया इस सदन को देखती है और यह आप का सदन है। आपको अपने सदन की गरिमा बनाकर रखनी है। आप तख्तियां लाकर इस सदन को नगर निगम और नगर परिषद जैसा मत बनाइए। अधीर रंजन जी, आपको जितना बोलना है, बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

(1225/KDS/RC)

माननीय अध्यक्ष : श्री दानिश अली जी, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। आप अभी मत बोलिए, बैठ जाइए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आपकी पीड़ा मैं समझता हूं, इसलिए पहले दिन से आज तक आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से हम बराबर सहयोग करते रहे। सर, आज हाउस की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हमारे योगदान के बिना हाउस की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती।

माननीय अध्यक्ष : यह केवल आपसे ही नहीं बढ़ रही, यह सबका सदन है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं केवल ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी विपक्ष का एक हिस्सा हूं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। सदन को चलाना, बहस करना, डॉयलॉग मारना, डिस्प्यूट करना हमारा काम है, डिसीजन लेना उनका काम है। हम मुद्दा उठाएंगे, लेकिन डिसीजन लेना उनका काम है। वे सरकार में हैं, पोजीशन में हैं और हम अपोजीशन में हैं। हम अपना फर्ज़ निभा रहे हैं, सरकार अपना फर्ज़ निभाए। यही हमारी उनसे उम्मीद है, इससे ज्यादा नहीं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि बैठे-बैठे न बोलें और न खड़े होकर बोलें। जब मैंने माननीय अधीर रंजन जी को बोलने को कहा है, तो वे ही बोलेंगे। आप ऐसा मत कीजिए। अधीर रंजन जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारे इस सदन में एक बहुत ही कद्दावर एवं वरिष्ठ नेता, जिनकी मैं बड़ी सराहना करता हूं, श्री अरुण जेटली साहब कहा करते थे – 'disruption is also a legitimate weapon for democracy.' तो क्या करें सर? हम भी तो हमारे वरिष्ठ नेता से ही सीखे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वाकिफ हैं कि कर्नाटक में क्या हालात हो रहे हैं। सिर्फ दो मुद्दे हैं। कर्नाटक ही नहीं, इस शिकार की राजनीति को बन्द करना चाहिए। यह पोचिंग पॉलिटिक्स बन्द करनी चाहिए। आज कर्नाटक, कल मध्य प्रदेश, इस तरह से एक के बाद एक अगर विधायकों को तोड़ा जाए, डिस्मेंटल किया जाए, पैसे का लालच दिया जाए, तो यह सही नहीं है। विधायक राजभवन से निकलते हैं, तो उनके लिए गाड़ी खड़ी है। एयरपोर्ट जाएंगे, हवाई जहाज खड़ा है। ठहरने के लिए आलीशान होटल तैयार है। इस सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कहते हैं कि हम अभी कर्नाटक ले रहे हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश लेंगे। यह शिकार की राजनीति, पोचिंग पॉलिटिक्स हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। इसे बन्द करना चाहिए, इसीलिए हम सदन में आए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की नीति और नीयत पर हिन्दुस्तान के आम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूं कि किसी भी हालत में लोकतंत्र को बचाकर रखें। शिकार की राजनीति बन्द होनी चाहिए। Poaching politics should be stopped. …(*Interruptions*). We are walking out.

1228 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष : सदन के उप नेता, रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए जो विषय इसी सत्र में, हाउस में उठाया गया है और पुन: आपने उन्हें बोलने की इजाज़त दी है, लेकिन इसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। …(व्यवधान)। यह सच है कि कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ, यह कांग्रेस के अपने घर का मामला है, लेकिन अपने घर को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के इस लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। …(व्यवधान)। मैं समझता हूं कि इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं यही कहना चाहता हूं। …(व्यवधान)

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ज्वलंत विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्ष 2014 में जब से माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, तब से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। अब शिक्षक पढ़ाना भी चाहता है, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं और अभिभावक भी 'पढ़े इंडिया, बढ़े इंडिया' में अपना सहयोग कर रहे हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होने के बावजूद अभी भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और कालेजों में हर वर्ष बच्चों के अभिभावकों से बिल्डिंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली तथा 10 माह की शिक्षा के बदले 12 माह की फीस वसूली जाती है तथा सिलेबस में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके पुस्तकों के नाम पर हजारों रुपये का चूना बच्चों के अभिभावकों को लगाया जाता है। इससे अभिभावकों का अपने बच्चों को पढ़ाने में पसीना छूट जाता है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005 से वर्ष 2018 के बीच प्राइवेट स्कूलों की फीस में 150 फीसदी का इज़ाफा हुआ है। स्कूलों में सालाना खर्च 55 हजार रुपये से बढ़ाकर लगभग डेढ़ लाख रुपये तक कर दिया गया है।

(1230/MM/SNB)

स्कूलों की ज्यादा फीस अभिभावकों के लिए मुसीबत बन गयी है। स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी में ज्यादा फीस वसूली जा रही है। कभी डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग, कपड़े और जूतों के नाम पर मनमाने ढंग से धन की उगाही की जा रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो विद्यालय संचालित हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है,

जिससे अभिभावकों के अपने बच्चों को पढ़ाने में अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सके, जिससे गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को उच्चकोटि की शिक्षा दिला सके।

महोदय, मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में अध्यापक हैं, उनमें ही उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे हर आदमी के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मुकेश राजपूत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter pertaining to my constituency during *Zero Hour*.

I wish to draw the attention of the Government to a serious matter regarding the havoc played by sea erosion in the coastal belt of Kerala in the last few days, especially in my constituency. When I visited various areas of my Parliamentary constituency, namely, Ponnani, I witnessed heavy damages caused at different places due to sea erosion. Many people living in the coastal areas like Aliyar Palli, Marakkadavu, Murinjazhy, Puthuponnani, Azheekkal, Veliyumkod, Thannithura, Palpetty and Kappirikkad have evacuated their houses due to heavy damages caused in the area. Similarly, places in the coastal belt like Tanur and Parappanangadi is also under severe threat of erosion. The situation is no different in other coastal areas of the State as well.

Fishermen are not in a position to go for fishing and their life has become miserable. The State may be given financial support by the Government of India to meet the difficulties of the fishermen. The existing sea wall is not being maintained properly. New sea walls would have to be constructed and a

proposal in this regard is pending with the Government of India. That proposal may be considered at the earliest. The major complaint is that the very construction of the sea wall has not been done scientifically. The intervention of the Government in this regard is also very much necessary.

I would like to urge upon the Central Government to adopt new scientific and technological methods to control sea erosion. The sea wall has to be constructed on a war footing. The pending application of the State Government for construction of the sea wall has to be considered forthwith. I would like to appeal to the Government to take up this matter very seriously.

Thank you.

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): महोदय, तेलंगाना राज्य का आलमपुर शहर जोगूलम्बा गदवाल जिले में आता है। आलमपुर शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित अधिकांश मंदिर बहुत पुराने हैं और अपने स्थापत्य के लिए विख्यात हैं। इनमें से ज्यादातर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत आते हैं। आलमपुर के सभी मंदिरों में जोगूलम्बा शक्ति पीठ, जोगूलम्बा देवी मंदिर और नवब्रह्मा मंदिर प्रमुख हैं। लोगों का मानना है कि देवी जोगूलम्बा उनके और उनके घर की सभी बुराइयों से रक्षा करती है। वास्तु दोष से मुक्त होने के लिए भी जोगूलम्बा देवी की पूजा की जाती है। जोगूलम्बा देवी मंदिर, जिसे जोगूलम्बा शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है, महाशक्ति के 18 पीठों में से पांचवां शक्ति पीठ है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के संगम पर तुंगभद्रा नदी के तट पर यह मंदिर बना है। इस मंदिर को दक्षिण काशी के नाम से पहचाना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख सकंद पुराण में भी किया गया है। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर को प्रसाद स्कीम में शामिल करके, मंदिर के विकास के लिए राशि आवंटित की जाए। यही मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड में जिला अस्पताल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था तथा संसाधनों की कमी से मरीजों को हो रही परेशानी की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

महोदय, जिला अस्पताल में प्रतिदिन 1600 से ज्यादा मरीजों का आना-जाना होता है, परंतु डॉक्टर और नर्स की कमी के कारण और मशीनों तथा उपकरणों के खराब रखरखाव के कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज अस्पताल में 300 बेड हैं, जबकि भाजपा सरकार में 400 बेड स्वीकृत हुए थे, परंतु आज तक मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार फण्ड स्वीकृत नहीं कर पायी है। अस्पताल में 39 डॉक्टर्स के पद स्वीकृत थे, जबकि अभी वर्तमान में 14 डॉक्टर्स हैं और 25 डॉक्टर्स का अभाव है। नर्स 168 स्वीकृत थीं, जबकि वर्तमान में 108 कार्यरत हैं और 60 नर्सों की कमी है।

(1235/SJN/RU)

अत्याधुनिक मशीनों तथा उपकरणों का अभाव है, जैसे कि सिटी स्कैन, एमआरआई आदि। अतः मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूं कि मरीजों को हो रही असुविधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिससे भिंड तथा आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संध्या राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान 30 प्रतिशत वनों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। एक समय था, जब घने जंगल थे, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई के चलते आज जंगल पेड़ विहीन हो चुके हैं। बड़ी मात्रा में सिर बोझा लकड़ी सूखी लकड़ी के नाम पर काटकर बाजारों में बेची जा रही है। वैसे तो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत 7 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर बोझा लकड़ी की कटाई नहीं रोकी जा रही है। मैं

जिस क्षेत्र से आता हूं वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। वहां पर कभी बहुत घने जंगल होते थे। उनमें से मझगवां, चितहरा, बांसा पहाड़, वारामाफी, मानिकपुर, मारकुण्डी, परसमनिया, नरोहिल में आज पूरी तरह से सिर्फ पलाश और गुलमेंहदी के पेड़ बचे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सिर बोझा लकड़ी काटने वाले लोग हैं, उनको चिह्नित किया जाए और उनको मनरेगा के माध्यम से वहां पर नया रोजगार देकर जंगलों में पेड़ लगाने का काम शुरू किया जाए। उनको चिह्नित करके वनोपज का पूरा लाभ उठाया जाए। जब तक सिर बोझा लकड़ी काटने की अनुमति रहेगी, तो जंगल इसी तरह से कटते रहेंगे। वर्तमान समय में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलाया है, उसके चलते उनको मनरेगा के साथ हर एक जंगल में फिर से वृक्षारोपण का काम दिया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री आर. के. सिंह पटेल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 61 का मरम्मत कार्य दो वर्षों से काफी धीमी गति से चल रहा है। इसके कारण बारसगांव से राहटी मार्ग पर आवागमन बाधित हो रहा है तथा जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मेरी सरकार सरकार से मांग है कि इस सड़क मार्ग के पुनर्निमार्ण का कार्य तीव्र गति से पूरा कराया जाए।

डॉ. के. सी. पटेल (वलसाड) : माननीय स्पीकर महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र वलसाड है। मेरे वलसाड और नवसारी जिले में आम की बहुत अच्छी फसल होती है। देश का 20 प्रतिशत आम हमारे गुजरात के वलसाड और नवसारी जिले में होता है। दो साल से मौसम की वजह से आम की फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो फार्मर्स हैं, उनका पेस्टीसाइड और खाद का पैसा भी नहीं निकलता है।

श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2015-16 में मेरे वलसाड जिले में बारह करोड़ रुपये नुकसान के लिए दिए थे और वह पैसे उनके खातों में जमा हुए थे।

अतः मेरी सरकार से अर्ज एवं नम्र प्रार्थना है कि इस साल भी सर्वे करके नवसारी और वलसाड जिले में जो आम की फसल में नुकसान हुआ है, उसमें उनकी हेल्प की जाए। मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे जो आम के पार्क हैं, उनका प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में समावेश किया जाए।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बैंकों में लगातार बढ़ रहे काम और कर्मचारियों की घटती हुई संख्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा है, उसके हिसाब से बैंकों पर लगातार बोझ बढ़ रहा है - खासकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास देश के सभी कामों का 70 फीसदी काम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हर काम, गरीब की पेंशन से लेकर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, वह सब कुछ डिजिटल इंडिया के कारण बैंकों के माध्यम से होता है।

(1240/GG/NKL)

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के होशंगाबाद, नरसिंहपुर और राइसिन जिले के अन्दर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वहां पर सारे बैंकों में कर्मचारी लगातार कम हो रहे हैं। एटीएमस में बराबर पैसा जमा नहीं हो रहा है। लोग लाइनों में लगे रहते हैं। जब तक उनका नंबर आता है, तब तक या तो सर्वर डाउन हो जाता है या फिर बैंक का समय खत्म हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बैंकों में बढ़े हुए कामों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे आम आदमी को बैंक का लाभ मिले और सरकार की जो मंशा है, उसको भी हम पूरा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जनपद लखीमपुर-खीरी, जहां की तीन विधान सभाएं, मेरे धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, वहां पर शारदा नदी बहती है। हर वर्ष इस नदी में तेज़ बहाव के कारण कटान होता है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट जाता है और हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। इसी तरह से मेरे लोक सभा क्षेत्र में गोमती नदी भी हो कर निकलती है, जो कि सूख गई है। यदि शारदा नदी से गोमती नदी को जोड़ दिया जाता है तो लखीमपुर के उत्तरी क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। साथ ही गोमती नदी में पानी आने से सूखे से भी राहत मिल जाएगी और आचमन के लिए जल भी उपलब्ध हो जाएगा। गोमती नदी के किनारों के तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ जाएगा। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि गोमती नदी के उद्गम स्थल, गोमत ताल से शारदा नदी को जोड़ने के लिए केवल 15 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ। धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I would like to tell you about a serious issue that our farmers are facing in Kerala.

As per the answer given on the floor, last week, to our hon. Member, Shri Anto Antony, more than 100 people were killed by animal attacks in Kerala. In my constituency, more than 30 people were killed.

Sir, in my constituency, there is more than 300 kilometres of forest boundary and more than 30,000 hectares of farmers' land which is now uncultivable due to frequent elephant attacks. There are so many preventive measures already taken by the Government, like the Project Tiger and the Project Elephant. It also provided funds for the restoration of natural water

bodies and food sources within the forest area to minimise the human-animal conflicts.

Sir, I have five suggestions to prevent the animal attacks. Firstly, the large conversion of forest land by the forest department for commercial purpose, including the plantations like eucalyptus, teak etc. should be stopped. It is inducing the animals to go outside the forests.

Secondly, we should erect a strong rail fencing. In my opinion, rail fencing is better. The solar fencing which is being used is totally ineffective.

Thirdly, we should give a proper compensation. That means, an effective compensation should be given to the victims.

Sir, I have another valid suggestion. The carrying capacity of forests must be scientifically assessed and steps must be taken to control the number of wild animals. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कास्मे फ्रांसिस्को कोईटानो सर्दिन्हा।

माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने का मौका दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री कास्मे फ्रांसिस्को कोईटानो सर्दिन्हा (दक्षिण गोवा): सर, थैंक्यू, मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया गया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बार नहीं, आप वॉक-आउट कर गए, तब भी मैंने मौका दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI COSME FRANCISCO CAITANO SARDINHA (SOUTH GOA): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Through you, I want to bring to the notice of the Minister of Railways, a very long pending issue which was also raised by my predecessor in the 16th Lok Sabha.

There is one village called Chandor, which is connecting many small towns and villages. There is a railway line passing through that side. Every now and then, whenever there is a passenger train or goods train crossing the line, the railway junction is closed. On either side, there is a queue of, maybe, 150 metres of cars and two-wheelers. So, I would like to bring to the notice of the Railway Minister to immediately take-up the construction of an over-bridge or an underpass so that people's hardships are brought to an end and they remember this Government forever.

HON. SPEAKER: Shri A.K.P Chinraj – Not Present

(1245/SRG/KN)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Hon. Speaker Sir, I request the Central Government, through you, to provide free educational loans for the students belonging to SC, ST and OBCs. You know that they are all economically poor students. So, economically poor students cannot afford to pay exorbitant tuition fee and other fee for higher technical and medical courses. Therefore, they approach the nationalized banks and cooperative banks for the educational loans for which the banks charge exorbitant rate of interest. Students repay these loans after the completion of their courses, say after five

years. The principal amount and interest amount thereon become burdensome. Therefore, I appeal to the hon. Finance Minister, through this House, to provide free educational loans to the SC, ST, OBCs and economically backward students across the country, so that they can repay in easy instalments without feeling the pinch of interest.

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य जो प्रथम बार संसद में आए हैं और पहली बार बोल रहे हैं, उनको मैं बुला रहा हूँ। उसके बाद वरिष्ठ सदस्यों को मौका दूँगा।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Speaker Sir, I am a first-time elected Member of Parliament from Bolpur constituency. I convey my regards to you and I also convey my sincere love and respect to all the Members of the Parliament. I am highly obliged to you for giving me a chance to say something in Parliament. I would like to draw your kind attention to some problems of Visva-Bharati University at Santiniketan. Visva-Bharati University is one of the famous universities in India. Students come from native country and foreign countries to study here. But it is very unfortunate that Teachers' appointment has been closed for a long time. As a result, students are being deprived of proper education. Besides this, the appointment of non-teaching staff has also been stopped for 19 years. As a result, the laboratory is about to be closed.

My second point is, the admission fee has been increased four times and the price of admission form has been increased two times. As a result, the poor and meritorious students are facing great inconvenience.

My last point is, …(*Interruptions*) this is the first time I am speaking. The Pearson Memorial Hospital has been closed. At present, there is no doctor and

no staff. Students are being deprived of proper treatment. We are very lucky that hon. Prime Minister is the Chancellor of the University. I would request the hon. Prime Minister, through you, to please look into the matter personally and solve the problem as early as possible. Thank you.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने माननीय मुख्य मंत्री नीतिश कुमार जी का और देश के प्रधान मंत्री जी और साथ में बैठे गृह मंत्री जी का, जिन्होंने सदन तक पहुँचने में मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपके माध्यम से सीतामढ़ी जिले की पूरी जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी आवाज़ बन कर मैं आज इस सदन में खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जो बिहार के नेपाल के बॉर्डर पर है, जो माँ सीता की जन्म स्थली है, जहाँ धरती से सीता जी प्रकट हुई थी।

(1250/CS/KKD)

सीतामढ़ी का अयोध्या से एक इंच भी महत्व कम नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सीतामढ़ी के स्थल को अयोध्या के बराबर का दर्जा दिया जाए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104, जो अयोध्या से सीतामढ़ी आता है, वह रोड चकिया से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से सुरसंड होते हुए जनकपुर धाम, नेपाल जाती है। उस रोड की स्थिति जर्जर है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर एक कुम्मा स्थान है, जहाँ एन.एच. पर डाइवर्जन पिछले 40 सालों से मैं देख रहा हूँ। सीतामढ़ी को डेवलप करके वहाँ आने वाले पर्यटकों को हम सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए रेलवे की कनेक्टिविटी जरूरी है। बगल के दरभंगा और मुजफ्फरपुर, जो एयरपोर्ट चालू होने वाला है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि वह जल्द से जल्द चालू हो। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और रक्सौल से चलने वाली ट्रेन को सीतामढ़ी तक जोड़ने का काम करें। आज सीता की जन्मस्थली पर बढ़ रहे अपराध भी एक चिंता का विषय है।

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तीरथ सिंह रावत जी।

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप नेक्स्ट टाइम बोलिएगा।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में एनआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2009 में खुला था। इसके खुलने के तत्काल बाद 930 छात्रों ने यहाँ आवेदन किया और वहाँ कक्षाएं चलीं। उसके पास में ही सुमाड़ी क्षेत्र में 350 एकड़ जमीन भी गाँव के लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो कि एनआईटी के नाम पर रजिस्टर्ड हुई। दुर्भाग्य से वहाँ एकाएक घटना घटी कि वहाँ से छात्रों को पलायन करना पड़ा। वहाँ से 625 छात्रों को जयपुर संस्थान में भेज दिया गया। इससे लोगों में एक आक्रोश और आन्दोलन पैदा हो गया। उन छात्रों में भी अपने भविष्य को देखते हुए उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरा भविष्य अंधकारमय न हो जाए, खराब न हो जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें भी धरना, प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। वहाँ छात्र आज भी आन्दोलित हैं और वहाँ संशय का वातावरण है।

मान्यवर, वहाँ जमीन उपलब्ध है, पैसा है और सब कुछ है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्री जी से कहना है कि उस ओर तत्काल ध्यान दिया जाए और संस्थान खड़ा करने के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मंजुलता मंडल।

माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्या पहली बार सदन में बोल रही हैं।

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Hon. Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak in this august on a very important matter.

Sir my Constituency is Bhadrak, Odisha, and I am the first women Member of Parliament from there.

Construction of flyover/bridges at Bhadrak, Ranital, Markona and Bahanaga railway stations should be given priority. Public and passengers are facing a lot of problems because of traffic issues there.

Sir, I would again request the hon. Railway Minister to give due attention to resolve the above issues relating to my Constituency. Thank you. Jai Odisha.

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): महोदय, आपने मुझे इस सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं अपने तेजस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मिथिला की धरती से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, जो जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि है।

(1255/RV/RP)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा में अवस्थित डी.एम.सी.एच. की 200 एकड़ भूमि पर एम्स के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया। इस पर भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित करके जाँच प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें कुछ त्रुटियाँ दिखाई गई हैं, जिसका निराकरण भी सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां के लोगों को हर वर्ष प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से

माँग करता हूं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए, ताकि उत्तर भारत के 22 जिले और नेपाल के 14 जिले के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में एम्स का निर्माण किए जाने से लगभग सात करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और इससे मिथिला क्षेत्र की चिरप्रतीक्षित माँग भी पूरी हो सकेगी।

धन्यवाद।

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. I wish to convey the severe disappointment of the people of Telangana that the assurances given to the people of Telangana in the Andhra Pradesh Reorganisation Act have not been addressed either in the Speech of the President of India or in the Budget presented by the Finance Minister.

There have been specific assurances given to the State of Telangana when the State was created. A Railway Coach Factory was assured at Kazipet; a Steel Plant was assured at Bayyaram; and a Tribal University was assured in the Act. I just wish to bring one thing to the notice of the Government through you. Last year, Rs. 1 crore was sanctioned. Similarly, Rs. 1 crore is sanctioned this year also. Is it possible to establish a new Tribal University with just Rs. 2 crore? So, through you, I appeal to the Government – the Home Minister is here and it comes under their Ministry – that whatever assurances were given to the State of Telangana at the time of its creation must be honoured. Thank you.

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Respected Speaker, Shri Om Birla, Sir, first of all, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on an important issue in Lok Sabha. I am a

practicing cardiologist at Wadhwan in Surendranagar. This is my Parliamentary Constituency. My city was previously known as Vardhmanpuri in the name of Lord Mahavir Swami who was the founder of Jain Sampradaya. Lord Mahavir Swami is known for non-violence. He stayed at my city while going to Palitana which is known for many Jain Temples.

Today, I speak here for our beloved defence personnel – Home Guards, State Police Force, SRPF, CRPF, BSF, Army, Air Force and Navy. We have been facing problems from some of our neighbouring countries for the last so many years. They are, both, notorious and anti-social in nature. They support and sponsor terrorist attacks as well as Naxalite attacks in some parts of our country. This anti-social activity may sometimes cause partial disability or permanent disability or death of our defence personnel. Recently, after the completion of General Elections, in my Constituency, I visited two young *shaheed* soldiers' families. Both the families are not in a good socio-economic condition. Both the families were dependent on *shaheed* soldiers' income.

Therefore, today, as a responsible Indian citizen, I would like to discuss about something which is beneficial for their family members. In India we have so many bank accounts either in the PSU banks or private banks. I propose to the Government to deduct only Rs. 1 from each and every account whether it is a savings account or a current account at the end of every financial year. The amount so collected can be used to support the family members of the *shaheed* soldiers. This amount can be distributed, in an appropriate manner, according to morbidity and mortality of our defence personnel. This amount should be

given in instalments to the family members of these martyrs so that their children can get better education and better lifestyle.

(1300/RCP/MY)

I would like to request the hon. Speaker to discuss this topic on the floor of Lok Sabha. This may encourage more young people to join the Defence brigade.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Hon. Speaker, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to raise an important issue pertaining to my constituency in the House. Through you, I would like to draw the attention of the Government as well as the hon. Minister to this issue.

As we all know, Bolangir belonged to the category of 'KBK districts' when it existed. It is a perennially drought-prone area. It is a backward area with less than three per cent irrigation. We have the problem of mass migration. There is lack of infrastructure in every possible way.

My request to you is this. Patnagarh is one of the oldest sub-divisions in my Parliamentary constituency which comprises of three blocks and a Notified Area Council. It has a population of 3,57,762, out of which 47 per cent of the population belongs to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe category according to the 2011 Census. A very high percentage of the population lives below the poverty line. Despite the fact that since 2018, Bolangir has been included in the Aspirational Districts Programme, this sub-division has only one Government-aided school which makes it very difficult to cater to the demands

of the large populace. The poor people of this area are facing immense difficulty to provide quality education to their children for lack of opportunity and resources.

Through your good offices, I would request the hon. HRD Minister to kindly consider the demand for establishment of a Kendriya Vidyalaya in Patnagarh in Bolangir Parliamentary constituency.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों का जीरो ऑवर लॉटरी से खुला था और किसी कारण से उनको बोलने का मौका नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से बोलने का अवसर देने की व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही सदन का समय बचेगा, उनको बोलने के लिए व्यवस्था दे दी जाएगी।

हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर तथा सरकार भी चाहती हैं कि सभी माननीय सदस्य बोलें। सभी को इस सदन में बोलने का मौका पर्याप्त रूप से दिया जाएगा।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।

1303 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/CP/MMN)

1401 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज मैं नियम 377 के अधीन मामलों को ले कर रहा हूं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है और मैंने सभी दलों के नेताओं को बुला कर कहा है कि संसद के सत्र में अब हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम समय 377 पर अपना वक्तव्य, जो लिखकर लाते हैं, उसको पढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि अधिकतम नए सदस्य अपनी बात रख सकें।

आज मैं बजट के वाद-विवाद के कारण 377 के अधीन मामलों को सदन के पटल पर रखने के लिए आप सबसे आग्रह कर रहा हूं। आप 20 मिनट के अंदर टेबल पर ले कर दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह जी।

Re: Supply of surplus water from Tikri Minor canal of Suryu Nahar Pariyojana - Phase II to Aranga reservoir in Gonda Parliaemtnray constituency, Uttar Pradesh

श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गौंडा): सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोण्डा में अरंगा, पर्वती और कोडर नाम के तीन प्राचीन प्राकृतिक जलाशय हैं, जो एक दूसरे से नाले के माध्यम से जुड़े हुए हैं तथा इनका क्षेत्रफल 6-7 हजार एकड़ में है। इन जलाशयों की वजह से उस क्षेत्र के भूजल का एक निश्चित स्तर बना रहता था, जिससे हजारों किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे।

विगत कई वर्षों से लगातार बरसात कम होने के कारण जलाशय सूखने के कगार पर आ गए हैं, जिससे हजारों एकड़ के क्षेत्रफल में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। और किसानों को सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है।

मान्यवर, सरयू नहर परियोजना खण्ड-2 की एक नहर-टीकरी माईनर अरंगा जलाशय के करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इस नहर का अतिरिक्त जल अरंगा झील में छोड़ दिया जाये तो कुछ हद तक इन तीनों जलाशयों के जल का स्तर बना रहेगा, जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई करने में काफी सुविधा प्रदान होगी।

(इति)

Re: Need to make Mahisagar river in Anand, Gujarat, pollution free

श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई) (आनंद): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र आनन्द में स्थित महिसागर नदी की गन्दगी की सफाई करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ पौराणिक कथाओं से जुड़ी इस नदी में हमारे जनपद और आस-पास के लोग दूर-दूर से आकर स्नान करना अपना सौभाग्य समझते हैं। धार्मिक दृष्टि से ओतप्रोत लोग इसके गन्दे पानी में मजबूरी में ही स्नान किया करते हैं। हमारी सरकार देश की नदियों की सफाई करने के लिए बड़ी ही तन्मयता से काम कर रही है किन्तु अभी तक देश में स्थित सभी नदियों की सफाई नहीं हो पाई है जिनमें एक हमारे क्षेत्र की महिसागर नदी भी है। फलस्वरूप वहां के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। उक्त कारण से नदी के आस-पास रहने वाले लोग परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तथा लोगों में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मेरे विचार से जन आक्रोश विकराल रूप न ले उससे पूर्व महिसागर नदी की सफाई शुरू हो जानी चाहिए।

अतः वहां पर व्याप्त जन आकोश को देखते हुए मेरा माननीय जलशक्ति मंत्री से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित महिसागर नदी की सफाई का काम उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब कराने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों में उत्पन्न जन आक्रोश समाप्त हो जाए और लोगों को शुद्ध जल उपलबध हो जाए।

(इति)

Re: Setting up of Trauma Centre level-I at Lala Lajpat Rai Hospital attached with Kanpur Medical College, Uttar Pradesh

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थापित जी0एस0वी0एम0 मेडकिल कॉलेज, कानपुर मंडल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत आठ जनपद (कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरूर्खाबाद, कन्नौज, इटावा एवं औरैया) आते हैं। इन जनपदों के अतिरिक्त आसपास के अन्य जनपद (फतेहपुर, झॉसी, महोबा, उन्नाव, हरदोई, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर) आदि दूरस्थ जनपदों के मरीज भी उपचार हेतु यहां आते हैं।

महोदय, मेडिकल कॉलेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय में दुर्घटनाओं में घायल रोगी अत्यधिक संख्या में आते हैं। कानपुर के आसपास के लगभग 15 से अधिक जनपदों में ट्रामा सेंटर न होने के कारण सभी रोगियों को जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में लेवल 2 स्तर का ट्रामा सेंटर इमरजेंसी विभाग के साथ चलाया जा रहा है, जो कि रोगियों की अधिकता के कारण अब काफी छोटा पड़ रहा है और वर्तमान में संचालित ट्रामा सेंटर के आसपास जमीन उपलब्ध न होने के कारण उसका विस्तार किया जाना संभव नहीं है।

लेवलः1 ट्रामा सेंटर, कानपुर में उपलब्ध नहीं है और लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर की दूरी लगभग 100 कि0मी0 से अधिक है। मेडिकल कॉलेज, कानपुर में नये ट्रामा सेंटर हेतु चिन्हित भूमि जी0टी0 रोड़ पर स्थित है। कानपुर नगर से 06 हाइवे (जी0टी0 रोड़ एन0एच0 2) आगरा हाइवे, कालपी-झांसी कानपुर रोड़ से सम्बद्ध है। विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में घायल रोगी प्रतिदिन उपचार के लिए आते हैं। यहां पर न्यूरो सर्जरी विभाग एवं कार्डियोथोरेसिक विभाग, मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्थापित किये जा चुके हैं, जिसमें चिकित्सा शिक्षक भी तैनात है। उक्त सुपरस्पेशलिटी

चिकित्सा शिक्षकों का उपयोग शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ लेवल-1 ट्रामा सेंटर के संचालन में भी किया जा सकता है, जो अन्यत्र चिकित्सालयों में उपलब्ध हो पाना कठिन होगा।

महोदय, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले सुपर स्पेशलिटी सेंटर के बगल में जी0टी0 रोड़ पर उपलब्ध भूखंड में यदि लेवल-1 ट्रामा सेंटर की स्थापना हो जाती है। तो इस क्षेत्र की जनता हेतु एक वरदान सिद्ध होगा। साथ ही सुपर स्पेशलिटी सेंटर प्रारंभ होने के उपरांत रोगियों को समस्त चिकित्सा सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायेंगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में मेडिकल कॉलेज कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में जी0टी0 रोड़ पर लेवल-1 ट्रामा सेंटर की स्थापना कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as project of national importance

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): बीसलपुर बांध का निर्माण कार्य बनास नदी पर टोंक जिले की देवली तहसील में किया गया है। वर्ष 1999 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा वर्ष 2004 में प्रथम बार पूर्ण भरा गया था।

वर्तमान में वर्षों से बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम हो रही है। विगत 15 वर्षों में मात्र 4 बार अर्थात् 2004, 20 06, 2014 एवं 2016 में ही बीसलपुर बांध पूर्ण रूप से भरा है। जबकि वर्ष 2010 में बांध लगभग पूर्ण रूप से सूख गया था। इसके अतिरिक्त बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी की गणना बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रगतिरत ईसरदा बांध की हाइड्रोलोजी में सम्मिलित की जा चुकी है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो का पानी टोरडी सागर में डाला जाना संभव नहीं है।

क्षेत्र के विस्थापितों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग अनुसार प्रस्तावित ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जो कि राज्य की कालीसिंध, चम्बल इत्यादि नदियों का पानी राज्य के 13 जिलों (झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, धोलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर) के बांधों में ले जाना प्रस्तावित है, के माध्यम से टोरडीसागर व मांशी बांध में डाला जाना प्रस्तावित है। लगभग 40,451 करोड़ रूपये लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डी.पी.आर. आवश्यक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को पूर्व में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार के समय ही प्रेषित की जा चुकी है। जिसका कार्य 3 चरणों में लगभग 7 वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के उत्तर पूर्व भाग टोंक व सवाई माधोपुर के साथ साथ अन्य 11 जिलों के किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण जीवनदायिनी परियोजना है। राजस्थान सरकार ने इस

प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से भी अनुरोध किया है।

(इति)

Re: Need to set up Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana Region

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand is having two major regions, Santhal Pargana and Chhota Nagpur. No doubt, the spread of Naxalism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region, which has been not only systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed in its homeland. Keeping the socio-economic problem being faced by Santhal Pargana in mind where agriculture is only the main source of income, we see an urgent need of comprehensive plan of action where special emphasis on good and equal opportunity of employment and friendly educational system is needed to be given utmost importance.

Santhal Pargana districts Deoghar, Godda, Jamtara, Pakur, Sahibganj and Dumka count amongst the socially, educationally and economically backward districts of the country. A look at the statistics of health, literacy, education, income, etc, gives an appalling picture of the poor state of the people.

Jharkhand is a rich state of poor people. It possesses 40% of India's mineral resources, but the access to resources has made little difference to the lives of ordinary people. Poverty and ignorance are still causes for low literacy rates, poor school attendance and large-scale drop outs.

I, therefore, draw the attention of the Government towards the need to set up three Kendriya Vidyalayas. An ideal location would be JARMUNDI (DUMKA), Deoghar and Mahagama (Godda) in the SANTHAL PARGANA Region. These locations are ideally suited for the purpose.

(ends)

Re: Need to expedite construction of Majhgay dam project in Madhya Pradesh

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो तथा बुन्देलखण्ड (मध्य प्रदेश) में पेयजल एवं सिंचाई जल की गंभीर समस्या है। इसका प्रमुख मझगांय परियोजना का पूर्ण न हो पाना है। महोदय, इस परियोजना में कैनाल केन नदी से मझगांय बांध में आयेगी। जमीन मध्य प्रदेश व मेरे संसदीय क्षेत्र की होने के बावजूद आधिपत्य उत्तर प्रदेश सरकार का है जिसकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। और केन नदी मध्य प्रदेश की होने के बावजूद इसके पानी का पूर्ण उपयोग रनगाव व बरियापुर बांध की माध्यम से उत्तर प्रदेश कर रहा है। यदि कैनाल की स्वीकृति दी जाती है तो मेरे संसदीय क्षेत्र पन्ना व अन्य क्षेत्रों की सैंकड़ों गांवों के लोगों को इसका सीधा-सीधा लाभ पेय जल व सिंचाई के लिए मिलेगा और सैंकड़ों एकड़ भूमि सिंचित हो जाएगी जिससे वहां के किसानों को कृषि करने में सहायता मिलेगी जिससे उनके जीवन में भी सुधार आएगा।

अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परियोजना को जल्द से जल्दी पूरा किया जाए और मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Delimitation of Assembly constituencies in Jammu & Kashmir

श्री अजय कुमार (खीरी): जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अनुसार वि0स0 सीटों का परसीमन प्रति 10 वर्ष में होना चाहिए परन्तु उक्त राज्य में 1995 के बाद परसीमन जनप्रतिनिधि कानून 1957 में संशोधन करके तत्कालीन मुख्य मंत्री फारूख अब्दुला द्वारा 2002 से 2026 तक रोक दिया। गया जिसके कारण लगभग 24 वर्ष से परसीमन नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि जम्मू काश्मीर राज्य में कुल 111 सीटें वि0स0 की हैं, परन्तु चुनाव केवल 87 सीटों पर होता है 24 सीटें राज्य के संविधान के अनु0 47 के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ दी गई हैं तथा कुल राज्य के मात्र 15.37 प्रतिशत घाटी के क्षेत्र 46 विधायक चुने जाते हैं, तथा घाटी की कुल आबादी में 11 प्रतिशत गुर्जर, बकरवाल व गड्डी जनजातीय होने के बावजूद भी घाटी की किसी भी सीट पर आरक्षण नहीं है। इसलिए नये परसीमन से न केवल सही प्रतिनिधित्व भी हो सकेगा वहीं सामाजिक समीकरणों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्कालीन सरकार के आदेश में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में होने वाले वि0स0 चुनाव से पूर्व नया परसीमन कराने व लागू करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Appointments on compassionate ground

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान भारत सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही अनुकम्पा आधार पर किए जाने वाली नियुक्ति की विसंगतियों के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी केन्द्रीय कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को भरण-पोषण हेतु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है एवं इसके लिए पांच प्रतिशत मृतक आश्रित भर्ती कोटा निर्धारित है।

महोदय, उक्त प्रावधान वर्ष 1998 से चला आ रहा है एवं वर्तमान परिदृश्य में यह अव्यवहारिक होता जा रहा है। एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हो गया है। क्योंकि मृतक आश्रित भर्ती कोटा की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान में अनुकत्या के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले पांच प्रतिशत मृतक आश्रित भर्ती कोटे के स्थान पर मृतक आश्रित की मृत्यु के तीन महीने के अंदर अनिवार्य रूप से उसके आश्रित को नियुक्त किया जाए।

(इति)

Re: Need to start flight services from Gondia Airport under UDAN Scheme

श्री सुनिल बाबूराव मेंधे (भन्डारा-गोंदिया): महोदय, गोंदिया एयरपोर्ट जो 9 साल पहले ही बनकर तैयार है। जहाँ 2290 मीटर का रनवे और टर्मिनल यात्रियों की सभी सुविधाओं के साथ बनकर तैयार है और वहाँ से एयरबस 320 का आवागमन हो सकता है। वह पिछले 9 साल से एक भी कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है जिसकी वजह से आसपास के गोंदिया, आमगांव, बालाघाट, लांजी, भंडारा, डोंगरगढ, गढ़चिरौली के लोगों को असुविधा महसूस होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से विनती करना चाहूँगा कि भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी करके वहाँ से प्रैक्टिकल तौर पर वहाँ से 1-2 फ्लाइट चालू की जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके।

(इति)

Re: Need to expedite electrification of Itarasi - Allahabad railway route

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): इटारसी-इलाहाबाद विद्युतीकरण परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वर्ष 2014 में केन्द्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस परियोजना को पर्याप्त फण्ड उपलब्ध कराया, जिसके फलस्वरूप मात्र 4 वर्षों में इटारसी से कटनी तक का ट्रैक विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं उक्त ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है।

कटनी से सतना एवं उसके आगे के ट्रैक का कार्य अभी शेष है, जिनके कारण कटनी जंक्शन में ट्रेन का पॉवर रिवर्सल किया जाता है, जिससे काफी समय का अपव्यय होता है। इस पूरे ट्रैक के पूरा होने से जहां एक ओर ट्रेनों की समय की पंक्च्युलटी वहीं रेलवे को राजस्व का भी लाभ होगा।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इटारसी-इलाहाबाद विद्युतीकरण परियोजना के शेष कार्यों को समयावधि में पूरा किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to include Bhojpuri language in Eighth Schedule to the constitution

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): अभिव्यक्ति के लिए भाषा की महत्ता और अनिवार्यता कितनी है हम सभी इससे अवगत हैं। इसी कारण व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के विकास, प्रचार, प्रसार और मान्यताओं के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में से एक प्राचीन भाषा भोजपुरी भी है। यह भाषा विश्व के कई देशों तथा देश के कई राज्यों में करोड़ों-करोड़ों लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इतनी प्राचीन और बड़े भू-भाग में बड़ी जनसंख्या में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु देश के अनेकों संगठनों, प्रतिनिधियों द्वारा बहुत लम्बे समय से संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जाती रही है। पूर्व की सरकारों द्वारा कई बार आश्वासन भी दिया गया कि इसे आठवीं अनुसूचि में शामिल किये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाया जायेगा। इसके बावजूद आज तक भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाये जिससे की देश के अंदर वास कर रहे करोड़ों लोगों की भवनाओं और उनके विश्वास का आदर हो सके।

(इति)

Re: Providing corpus fund for the creation of an SC/ST bank

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): This Government has taken several steps to ensure the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India. The Stand Up India Scheme allows SC/ST and women entrepreneurs to avail loans in the range of Rs.10 lath and I crore for setting up a new enterprise. Until 2016, the total number of entrepreneurs that have benefitted was 21,735 and the total amount sanctioned was Rs.4747.95 crore. Furthermore, the Ministry of MSME has launched an SC/ST Hub to provide professional support to SC/ST entrepreneurs and the Ministry of Social Justice and Empowerment has created a Venture Capital Fund to promote entrepreneurship amongst the SC population, with a special focus on women. To supplement these efforts, I would like to request the Government to provide a corpus fund for the creation of an SC/ST Bank for Entrepreneurship Development amounting to Rs.10,000 crores.

(ends)

Re: Need to provide rail link between Meerut and Panipat

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पानीपत हरियाणा में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं आर्थिक केन्द्र है। परन्तु मेरठ व पानीपत के मध्य अभी तक कोई रेल संपर्क नहीं है। मेरठ हैंडलूम, खेल उद्योग, प्रकाश उद्योग, स्वर्ण आभूषण निर्माण उद्योग तथा गुड़ एवं चीनी का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है। मेरठ को पानीपत जैसे महत्वपूर्ण नगर से रेल के द्वारा जोड़ने के महत्व को सरकार ने स्वीकार करते हुए वर्ष 2017 के रेल बजट में सर्वेक्षण हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि भी अवमुक्त की थी। इस रेल संपर्क से मेरठ के साथ मुजफ्फरनगर, बागपत एवं शामली तथा हरियाणा में पानीपत व समीपवर्ती क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास होगा।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ तथा पानीपत के मध्य रेल मार्ग निर्माण करने का कार्य मंत्रालय द्वारा शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

(इति)

Re: Need to declare Gandhi Ashram in Vaishali district, Bihar as National Heritage

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): वैशाली जिले के हाजीपुर रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर ऐतिहासिक गांधी आश्रम स्थित है, जहां स्वतंत्रता आन्दोलन के जमाने में महात्मा गांधी आया करते थे। गांधी आश्रम अपने दामन में स्वतंत्रता संग्राम व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े कई ऐतिहासिक क्षणों को समेटे हुए है। इस आश्रम से बापू की कई यादें जुड़ी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा है। जुब्बा सहनी, योगेन्द्र शुक्ला, बैकुण्ड शुक्ला, दीप बाबू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का कर्म स्थल रहा। ये गांधी गाश्रम आज सरकारी उदासीनता का शिकार है साथ ही इसकी चल अचल संपत्तियों पर लोगों का अवैध कब्जा हो चुका है जिसे कब्जाधारियों के चंगुल से निकालने की अति आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस गांधी आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए साथ ही जुब्बा सहनी, योगेन्द्र शुक्ला, बैकुण्ड शुक्ल आदि अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारक बनवाया जाए।

(इति)

Re: Need to fill up backlog vacancies meant for SCs/STs in Central Government offices and Departments

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकारी विभागों व अर्ध सरकारी विभागों तथा राज्य स्तरीय सरकारी विभागों में भारी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैकलॉग में सीटें खाली पड़ी हैं और पदों की भर्ती न होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति निराशा पैदा हो रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी युवा बेरोजगारी के कारण खाली घूम रहे हैं। यदि इन खाली पड़े बैकलॉग के पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा इन नियुक्तियों को भरा जाएगा तो लाखों परिवारों को रोजगार मिल जाएगा और सरकार का भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति यह सहानुभूति का अच्छा संदेश जाएगा।

अतः केन्द्र सरकार सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैकलॉग में खाली पड़े पदों को तत्काल भरने के आदेश को लागू करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to ensure Minimum wages Act is applicable to Tea Garden workers

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): In North Bengal — Darjeeling, Alipurduars, Jalpaiguri and Cooch Behar are dominated by Tea plantations, but the workers here are deprived of their basic wages. They are paid only Rs 176 per day, which is the lowest wage paid in the nation.

Minimum Wages Act is applicable across all sectors in Bengal, except in tea gardens. Despite being a highly skilled job, their salary is lower than the minimum wage for unskilled agricultural workers in the state.

Tea gardens are governed by the Plantation Labour Act of 1951, directly derived from the British feudal system that favours tea garden owners and denies Land Rights to workers. The owners can shutdown and reopen tea gardens without any accountability towards the workers. Hence, I request this august house to make comprehensive changes to the PLA Act to reflect the realities of New India and ensure Minimum Wages Act is applied to tea gardens too.

(ends)

Re: Wild animals menace

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The farmers of Idukki are facing destruction of crops caused by the wild animals. It has also been found in recent years that wild boar population is rising. Five people were killed this year due to the attack of wild elephants and twenty persons were injured. The total loss is estimated to be Rs.25 crore.

This is because of non-availability of food for wild animals within forest. Forests are being used for non-forest activities like teak and eucalyptus plantations, resulting in reduced food availability. The Forest Department should be responsible for keeping wild animals within the forest. If farmers are at a loss, they must be fully compensated for that loss within 48 hours. There must be adequate insurance coverage to cover for death. I urge upon the government to take necessary steps to prevent the attack of wild animals and adequate insurance coverage should be provided to the injured.

(ends)

Re: Implementation of POCSO Act

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The POCSO Act, which provides for death penalty for aggravated sexual assault on children, making it gender neutral and introducing provisions against child pornography and for enhancing punishment for certain offences is aimed at discouraging the trend of child sexual abuse by acting as a deterrent. There is increasing concern in Kerala, that despite its special focus on children and specific child-friendly provisions, too many cases are piling up, and thousands are pending. All cases registered under POCSO Act in Kerala do not end up in convicting accused. Therefore, I request the government to take stringent measures to deter the rising trend of child sex abuse in the country by ensuring fair trial and make sure that all the pending cases specially in Kerala are disposed off urgently .

(ends)

Re: Funds for AMU Kishanganj Campus, Bihar

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I want to draw the attention of the Government towards the fact that an amount of Rs.137 crore was sanctioned for Aligarh, Muslim University, Kishanganj Campus, Bihar by UPA government, and till date only Rs.10 crore has been released. I, therefore, request that more funds are to be immediately released and more courses may be introduced. Further, entrance for various courses should have centres in Kishanganj, Bihar.

(ends)

Re: Need to provide better rail connectivity to Namakkal in Tamil Nadu

SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL): My Namakkal parliamentary constituency is famous for poultry business and truck body building industry Namakkal district is considered as a major trucks hub in the country and it alone has about 110 units. The Namakkal-Tiruchengode belt accounts for over 150 of the units. A lot of raw materials like steel, timber and other materials come to Namakkal from various parts of the country and lot of fodder items and other essential things come from various parts of the country to meet the demands and shortages of the poultry industry.

At present, one weekly train Tuticorin to Okha express is running from Tuticorin via Karur-Erode-Salem. I request the Hon'ble Minister to divert this train route via Karur- Namakkal-Salem (instead of Erode) which will be more useful for the poultry industry and truck body building industry. Likewise, Nagarkoil to Mumbai express (No. 16339/16340) is running from Karur-Erode-Salem 04 days in a week. This train is also to be diverted via Namakkal (instead of Erode), so that the textile industry, poultry industry and truck body building industry will be benefitted and be developed. Further, a daytime intercity express may be introduced from Karur-Namakkal-Salem-Chennai and vice versa for the convenience of the officer goers, businessmen. In addition to that, a full-fledged infrastructure facilities along with Escalator and Lift facilities may be provided in Namakkal Railway Station.

Hence, I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to 'take necessary action immediately to fulfill the long pending demands of my Namakkal constituency people.

(ends)

Re : Transfer of Government assets to private hands

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The civil aviation sector in the country is in doldrums with the government refusing to intervene in the sector. The Jet Airways has been closed throwing twenty thousand employees out of work. It has now been referred to the National Company Law Tribunal, which may take a lot of time to resolve the problems. The government has stated that it intends to disinvest Air India, thus ending the government presence in the airlines sector. Three airports belonging to the Airport Authority of India are being leased out to the Adani group thus transferring government assets to private hands. I oppose the government's efforts to privatize the airline sector and also the government airports.

(ends)

Re: Varikapudisala Lift Irrigation Project in Andhra Pradesh

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The country gradually acknowledges the acute water crisis affecting our major cities and towns in recent weeks. But today I will highlight a historically prevalent and perennial drought that has plagued the plateaus of Palnadu in Andhra Pradesh.

It was in 1952 that this region, eternally challenged by hilly terrain and high temperatures, was declared drought prone. The same year, the Varikapudisala Lift Irrigation Scheme was deemed most essential to resolve the shortage of drinking and irrigation water in Guntur district, particularly in the mandals of Karampudi, Durgi, Veldurthi, Bollapally and Pullelacheruvu.

I regret to inform you that 67 years later, the scheme is yet to see the light of the day. In 2008, the then Chief Minister of United Andhra Pradesh had made herculean efforts for the scheme, beginning at Gangalakunta. However, successive State Governments had pulled the plug on the visionary idea. As a result, more than 4,50,000 people have been reeling under distress without drinking water. Hence, 1,20,000 acres of land remain uncultivated.

This summer, almost 30 lakes and other water streams dried up. The Water level in the Nagarjuna Sagar Project has seriously depleted. Borewells were dug to a depth of 1200 feet to but to no avail.

The people of Palnadu Region need full support of the Central Government to help lift Krishna River water to a mammoth height of 80 to 100

feet and impound it into the Vajralapadu lake. I request the Ministry of Jal Shakti to help harness this water resource by way of Jal Shakti Abhiyans with much needed Central funding.

The lake water is to be supplied to over 90 villages by a main pipeline of 7.5km running through 10 acres of forest land, but the acquisition of forest land has been a bone of contention in the region. I request the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to coordinate with the State Forest Department for clearance and certification to realize the Varikapudisala Lift Irrigation Project.

(ends)

Re : Setting up of Post Office Passport Seva Kendra at Dombivali in Maharashtra

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Former Minister of External Affairs, in June 2017 had sanctioned a POPSK in my Constituency. After a lot of deliberation, it was found that the Post Office at MDC, Dombivali (E) would be the most suitable location for the opening of this POPSK. However, this post-office had only 200 Sq. Ft. of constructed space in place of 300 Sq. Ft. (as required under MSR) while several Sq. Ft. of space (about 1000 Sq. Ft.) is left open and unconstructed in the same premises. Moreover, this was the only post office in Dombivali which is functioning from the department building. Despite several follow ups, I couldn't get an amicable solution. I request the Hon'ble Minister of Communications to kindly permit construction of 500 sq. ft. structure at the said premises by using my MPLAD Fund and facilitate the opening of this POPSK at the earliest.

(ends)

Re: Gauge conversion of railway lines between Banmankhi and Bihariganj in Bihar

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य अन्तर्गत पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के बनमनखी से बिहारीगंज 28 किलोमीटर रेल लाईन आमान परिवर्तन के निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2014-15 में हुई थी। उक्त निर्माण कार्य पर 31 जनवरी 2016 से ब्लॉक भी लगा दिया गया। उक्त खंड के बनमनखी से बड़हरा कोठी 16 कि0मी0 का निर्माण पूर्ण कराकर गाड़ी भी चला दी गई है। शेष बचे बडहरा कोठी से बिहारीगंज 12 कि0मी0 का निर्माण अधूरा है। इसके बीच दो ब्रिज का निर्माण भी बहुत धीमी गति से हो रहा है। बिहारीगंज तक आमान परिवर्तन काम पूरा होने से सिर्फ बिहारीगंज बड़ा व्यापारिक केन्द्र ही नहीं बल्कि पूरे अनुमंडल के लोगों को रेल सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

आग्रह है कि बनमनखी-बिहारीगंज रेल खंड के शेष बचे बड़हरा कोठी से बिहारीगंज 12 कि0मी0 आमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण कराया जाए।

(इति)

Re : Setting up of Red Gram Board in Tandur region of Telangana

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA) : Red Gram is the most important pulse in the country and its ability to produce high economic yields even if there is soil moisture deficit makes it vital crop in rainfed and dryland agriculture. With rich source of 23% protein, vitamins and minerals, Redgrarn has become an indispensable part of Indian meal and is also used as feed and fuel.

Redgram is grown in 2.25 lakh hectares in Telangana and is lifeline for the dryland farming community in Ranga Reddy district. With market preference for 'Tandur Tur Dal' and consistent demand for this particular 'brand' of Tur Dal in commodity markets, farmers are getting good price. Secondly, demand for Tandur Tur Dal is due to its unique taste, better cooking quality and enhanced keeping quality of cooked dal helps it to get even the GI tag.

Farmers, scientists, traders and public representatives have been requesting for setting up of Red Gram Board in Tandur as:

> its productivity in Tandur is 758 kg/ha — far higher than national average of *655* kg/ha.

> has immense potential for export. Tandur region is the biggest market for Redgram.

> getting support from Prof. Jayashankar Telangana State Agriculture University and from ICRISAT which has a mandate to conduct research on Redgram.

> helps in timely support to small and marginal farmers with credit, inputs, etc. and availability of processing plants.

In view of the above, I request Government of India to set up Redgram Board in Tandur at an early date. (ends)

Re : Providing financial assistance to farmers who were hard hit by cyclone Gaja

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): In my Constituency, Nagapttinam, Thiruvarur, Thiruthuraipoondi, Muthupettai, etc., are yet to recover from cyclone Gaja. I would like to draw the attention to the Union Government to release more funds in the upcoming budget for the purpose. The Cavery water has not yet been released to Tamil Nadu so the farmers are suffering.

In fact, cyclone Gaja severely affected the crops, uprooted lakhs of coconut trees, teak trees, banana trees, destroyed the houses, killed people, displayed boats, uprooted thousands of electrical posts, cell phone towers, transformers etc. People faced untold suffering after the Cyclone Gaja wiped out everything from their houses. On the one hand the Cyclone destroyed the poor. On the other hand, it has made the rich and middle class poor overnight. Farmers are yet to receive funds from the government. The Central Government released a meagre amount which is not at all sufficient in comparison to the damages ravaged by Cyclone Gaja.

Hence, I request the Union Government to kindly provide the fund to the farmers immediately.

(ends)

Re : Need to put in place safety measures for Kollam bypass in Kerala

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The Kollam bypass was commissioned on 15th January 2019. Required safety measures were not provided in the bypass. The bypass has become an accident prone area, 54 Accidents were reported within 5 months, 7 persons died and more than 100 including pedestrians sustained injury. 57 by-roads are connected to the 13 kilometer bypass. The development of bypass with service road and development of junction are necessary for avoiding accidents. If the safety measure are not provided the entire bypass will become a black spot. Land is available for development of bypass. Speed control is also required.

Hence, I urge upon the Government to initiate urgent action for providing safety measures in Kollam bypass and impose speed restriction as immediate solution and develop the Kollam bypass into four lane road with service road.

(ends)

Re: Need to establish a Tourism University in Parasnath Hills in Giridih parliamentary constituency and promote tourism in the region

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाडी माँ भारती की गोद में मौजूद हमारे देश की वह धरोहर है जो आज के भारत को प्राचीन सभ्यता से जोड़ती है। इस अनमोल धराहर को वतमान सह भविष्य के भारत हेतु कुछ इस अंदाज में पिरोएं कि हमारे जैन साथी से लेकर झारखंड और पूरे भारत में परचम विश्व पटल पर लहरा दे। इसका एक ही रास्ता है हम इसे पर्यटन स्थल के रूप में सूचित करे ।। निवेदन है कि झारखंड की पारसनाथ पहाडी में पर्यटन विश्व विद्यालय की स्थापना की जाय एवं पर्यटन उद्योग स्थापित किया जाय।

(इति)

सामान्य बजट - सामान्य चर्चा - जारी

1403 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनने वाली सरकार ने स्वदेशी की तरह स्वदेशी का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को सलाम करता हूं।

अध्यक्ष जी, राजनैतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट पैदा हुआ है, पहली बार इस बजट ने देश को यह एहसास कराया है कि राजनैतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट समाप्त करने के लिए नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार काम कर रही है। वर्ष 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी, तो प्रधान मंत्री जी ने संसद भवन के सामने माथा टेक कर इस बात का संकल्प किया था कि यह सरकार गांव, गरीब, किसान तथा सेना के जवान के लिए समर्पित सरकार होगी। पांच साल चलने वाली सरकार ने गांव में रहने वाले गरीबों के मन में भरोसा पैदा किया। गरीब एक शौचालय के लिए तरसता था। आज गरीब के घर के सामने एक शौचालय दिखता है, तो उसे लगता है कि कोई सरकार हमारी चिंता करती है और हमारे घर के सामने एक शौचालय भी बनाती है।

आजादी की लड़ाई के दिनों में मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जब आजादी मिलने वाली थी, तब गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों के सामने कहा कि आजाद देश, स्वच्छ देश और स्वस्थ देश ही स्वतंत्र देश होता है।

(1405/NK/SAN)

उसके लिए नरेन्द्र भाई मोदी जी ने काम किया। मैं गुजरात की धरती को नमन करता हूं। संसदीय राजनीति के बाहर मोहन दास करमचंद गांधी जी को पैदा किया, उतना बड़ा नेता अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन संसदीय राजनीति के भीतर उसी गुजरात का सपूत नरेन्द्र भाई मोदी पैदा हुए, संसदीय राजनीति में उतना बड़ा नेता कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं इंदिरा गांधी को भी कहता

हूं। सरदार पटेल को इन लोगों ने वहां पहुंचने नहीं दिया। आप हमें डिस्टरब मत कीजिए। …(व्यवधान) अभी शुरू किया है और अभी से ही कलह शुरू कर दी। …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने बोलूंगा। इन लोगों से भी कह दीजिए कि मेरे सामने करके न बोलें। गरीब के मन में भरोसा पैदा हुआ है। राजनीति में भरोसे का संकट कहां से पैदा हुआ? देश की संसदीय राजनीति में भरोसे का संकट इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखता कुछ है। हिन्दुस्तान के किसानों के मन में पहली बार मन में भरोसा पैदा हुआ है। कोई सरकार है जो कहती है, वह करती है और जो दिखता है, उसका परिणाम वर्ष 2019 में आया। हम इस बात को कह सकते हैं। संसदीय राजनीति में विरोध करना लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा आधार है, अपोज करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि अपोज करने की भी ताकत खत्म हो गई है। हमको लगता है कि हम लोगों को ही पैदा करना पड़ेगा।

अध्यक्ष जी, किसानों के मन में भरोसा पैदा हुआ है। नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में संसद ने किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य देने के लिए कानून बनाया है। पहली बार किसी सरकार ने हिन्दुस्तान के किसानों के खाते में छह हजार रुपये देने का फैसला किया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कम है, जिन लोगों ने कभी छह पैसे किसानों को नहीं दिए, वही लोग कहते हैं कम है। उसका विश्लेषण जानना चाहिए, खतौनी में एक बीघा खेत, एक कट्ठा, एक बिसवा, अगर दस भाई का नाम है तो दसों भाई को छह-छह हजार मिलेगा। अधीर जी, इस बात को आपको जानना चाहिए कि उसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण यह है कि अगर भूमिहीन किसान ने अपने परिश्रम के पसीने से एक बिसवा भी खेत खरीदा है और उसके छह भाई हैं तो उसको सलाना छत्तीस हजार रुपये मिलेंगे, इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। आप पन्द्रह रुपये रोज मजदूरी जोड़ते हैं, मैं किसान हूं और इस बात को जानता हूं। यह पहली सरकार है जिसने हिन्दुस्तान के किसानों को गोबर खाद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मैं सदन के सभी भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने संसदीय क्षेत्र में गोबर की खाद पर सब्सिडी देने का प्रावधान सरकार ने लागू किया है, अपने संसदीय क्षेत्र में उसे लाभकारी बनाएं। किसान के सवाल पर मतभेद मत पैदा करो। यह देश किसानों का है। यह देश कृषि प्रधान देश

है। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई और सहयोग होना चाहिए, जो संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। किसान अपना खाता ही नहीं खिलाता भी है। जब यूरोप के देशों में आंदोलन चल रहा था, कमाने वाले खाएंगे और लूटने वाले जाएंगे, भारत में आंदोलन चल रहा था कि हम खाते ही नहीं खिलाते भी हैं, लूटने वाले जरूर जाने चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं पहले तीन बार भदोही से सांसद था, अब बलिया से सांसद हूं, पार्टी ने आदेश दिया। माननीय मुलायम सिंह जी उपस्थित हैं। बलिया को ठीक से जानते हैं। यह पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्र शेखर जी का क्षेत्र था, इस बार वहीं से सांसद बना हूं। मेरी जन्म भूमि भी वहीं है। लोक नायक जय प्रकाश नारायण और मेरा गांव अगल-बगल है। बलिया ऐतिहासिक भूमि है। देश 1947 में आजाद हुआ था लेकिन मेरा बलिया 1942 में आजाद हुआ था। वहां के गांव में रहने वाले किसान, गांव में रहने वाले कामगार ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए 1942 में बलिदान दिए थे।

(1410/SK/RBN)

1410 बजे (श्री ए. राजा पीठासीन हुए।)

आज भी जितनी जागरूकता है, राजनैतिक जागरूकता है, इस बात को आप देख सकते हैं, हमारा और जय प्रकाश नारायण जी का गांव एक ही है। मुलायम सिंह जी गए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भी वहां गए हैं, बहुत से लोग गए हैं। चन्द्रशेखर जी ने पदयात्रा के दौरान सपना देखा था, पीने के पानी का सवाल देखा था, उन्होंने कहा था कि लगता है कि इस देश में पानी के सवाल पर युद्ध होगा। इस कठिनाई को सबसे पहले अगर किसी ने समझा है तो इस देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने समझा है। सबसे पहले भारत सरकार में जल संरक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू हुआ। मैं पिछली तीन बार से भदोही से सांसद था। 67 किलोमीटर की मोरवा नदी सूख गई थी, मैंने तलहटी से लगकर, अपना और अधिकारियों के श्रमदान से पानी प्रवाह करवाया। आज भी वहां पांच फीट पानी देखने को मिलता है। मैंने वहां तालाब खुदवाए। पानी में प्रदूषण है, आर्सेनिक है, अगर सब सांसद अपने क्षेत्रों में तालाब खुदवा देंगे, प्राकृतिक जल प्रवाह

को जीवंत कर देंगे तो किसी पानी में कोई प्रदूषण नहीं रहेगा। अगर तलहटी खुदवाएंगे, बालू तक जाएंगे तो पानी स्वाभाविक तौर पर ऊपर आ जाता है, मैंने इसे प्रयोग में देखा है।

सभापति जी, बलिया में मैंने काम शुरू किया है। सूरह ताल दुनिया का प्रसिद्ध ताल है, मैं शनिवार को इसकी खुदाई शुरू करवाने वाला हूं। एक ऐसा कटहल नाला है जो छ: महीने उत्तर की तरफ चलता है और छ: महीने दक्षिण की तरफ चलता है, मैं इसकी खुदाई करवाऊंगा। दोआबा में भागड़ नाला है। घाघरा, गंगा और तमसा के बीच में बसने वाला बलिया है। बलिया वर्ष 1942 के आंदोलन में पहले आजाद हो गया, गांधी जी का वहां कम आना-जाना था। सुभाष चन्द्र बोस जी का वहां आना-जाना ज्यादा था। जय प्रकाश नारायण जी के सुभाष चन्द्र बोस जी के पारिवारिक संबंध थे, कुछ दूर की रिश्तेदारियां थीं। वर्ष 1941-42 में जब सुभाष चन्द्र बोस अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर दिए गए थे तो बलिया में आकर चुपके से जय प्रकाश नारायण जी के यहां रहते थे। किसानों के बीच में जाकर काम करते थे। उसी का परिणाम हुआ कि 1942 में देश को आजाद करने का रास्ता बलिया ने दिखा दिया था। बलिया विद्रोह की धरती है। यहां के ऋषियों-मुनियों में भी विद्रोह की ताकत है। भृगु बाबा की धरती है। भृगु बाबा ने क्रोध में विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी थी। उसी विद्रोह की प्रेरणा आज भी बलिया के लोगों को मिलती रहती है। वहीं सुभाष चन्द्र बोस ने पहली बार टाउन हाल मैदान की मीटिंग में कहा था – 'तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उन्होंने यह कहा था। विधाता का क्या विधान है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई ने भी उसी बलिया की धरती पर कहा – 'तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें सुशासन दूंगा।' उसी सुशासन का प्रमाण-पत्र यह बजट है। उसी सुशासन का दस्तावेज यह बजट है। गांव, गरीब, किसान के समर्थन का यह बजट है।

सभापति महोदय, इसी संसद में राम मनोहर लोहिया जी भी थे। वह कम वोट से जीतकर आए थे। यहां मुलायम जी उपस्थित हैं, चुनाव का संचालन कर रहे थे। वह कम वोट से जीत कर आए थे, जो लोग अब वहां बैठते हैं, यहां बैठते थे। जब लोहिया जी शपथ लेने लगे तो ये लोग उन पर ताना मारते थे। ये लोग यहां बैठते थे तो लोहिया जी पर ताना मारा कि कितने वोट से जीते हैं? तब लोहिया

जी ने कहा कि तुम लोग जितने हो उसके दुगुने वोट से जीते हैं। 336 या 340 संख्या थी और वह 1200 वोट से जीते थे। तब इंदिरा गांधी जी वहां बैठती थीं, इसी संसद में राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था – इंदिरा गांधी, तुम यदि हिंदुस्तान की महिलाओं को धुँआ रहित चूल्हा दे दो, तुम यदि हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए बापर्दा पाखाना दे दो तो 25 साल तक तुम्हें कोई प्रधान मंत्री पद से हटा नहीं सकता है।

(1415/MK/SM)

लोहिया जी ने कहा था, संसद की कार्यवाही उठाकर देख लीजिए। मुलायम सिंह जी इस बात को जानते होंगे। इस काम को किसने किया? इस काम को किसी प्रधान मंत्री ने नहीं किया, किसी ने महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा नहीं दिया, किसी ने पर्दे वाला पाखाना नहीं दिया। बहुत अरसे के बाद किसी प्रधान मंत्री ने देश की माताओं और बहनों के लिए धुआं रहित चूल्हा और पर्दे वाला पाखाना दिया, उस व्यक्ति का नाम है नरेन्द्र भाई मोदी। इसलिए मैं कहता हूं, मुलायम सिंह जी सही मानते हैं राम मनोहर लोहिया की बात को, आप लोग भी मानते हैं, यदि राम मनोहर लोहिया की बात सही है तो नरेन्द्र भाई मोदी को 25 साल तक प्रधान मंत्री रहना चाहिए। इसलिए मैं मुलायम सिंह जी को राम मनोहर लोहिया का असली वारिस मानता हूं क्योंकि जब पिछली लोक सभा का सत्रावसान हो रहा था तो समापन भाषण में हमारे मित्र मुलायम सिंह जी, चूंकि ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इसलिए इनसे मेरा दिली प्रेम है, इन्होंने वहीं खड़े होकर कहा था कि नरेन्द्र भाई मोदी ने लोहिया के सपनों को साकार किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी पुन: प्रधान मंत्री बनें। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं, इसीलिए मैं मानता हूं कि आप ही लोहिया के असली वारिस हैं। लेकिन, आज लोहिया के विचार पर चलने वाले लोग भटक गए।

सभापति महोदय, शायद आप नहीं जानते होंगे कि बिहार में हाथी का मेला लगता है। लेकिन, मुलायम सिंह जी के अनुयायियों ने ऐसा किया कि हाथी का एक मेला लखनऊ में भी लगने लगा। यहां एक महानुभाव थे, शायद चले गये, बहुत बोलते हैं। लखनऊ से हाथी खरीदकर जब चलते हैं तो जौनपुर आते-आते फोन आता है कि तुम हाथी के मालिक नहीं रहे, फिर वे लौट जाते हैं। आपके

संघर्ष के प्रभाव से सोनपुर का मेला फिर से इस बार लखनऊ में लगने लगा, लेकिन गरीबों के परिश्रम के पसीने की ताकत ने उस हाथी के मेले को फिर से उजाड़ दिया है और भविष्य में भी उजड़ ही जाएगा।

सभापति महोदय, जब किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, जब किसानों को उत्पादन के लाभकारी मूल्य मिलते हैं, जब प्रधान मंत्री सड़क योजना के द्वारा गांव को खेत से जोड़ते हैं, पावर फार ऑल, जब हर गांव में बिजली लगाने की बात आती है और जब पांच लाख रुपये गरीबों को इलाज कराने के लिए मिलते हैं, मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था, मैंने दो हजार लोगों को कार्ड बांटे, एक बुढ़ी औरत कार्ड लेकर जा रही थी तो लग रहा था कि उसको पांच लाख का ड्राफ्ट मिल गया है, वह कह रही थी कि यह वही जान सकता है, जो गरीब मां का बेटा है। मेरी आंखें भर आईं और मैंने कहा कि धन्य हो नरेन्द्र भाई मोदी ! तुमने गरीबों की आह को समझा है, गरीबों की गरीबी को समझा है। लोग दवा के अभाव दम तोड़ देते थे। आप लोगों को इस बात की प्रशंसा विपक्ष में रहते हुए भी करनी चाहिए कि पहली बार किसी गरीब को लगा है कि कोई सरकार हमारी गरीबी की आह को भी सुनने वाली है, समझने वाली है। यह पहली बार लगा है।

हिन्दुस्तान में जल संरक्षण का काम चल रहा है।

(1420/YSH/AK)

कहां से पैसा आता है? यहां शशि थरूर जी किसान की बात कर रहे थे। सभापति महोदय, शशि थरूर जी जब किसान की बात कर रहे थे तो मैं यहीं बैठा था। बिहार में भिखारी ठाकुर लोकगीत गाना गाने वाले व्यक्ति थे। वे विदेशियों का गीत गाते थे। जब शशि थरूर किसान की बात कर रहे थे तो मुझे लगा एक अंग्रेजी फिल्म में भूमिका करने वाली कोई हिरोइन भिखारी ठाकुर के विदेशिया गीत गा रही है...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Hon. Members, please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): वे जिस लोक सभा में हैं क्या उसमें किसान नहीं हैं? क्या वहां उन्हें किसानों ने नहीं चुना है? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No more interruptions please.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): हम आपको कहां मना कर रहे है कि हमारा जैसा शरीर आप मत बनाइए। यह हमें प्रकृति ने दिया है तो क्या करें? आपको दे दें? यह देने वाली चीज तो है नहीं। वे ऐसा कह रहे हैं तो हम क्या करें? भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया है तो क्या करे? मुलायम सिंह जी से पूछ लीजिए। यह शरीर बड़ी तपस्या से बना है, ऐसे ही नहीं बना है। आप पगड़ी बांध कर आए हैं। आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पगड़ी बांधने वालों का सम्मान करता हूं, लेकिन यह मत समझना कि पगड़ी बांधने वालो से मैं डरता हूं। किसान डरता नहीं है।…(व्यवधान) अब आप बोलने दीजिए।

यह भविष्य में भारत की समृद्धि बढ़ाने वाला बजट है। वर्तमान की चुनौतियों का समाधान करने वाला बजट है। भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उसका समाधान करेगा। अतीत में जो गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने का संकेत इस बजट ने दिया है।

सभापति जी, मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में गांव, गरीब, किसान और सेना के जवान के लिए समर्पित इस सरकार ने देश में एक भरोसा पैदा किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियरा में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो स्मारक बनाया है, उस संचालन मंडल के सदस्य माननीय मुलायम सिंह जी भी हैं। उस स्मारक को जाकर देखने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। वहां का मैं चेयरमैन भी हूं। वहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक अद्भूत तरह की पंचायत की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा के आधार पर एक पंचायत विमर्श केन्द्र बन रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए हम

क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक विमर्श केन्द्र बन रहा है। यह प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके गांव में बनने वाला राष्ट्रीय स्मारक है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस भारत का सपना देखा था, पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी ने जो सपना देखा था। माननीय दत्तोपंत थेंगडी जी ने जो सपना देखा था, इस बजट में वह सपना साकार हो रहा है और यह बजट ऐसे भारत के बनने का संकेत कर रहा है। इस बजट से किसानों के मन में भरोसा पैदा हुआ है। किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक जरूर दोगुनी हो जाएगी। एक किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं कि किसानों की जेब में जब पैसे नहीं रहेंगे, खरीदने की ताकत नहीं होगी तो दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई के बाजारों में रौनक नहीं होगी। इसीलिए इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के प्रस्तुतीकरण में यह बात साफ-साफ है। यहां वित्त राज्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। परिश्रम के पसीने को सूखने से पहले उनके परिश्रम का पारिश्रमिक मिल जाएगा ऐसा उपाय आपने बजट में किया है। परिश्रम के पसीने की कीमत का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। …(व्यवधान)

(1425/RPS/SPR)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please conclude now.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): आप यहां रहते हैं तो कुछ दूसरा करते हैं और वहां रहते हैं तो कुछ दूसरा करते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Your Party has given a long list of hon. Members to speak. A lot of other hon. Members have to speak further.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): इसलिए अपनी बात को पूरा करते हुए, मैं आपसे कह सकता हूं:

> "खेतों को संवारा तो संवरते खुद भी, फसलों को उभारा तो उभरते हुए खुद भी,
> फितरत को निखारा तो निखरते हुए खुद भी, नित्य अपने बनाए हुए सांचों में ढलेंगे,
> हम जिन्दा थे, हम जिन्दा हैं, हम जिन्दा रहेंगे।"

इसीलिए मैं यह कहता हूं और उसे भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने और वित्त मंत्रालय ने पहचाना है कि जो शान से जीता है, वही किसान होता है। इसलिए किसान, जवान, पहलवान – ये सब एक ही जाति के होते हैं और आने वाला भारत, जिस तरीके से भारत की सरकार नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व

में चल रही है, पहली बार यह लग रहा है कि हिन्दुस्तान के साढ़े छ: लाख गांवों में रहने वाले भारत के गांवों की चिन्ता यह सरकार कर रही है, गरीब की चिन्ता कर रही है, किसान की चिन्ता कर रही है। आपने देखा कि 2019 के चुनाव में खेत, खलिहान में रहने वाले किसानों ने लाठी लेकर लोगों को कहा कि चलो, मतदान करो। यह हमारा है, हमारे बीच रहने वाला है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): मैं कन्क्लूड करता हूं।

मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप विरोध करें, to oppose is democracy. इस अपोज़ से ही डेमोक्रेसी को ताकत मिलती है, लेकिन कम से कम किसान के सवाल पर, हिन्दुस्तान के गांव के सवाल पर एकमत रहो। मेरी समझ से यदि ये एकमत रहे तो किसान, गांव के गरीब लोगों को समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। शासन ही सब कुछ करेगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। समाज को भी खड़ा करना पड़ेगा। …(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

भारतीय लोकतंत्र में मैंने जो समझा है, शासन, प्रशासन और समाज मिलकर देश को समृद्धि तक पहुंचा सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1428 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Budget for 2019-2020, on behalf of our Party, TRS. I am also congratulating Shrimati Nirmala Sitharaman *ji* for being the first South Indian woman to present the Union Budget in this august House. निर्मला सीतारमण जी, तमिलनाडु की बेटी हैं और तेलंगाना की बहू हैं। …(व्यवधान) आन्ध्रा प्रदेश की, तेलुगु की बहू हैं। …(व्यवधान) हम लोगों ने यह सोचा था कि अगर इस हाउस में कोई मिनिस्टर है तो वह उन स्टेट्स के लिए ध्यान रखेगा, मगर सदर्न स्टेट्स की डेवपलमेंट के लिए, जिस तरह से सोचा था, उस तरह से इस बजट में प्रॉविजन्स नहीं रख पाए हैं। साथ ही, अगर उनकी स्पीच में देखें तो पहले गवर्नमेंट के विज़न को 10 प्वाइंट्स में बताया गया है। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए उन प्वाइंट्स को मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं।

(1430/RAJ/UB)

उन्होंने विजन ऑफ द डिकेड में 10 पॉइंट्स को रेज किया है। वे देश की इकोनॉमी को फाइव ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। India has a federal structure with distribution of powers between the Central Government and the State Governments. You take a look at how the powers are placed between the Central Government and the State Governments for the benefit of the federal system. यह बहुत महत्वपूर्ण है। देश को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी तरह से साथ में लेना चाहिए। जयंत सिंहा जी आज यहां नहीं हैं। कल जयंत सिन्हा जी ने बजट के मुख्य दो-तीन इश्यूज पर फोकस किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस 'जल शक्ति मंत्रालय' पर किया। यह नया मंत्रालय बना है। हम उसमें एक वर्ड कोट करना चाहते हैं। "This new *Mantralaya* will look at the management of our water resources and water supply in an integrated and holistic manner, and will work with the States to ensure '*Har Ghar Jal*'." उन्होंने इस ऑगस्ट हाउस में बताया है कि हर

घर जल पहुंचाने के लिए स्टेट के साथ काम करेंगे। 'हर घर जल' बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, हम तेलुगू में इसे 'इन्टिन्टिकी नील्लु' बोलते हैं। भारत में पहली बार हर घर जल तेलंगाना स्टेट ने दिया है। उसके उद्घाटन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। दिनांक 7 अगस्त, 2016 की प्रधान मंत्री जी की स्पीच 36 मिनट्स की है। प्रधान मंत्री जी के उस स्पीच को हर पार्टी वालों को सुनने की जरूरत है। उस स्पीच माननीय में प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि दो साल से बना हुआ यह राज्य है। उन्होंने हमारे राज्य के मुख्य मंत्री, चन्द्रशेखर जी के बारे में बताया था कि कभी भी चन्द्रशेखर जी हमारे पास आते हैं तो वह दो चीज के लिए ही बात करते हैं। वह किसानों और गांवों की बात करते हैं। अभी तक भारत में किसी राज्य ने यह काम नहीं किया है। हम लोग पहली बार घर-घर में पानी पहुंचाने के लिए 'मिशन भगीरथ' को उस समय आगे लेकर गए। उसका उद्घाटन हुआ था। जो कम्पलीट हुआ। यह पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। 'हर घर जल' के बारे में जो बताया गया है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने तेलंगाना में ऑलरेडी पानी दे दिया है। ऑलरेडी, हम लोग यह कार्यक्रम ले चुके हैं। अभी कम से कम 23,968 हैबिटेशंस में पानी दे रहे हैं। हम हर घर में फिल्टर पानी दे रहे हैं। हम रिवर से पानी लिफ्ट करके, उसे फिल्टर करके दे रहे हैं। हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है। यह पूरे हाउस के सुनने के लिए है। हम लोगों ने हर घर में जल पहुंचाने के लिए एक लाख पांच हजार किलोमीटर की पाइप लाइन बिछा दी है। इस तरह से हमने हर घर में पानी देना शुरू भी कर दिया है। (1435/IND/KMR)

मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा यह प्रोजेक्ट देखने के बाद यही पूरा प्रोजेक्ट सारे भारत में लगा रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। नीति आयोग ने स्टडी करके इस प्रोजेक्ट के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की अनुशंसा भी की है। हम लोगों ने सोचा था कि इस बजट में तेलंगाना के साथ जरूर न्याय किया जाएगा और कुछ पैसा दिया जाएगा। यंग लीडर अनुराग जी सदन में बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कम से कम आप लोग जो प्रोजेक्ट देश में लगाने के लिए सोच रहे हैं, वह प्रोजेक्ट ऑलरेडी तेलंगाना में लगा हुआ है। उस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट ट्रीट कीजिए और उसको फंड देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा मुद्दा किसानों के लिए छह

हजार रुपये का है। हमारे दोस्त ने भी यही बात कही है। किसान के खाते में छ: हजार रुपये अभी तक नहीं दिए हैं। भारतवर्ष में हमारी पहली राज्य सरकार है, जिसने 10 हजार रुपये प्रति एकड़ हर किसान को दिए हैं। इस योजना का नाम 'रायतु बंधु' रखा है। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सदन में महाराष्ट्र के सांसद भी बैठे हैं। महाराष्ट्र के 40 बार्डर विलेजेज के किसान बोल रहे हैं कि हमारे गांवों को तेलंगाना में मिला दीजिए क्योंकि यहां पानी भी मिल रहा है और हर किसान को दस हजार रुपये भी मिल रहे हैं। 'आरोग्य श्री' योजना है और इसका कवरेज 'आयुष्मान भारत' से ज्यादा है। 'ऋतु बीमा' योजना को भी हमने डिफरेंट वे में लागू किया है। सबसे महत्वपूर्ण 'कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई' प्रोजेक्ट की भी बात है। हैदराबाद बहुत हाइट पर है। वहां मल्टीपल लिफ्टिंग करके गोदावरी रिवर को 800 मीटर ऊपर लाकर तेलंगाना के किसानों को पानी दे रहे हैं। उसके साथ-साथ 'कालेश्वरम' के प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट की है और केंद्र ने भी स्टडी की है, इसे जरूर कंसिडर करें। स्टेट और सैंटर, दोनों यदि साथ मिलकर चलें तभी डेवलपमेंट में फाइव ट्रिलियन करने का चांस रहेगा। उसके लिए स्पेशल कंसिड्रेशन करना चाहिए। इसके साथ-साथ जीडीपी देखें तो हम सबसे अग्रणी हैं। पूरे भारत देश में तेलंगाना 14.9 परसेंट जीडीपी के मामले में सबसे आगे है। कंट्री का एवरेज यदि 6.8 परसेंट है, तो हम डबल जीडीपी में चल रहे हैं। उसके लिए स्पेशल कंसीड्रेशन करना चाहिए। जब हमारा स्टेट बन गया था, उस समय रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉयफरकेशन एक्ट में काफी चीजें रेलवे प्रोजेक्ट, बाय्याराम स्टील प्लांट, कोच फैक्टरी आदि कई चीजें हमें देनी थीं, इसे भी कंसिडर किया जाए। इसी तरह बालापुर रंगा रेड्डी जिला है। यहां भी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है। हम लोगों के राज्य के लिए प्रधान मंत्री के 7 तारीख के भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं। सब लोग यू ट्यूब में स्पीच देख लीजिए। वह सब मैं आपको सुनाना चाहता था। हमारे पास समय कम है। उसमें प्रधान मंत्री जी ने अड्रेस किया है कि यह स्टेट बहुत आगे बढ़ेगा और यह स्टेट हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि बजट में हमारे लिए प्रोविजन नहीं है, उसे भी देख लेना चाहिए। मैं रेलवे के लिए, कोच फैक्टरी के लिए, फोर लेन के प्रोजेक्ट आदि को इनक्लूड करने के लिए आपके माध्यम से सरकार से बोल रहा हूं। (इति)

(1440/VB/SNT)

1440 बजे

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए, इसे मैं बजट नहीं कहूँगा, बही-खाते पर बोलने का अवसर आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पहली बार देश की कमाई का बही-खाता, लेखा-जोखा पेश करके देश को गौरव की अनुभूति करायी है।

जब से बजट पर चर्चा हो रही है, विपक्ष की तरफ से हमेशा एक सवाल रहता है कि फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी, जो लक्ष्य हैं, वे कैसे पूरे होंगे। विपक्ष यह भूल गया है कि अगर 'मोदी है, तो मुमकिन है,' यह बात अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में है। अगर दुनिया में कोई भी संकट आता है, अगर कोई बात आती है, तो विश्व के लोग आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि अगर इसका समाधान कोई कर सकता है, तो केवल भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष के लोग स्पष्ट रूप से लिख लें कि अब देश में कोई भी विषय असंभव नहीं है। …(व्यवधान) पुलवामा का जवाब अगर किसी ने दिया है, तो हमने दिया है। …(व्यवधान) आप ठीक कह रहे हैं। …(व्यवधान)

आज़ादी के बाद परम् पूज्य महात्मा गांधी जी ने कल्पना की कि इस देश को कांग्रेस से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यह 70 वर्षों तक नहीं हुआ। जब गुजरात का एक बेटा, एक नेता पैदा हुआ, यह तभी संभव हुआ। …(व्यवधान) कांग्रेस मुक्त हो गया। इसलिए 'मोदी है, तो मुमकिन है।' यह बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। …(व्यवधान)

महोदय, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। मैं बजट के बहुत अंदर न जाकर, उसके डेटा पर नहीं बोलना चाहता हूँ। …(व्यवधान) अभी भी वक्त है, आप लोग समझ लीजिए। आपकी संख्या घटती जा रही है। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): No interruptions please. Hon. Member, you please address the Chair.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, जब इस देश में बैंकों पर संकट आए और जब सरकार बदली, तो बैंकों के जितने डिफॉल्टर्स थे, जिन्होंने पैसे ले लिये थे और नहीं दे रहे थे, उनकी एक सूची बनायी। ऐसे लोग, जो पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, उनको बट्टे खाते में डाल दिया गया। विपक्ष ने इसका दुष्प्रचार करना शुरू किया कि सरकार ने उस पैसे को देश के पूंजीपतियों के पास छोड़ दिया। जिसको व्यापार का क-ख-ग का ज्ञान है, जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, वह समझता है कि बट्टे खाते में डाले गये पैसे को छोड़ा नहीं गया है, उसकी सूची बनायी गई है और उनको चिह्नित किया गया ताकि देश के बैंकों के ऐसे डिफॉल्टर्स को, देश के चोरों को देश के बैंकों से दोबारा पैसे न मिलने पाएँ।

आज मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि नयी सरकार के प्रयास से उस पैसे में से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकवरी इस सरकार ने की है। यह तब मुमकिन हुआ जब इस देश में मोदी की सरकार आयी। इसलिए 'मोदी है, तो मुमकिन है।'

(1445/VB/GM)

देश में 9.60 करोड़ शौचालय बने। ये नामदार लोग उस शौचालय की कीमत को नहीं समझ सकते हैं, उस शौचालय की ताकत को नहीं समझ सकते हैं कि यह नारी-गरिमा और नारी-सम्मान से जुड़ा हुआ कितना महत्त्वपूर्ण विषय है। हम लोग गांव, गरीब किसान से चुनकर आते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक गरीब की बेटी ब्याह के बाद अपने ससुराल पहुँचती है, जो पढ़ी-लिखी नहीं है, गरीब है, अशिक्षित है, तो उसको यह चिन्ता नहीं होती है कि उसे सोने के लिए कौन-सा कमरा दिया जाएगा, रहने की कौन-सी जगह मिलेगी, खाने के लिए कौन-सी चीज दी जाएगी? उसके मन में केवल यह डर और पीड़ा रहती है कि अगर मुझको शौच आएगी, तो मैं किससे कहूँगी। अभी नई-नई घर में आई हूँ, न तो मैं किसी को पहचानती हूँ, कौन रिश्तेदार है, कौन सास है, कौन चाची है, कौन नानी है, कौन मामी है, कौन काकी है, वह नहीं जानती है। लेकिन उसको इस बात का डर सताता है। इसलिए उसके मन से इस भय को निकालने और सम्मान से जीने का अगर किसी ने अवसर दिया, तो वह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिला।

यहाँ पर हमारे टीएमसी के साथी कह रहे थे कि नारी से नारायणी कैसे बनेगी, यह कैसे संभव है। मैं किसी और की बात नहीं कहता हूँ, मैं स्वयं अपनी बात कहता हूँ। मेरी माता जी ने उपले बेचकर हमें पाला है, तो उनका जो सपना थे, उनका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था कि महल हो, गाड़ी हो। यदि उनका कोई सपना था, तो जीवन की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वे कैसे पूरी हों, ये थीं। मूलभूत आवश्यकता के लिए एक घर हो, मूलभूत आवश्यकता के लिए शौचालय हो, मूलभूत आवश्यकता के लिए स्वच्छ ईंधन हो और जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए दर-दर भटकना न पड़े, दर-दर भीख न माँगनी पड़े।

मैं अपनी बात कहता हूँ। मैंने बचपन में गरीबी में जीवन जीया है। जब एक छोटा-सा ऑपरेशन कराने की बात आई, तो अपनी माता जी को मैंने देखा कि उन्होंने कैसे दर-दर भटककर लोगों से चन्दा माँगा, अगर वह आज जीवित होतीं, तो वह मोदी जी को बधाई देतीं, उनको आशीर्वाद देतीं कि अब किसी माँ को अपने बेटे के इलाज के लिए, अपने परिवार के इलाज के लिए दर-दर जाकर चन्दा नहीं माँगना पड़ेगा।

महोदय, आप कहें, तो मैं अपना भाषण ले कर दूँ। इतनी जल्दी मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया हूँ।

महोदय, एक नहीं अनेक विषय हैं। लोगों ने सवाल उठाए कि सरकार ने एससी, एसटी के बजट में कटौती कर दी है। लोगों ने ठीक से नहीं देखा। एससी, एसटी के बजट में सरकार ने बढ़ोतरी की है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की है। महोदय, मैं समझ रहा हूँ कि आप समय कम देंगे।

मैं इस सदन का ध्यान एक विशेष बात पर ले जाना चाहता हूँ। हम सभी यह जानते हैं कि देश में बड़े स्तर पर संविदाकर्मी रखे जाते हैं। जब वर्ष 1992 में इस देश में उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, तो उस समय से इस देश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने की बात आई। मैं पूरे सदन का सहयोग चाहूँगा, आज पूरे देश का युवा आउटसोर्सिंग के नाम पर प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा चलने वाली जो कम्पनियाँ हैं, वे युवाओं का शोषण कर रही हैं। मैं इस बजट के

माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि अब समय आ गया है कि आउटसोर्सिंग पर देश में एक राष्ट्रीय नीति बने ताकि देश के युवाओं के शोषण को रोका जा सके।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स चिह्नित किये थे। जो पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियों के कारण अनेक समस्याएँ पैदा हो गई थीं, उन 115 जिलों को चिह्नित करके उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया।

(1450/PC/RK)

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि देश भर में एक नहीं, अनेक जिले हैं, जो उद्योगविहीन जिले हैं। वहां के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैं सरकार से, वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाए। चिन्हित कर के वहां के उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडेक्ट' का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे थोड़ी सहूलियत और राहत तो हुई है, लेकिन आज भी लोग उद्योग, व्यापार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत सरकार ने जिस तरह पूरे देश में शौचालय, आवास और बिजली देने का काम किया है, उसी प्रकार सरकार ने सब जिलों में पाइपलाइन से स्वच्छ पानी देने की योजना बनाई है। इसके लिए देश भर में 256 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 1538 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जो डार्क-ज़ोन में चले गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस पर जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे जिलों, ऐसे ब्लॉकों को हम लोग स्वच्छ पानी दे पाएंगे।

मैं पुन: मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि यह बजट सर्वव्यापी है, स्र्वस्पर्शी है और समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, इस देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो इस बजट से अछूता रहा हो। इसलिए, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए और इस बात का आभार व्यक्त करते हुए कि जिन बिंदुओं को हम लोगों ने उठाया है, निश्चित रूप से सरकार इन बिंदुओं पर विचार करेगी। विपक्ष

के पास अभी भी मौका है, ज़रा सा चिंतन कर ले, नहीं तो 'मोदी है, तो मुमकिन है' और हमें लगता है कि अगली बार हम लोग वहां तक आएंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Before the hon. Member Shri Ramchandra Paswan speaks, I have to make one announcement. Hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so. It will be treated as part of the proceedings of the House.

1453 बजे

श्री राम चन्द्र पासवान (समस्तीपुर) : सभापति जी, आपके माध्यम से मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस आम बजट के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। आज पूरे देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जो वर्ग आज इस सरकार की सराहना न करे, किसी जगह के लोग नहीं हैं, जो इस बजट को अपना बजट न मानते हों। आज इस महापंचायत में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि जो दूर-दराज का, देहात का एरिया था, मेरा लोक सभा क्षेत्र भी काफी इंटीरियर इलाके में पड़ता है। वहां आज से नहीं, वर्ष 1999 में मैं जब जीता था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे। मेरा जो क्षेत्र है, वह मिथिलांचल का क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र है। मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र में जो समस्याएं थीं, आज इस सरकार के माध्यम से काफी समस्याओं का समाधान हुआ है।

(1455/SPS/RC)

वर्ष 1997 में हमारी लोक जन शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे। उन्होंने रेल मंत्री के रूप में काफी योजनाएं देने का काम किया था। हम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को और पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इनके समय में कार्य हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन जितनी तेजी से होना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से यह जो बजट है, किसानों के लिए है और महिलाओं को भी इस बजट में प्रोत्साहित किया गया है। आज महिलाओं के खाते में जन धन योजना के तहत पांच हजार रुपये न रहने पर भी उसमें से पैसे निकालने का प्रावधान किया गया है और एक लाख रुपये लोन देने का भी प्रावधान किया गया है। जो महिलाएं वंचित थीं, जो घरों में बेरोजगारों की तरह बैठी हुई थीं, आज उन महिलाओं को लग रहा है कि इस देश में हमारे लिए भी कोई सोचने वाला है और कोई सरकार है। वह सरकार नरेन्द्र मोदी जी की है। हमारे बीच में युवा हैं और उन युवाओं की संख्या काफी अधिक है। इस बजट के माध्यम से उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, फिर भी युवाओं के लिए सोचने की जरूरत है। आज हमें काफी खुशी

हो रही है और हमें एन.डी.ए. सरकार पर काफी गर्व है। जो बिजली की समस्या थी, यह समस्या काफी हद तक हमारे बिहार में सॉल्व हो चुकी है। लगभग हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। ऐसा कोई गांव नहीं है, जिस गांव में गैस नहीं पहुंची हो। हमारी सरकार ने योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव में गैस पहुंचाने का काम किया है। हम उस गांव से आते हैं, जो गांव काफी गरीबी से गुजरने वाला था। आज भी है, लेकिन उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। जब हमारी मां, हमारी बहन चूल्हा फूंकने का काम करती थी तो उस समय उसको नानी याद आती थी, लेकिन आज उसको नानी याद नहीं आ रही है, आज तो सिर्फ नरेन्द्र मोदी जी की सरकार याद आ रही है, जिनके माध्यम से उनको गैस का कनेक्शन मिला है। आज उनके चूल्हा फूंकने में कमी हुई है। जो सुलभ शौचालय हैं, गांव में कोई सोच नहीं सकता था, कोई सुनकर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन उन शौचालयों को बनवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम इनको धन्यवाद देते हैं। ये बधाई के पात्र हैं। उन लोगों की बात को इस महापंचायत में रखने के लिए हम भी जीतकर आए हैं, हमें भी गर्व होता है। इस समय हम बोल रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग सुनकर प्रसन्न हो रहे होंगे कि जिसे हमने वोट दिया है, वह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जिसको वोट दिया है, वह नेता हमारे लिए सोचने का काम कर रहा है। जो जल-नल योजना है, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। जल-नल योजना देश के लिए आई। खासकर बिहार के हमारे क्षेत्र में नलकों का पानी सूख चुका है और बहुत लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।

(1500/KDS/SNB)

वे पानी की किल्लत में हैं। अत: हम कहना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर सरकार ने इस कार्य को करने की योजना बनाई है, लेकिन उसमें और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां नल-जल के बिना लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं।

सभापति महोदय, हम अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। हमें भी बोलने का कुछ अवसर दिया जाए। आप भी पुराने सदस्य हैं, हम भी पुराने हैं। हम अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहते हैं। सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज किसानों के बीच में कोई पार्टी, कोई फिलिंग, कोई मतभेद नहीं है। आज किसान को सरकार पर पूरा भरोसा है और हमें लगता है कि जिस बहुमत से आज यह सरकार काम कर रही है, जिस बहुमत से यह सरकार जीतकर आई है, अगली बार जब सरकार जीतेगी तो पूरे का पूरा उधर का भी सफाया हो जाएगा। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत जो गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल में दवाई के अभाव में मर जाते थे, आज उनके इलाज के लिए सरकार ने 5 लाख रुपये देने की व्यवस्था की है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम आपके माध्यम से बहुत कम समय में अपनी बात को रखेंगे।

सभापति महोदय, जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, उस समय सकरी हसन रेल लाइन का काम शुरू हुआ। लेकिन अभी तक काम अधूरा है, इसलिए हम चाहेंगे कि यह जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हम गडकरी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इनकी जो बहुत सारी हाइवे संबंधी योजनाएं हैं, उनको जल्द पूरा कराया जाए। इसके बाद प्रधान मंत्री सड़क योजना का कार्य है, जो काफी अधूरा पड़ा हुआ है, उस कार्य को भी हमारी सरकार जल्द से जल्द पूरा कराएगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। आज हम काफी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से आपने कम समय दिया, लेकिन फिर भी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यह सदन है और सदन में एक-एक सेकेण्ड का बहुत महत्व है। धन्यवाद।

(इति)

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri A. Ganeshamurthi in Tamil,
please see the Supplement. (PP 364 to 364D)}

* Laid on the Table. Original in Tamil.

*SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI):

* Laid on the Table.

*SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM):

*Laid on the Table.

***डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** स्पीकर महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने की अनुमति प्रदान की।

2019 के लोक सभा चुनाव में फिर एक बार हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जो प्रचंड जनादेश मिला है, वह यही बताता है कि इस देश के 130 करोड़ नागरिकों ने नरेन्द्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल के निर्णयों को अपनी स्वीकृति दी है। यह जनादेश यह भी प्रतिपादन करता है कि मोदी जी ने 'नए भारत निर्माण' की जो नींव रथी थी, उस पर बुलंद एवं भारत की मज़बूत इमारत बनाने के लिए जनता ने अपनी मुहर लगाई है और स्वीकृति भी दी है। इस जनादेश की वजह से देश का लोकतंत्र और भी मज़बूत हुआ है और नरेन्द्र मोदी जी एक 'जन-नायक' के रूप में स्वीकृत हुए हैं।

यह बजट नए भारत के निर्माण के लिए एक मज़बूत नींव की तरह है, इसलिए मैं भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तथा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी बधाई देता हूं। मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी है। पूरे विश्व में 11वीं इकोनॉमी से छठे पायदान पर भारत की अर्थव्यवस्था उभरकर आई है।

स्पीकर महोदय, वर्ष 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हुई है। पहले के 55 सालों में और मोदी सरकार के मात्र 55 माह में अर्थव्यवस्था डबल हुई है। यही मोदी सरकार की सफल अर्थव्यवस्था का सूचकांक है। बड़े सपने देखना, उनको साकार करने के लिए कठोर परिश्रम और शक्ति रखना मोदी सरकार की पहचान है। इसीलिए, मोदी जी ने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सपना रखा है। मुझे मोदी जी तथा सरकार पर पूरा भरोसा है कि हम वर्ष 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

---

* Laid on the Table.

स्पीकर महोदय, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस बजट में किए गए ठोस निर्णयों की मैं सराहना करता हूं। देश में कनेक्टिविटी के लिए अच्छे निर्णय लिए गए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को बल देते हुए उसे तेजी से बढ़ाना। 97 परसेंट कनेक्टिविटी होगी। इन्डस्ट्रीयल कोरीडोर, सागरमाला, जलमार्ग, नेशनल हाईवे, पोर्ट्स, उडान योजना के साथ कनेक्टिविटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। मेट्रो रेल, नेशनल हाईवे, अगले 5 सालों में एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण। रेलवे में 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उसमें पीपीपी भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। पावर कनेक्टिविटी, वन नेशन वन ग्रिड के तहत हर जगह को बिजली पहुंचाई जाएगी। सभी नागरिकों को वर्ष 2022 तक घर मिलेगा और अफोर्डेबल हाउसेस का निर्माण करके सब को आशियाना मिलेगा। एमएसएमई सैक्टर को बल मिलेगा और हर छोटे उद्योग करने वाले को इन्टरेस्ट सब्वेन्शन स्कीम के साथ न्यूनतम एक करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। प्रधान मंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम देश निर्माण में सहयोग देने वाले स्वैच्छिक संगठनों को बाजार से स्टॉक मार्केट के जरिए पूंजी की सुविधा मिलेगी। एफडीआई के लिए बढ़ावा मिलेगा। पहले से एफडीआई में छ: परसेंट वृद्धि हुई है। एविएशन, मीडिया इन्श्योरेंस सैक्टर में एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा। सिंगल बांड में भी एफडीआई छूट दी जाएगी। भारत में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। स्पेस, पीएसयू, एनएफआईएफ को इसरो से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी के रास्ते चलते गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए जाएंगे। हर घर में उज्ज्वला के तहत गैस दी जाएगी। हर घर में शौचालय, प्रधान मंत्री आवास के तहत सभी को घर मिलेगा। 1.95 करोड़ आवासों का निर्माण होगा। सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली होगी। जल शक्ति को तहत हर घर जल पहुंचाया जाएगा। अन्नदाता से ऊर्जादाता योजना के तहत किसान की आय दोगुना करने पर बल देना।

महोदय, जहां तक एससी/एसटी का सवाल है, उन वर्गों को अम्ब्रेला के नीचे कवर कर लिया और अनुसूचित जाति के बजट में 9 परसेंट की वृद्धि की गई है। एससी/एसटी युवाओं को

स्टैंड-अप योजना से लाभ पहुंचाने का काम किया गया है और स्टैंड-अप योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि एससी/एसटी युवा, खास कर महिला उद्यमियों को बैंक से दस हजार रुपये की राशि दी जाए और बिना कोलेट्रल कम ब्याज पर लोन देने की सुविधा दी जाए। शिक्षा में सुधार के लिए तथा नई शिक्षा नीति के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह बजट फाइव ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का फाउंडेशन रखने वाला है। नए भारत के निर्माण के लिए यह बजट आधारशिला रखेगा।

महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

*SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR):

* Laid on the Table.

1503 बजे (श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): धन्यवाद सभापति महोदय। मोदी सरकार का यह बजट देश को ऊंची उड़ान देने वाला बजट है। हमारी वित्त मंत्री, जो देश की पहली वित्त मंत्री रही हैं, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उससे पूरे देश में एक विश्वास और आकांक्षा की उम्मीद जगी है। जिस तरीके से देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, उस विश्वास पर खरा उतरने वाला यह बजट है। बजट में आय और व्यय, इन दोनों का प्रावधान होता है। धन कहां से आया, इसका भी महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व है कि धन किस पर खर्च हुआ, धन किसको दिया गया? मैं यह कह सकता हूं कि आजाद भारत में इस बजट के माध्यम से यह तय हो चुका है कि यह मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। गरीबों के सपने साकार करने के लिए इस बजट में सभी तरह के प्रावधान किए गए हैं। यह सदन साक्षी है कि गांव में रहने वाली वे महिलाएं, जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती थीं, उन मां-बहनों को किस दर्द और पीड़ा को झेलना पड़ता था।

(1505/MM/RU)

सात करोड़ एलपीजी के गैस कनेक्शन दिए जाना, यह देश के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आने वाले समय में आठ करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में देने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। यह देश में बहुत बड़ा अभियान ग्रामीण मां-बहनों के लिए, गरीब परिवार की माता-बहनों के लिए मोदी जी द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा अभियान है।

सभापति महोदया, मोदी सरकार ने गरीबों के घर के सपने को साकार किया है। गांव में रहने वाले गरीब को पक्का घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसके पहले की सरकारें क्या देती थीं और कैसे घर बनता थाा, पूरा सदन इस बात का गवाह है। पहले इंदिरा आवास के नाम पर घर दिए जाते थे, लेकिन राशि बहुत कम होती थी। वह बना हुआ घर एक बारिश में ढह जाता था। एक आंधी आती थी और घर के टिन उड़ा कर ले जाती थी। लेकिन आज मोदी सरकार ने डेढ़ लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्र में घर निर्माण को देकर गरीब के पक्के घर के सपने को साकार किया है। आज एक धनवान व्यक्ति उस घर की कीमत नहीं समझ सकता है। उस घर की क्या अहमियत है, यह कच्ची

झोंपड़ी में रहने वाले गरीब से पूछिए। वह गरीब जिसके पास घर बनाने का पैसा नहीं है। बरसात जब आती थी तो बाजार से प्लास्टिक की पन्नी खरीदकर बरसात से बचने के लिए अपने घर पर डाल देता था। आज ऐसे करोड़ों गरीबों को पक्का घर देकर उनके आंगन में खुशहाली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना भारी समर्थन मिलने के पीछे जो कारण हैं, विगत पांच सालों में सरकार ने सामाजिक सरोकार के जो काम इस देश में किए हैं। गरीब तक अपनी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का एक सिस्टम डेवलप किया है।

सभापति महोदया, इस देश ने वह भी देखा है जब दिल्ली से गरीबों के लिए पेंशन जाती थी और पेंशन गांव के सचिव या सरपंच के हाथ से मेनुअल जब बंटती थी तो गरीब के तीन सौ रुपये में से भी सौ रुपये खा लिए जाते थे। लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसा भारत सरकार से पहुंच रहा है, उसमें बीच के बिचौलिए खत्म हो गए हैं, बीच के दलाल खत्म हो गए हैं, क्योंकि सीधा पैसा गरीब की जेब में जाने का सिस्टम मोदी सरकार ने डेवलप किया है। इसके माध्यम से आज गरीब इस बात पर विश्वास करता है कि दिल्ली में कोई बैठा है जो हमारा रखवाला है। दिल्ली में जो बैठा है, वह हमारे धन पर किसी को डाका डालने नहीं देगा।

सभापति महोदया, सामाजिक जीवन में, समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आज तक जितनी सरकारें इस देश में बनी हैं और जितनी भी सरकारों ने प्रयोग किए होंगे, वे अच्छे रहे होंगे। लेकिन मोदी सरकार ने सामाजिक जीवन स्तर, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोशिशें की हैं। श्रम योगी पेंशन योजना- वह श्रमिक, जो मेहनत के बल पर अपना परिवार पालता है, उस श्रमिक से छोटी सी राशि लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये महीना आजीवन पेंशन देने की योजना नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में लाँच की है।

(1510/SJN/NKL)

आज तक लगभग 30 लाख श्रमिक इस योजना से जुड़ चुके हैं। आज देश भर के किसानों को छः हजार रुपये किसान सम्मान निधि दी गई है। मोदी जी ने सीमांत किसानों के लिए भी 'किसान पेंशन योजना' लांच की है, इसमें 40 वर्ष तक की आयु के किसान उस किसान पेंशन योजना से

जुड़ेंगे। जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, तो उन्हें भी जीवन भर तीन हजार रुपये महीने मिलेंगे। यह 'किसान पेंशन योजना' भारत सरकार ने लांच की है। यही तो सामाजिक सरोकार है। यही तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश है।

सभापति महोदया, किसान-मजदूर से लेकर छोटे व्यापारी तक की भी चिंता की गई है। मोदी सरकार ने जिस व्यापारी का डेढ़ करोड़ रुपये महीने तक का टर्नओवर है, उस व्यापारी को 'कर्मयोगी पेंशन योजना' के तहत सीधे लाभ दिए जाने का प्रावधान किया है। जल शक्ति विभाग का गठन करके भूमिगत जल भंडारण कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आज जमीन में पानी कम डिपाजिट हो रहा है और विद्ड्रॉल अधिक हो रहा है।

सभापति महोदया, मैं अभी तो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : चौहान साहब, आपको दस मिनट बोलने का समय दिया गया था, लेकिन अब आपको बोलते हुए 12-14 मिनट हो गए हैं।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा) : सभापति महोदया, मुझे थोड़ा-सा समय और दीजिए।

माननीय सभापति : आप प्लीज वाइंड अप कर दीजिए। बाकी अन्य लोगों को भी बोलना है। इसलिए आप वाइंड अप कर दीजिए।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा) : सभापति महोदया, जल शक्ति विभाग का गठन करके जल संचय के लिए एक एक्शन प्लान बनाना भी इस सरकार ने तय किया है। मोदी जी ने 'मन की बात' में अपनी तरफ से सबसे पहले देश को एक संदेश दिया कि आइए, आने वाले भविष्य में जल संकट से देश को बचाने के लिए हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसमें समाज को जोड़ने के लिए आह्वान किया है। उसी के साथ घर-घर तक जल पहुंचाने के लिए भी उन्होंने इस योजना में प्रोविज़न किया है। मैं वित्त मंत्री जी और देश के प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाइयां देता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने बधाई दे दी है।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा) : सभापति महोदय, विपक्ष अकारण अच्छे कामों की भी आलोचना करता है। मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। देश की खातिर जो अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए पूरे सदन को एक होकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर देश हित में अपना समर्थन और सहयोग देना चाहिए। आज यह देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था है। आज हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से 6वें पायदान पर आ गए हैं।...(व्यवधान) यह सरकार की उपलब्धियां हैं। मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

(इति)

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):**

* Laid on the Table.

***श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई) (आनंद):**

* Laid on the Table.

1513 hours

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity. Before I comment on the Budget 2019, I wish to congratulate, through you, Shrimati Nirmala Sitharaman for being the first full-time lady Finance Minister.

More than a battle of genders, a woman, at the helm of finance, should also, hopefully, help in balancing the home budgets of the poor who continue to face deficits of far greater proportions, and having no recourse to fulfil their empty stomachs even with the borrowed funds that the Governments are able to access on a need basis.

Madam Chairperson, we all know that Budget is essentially a statement of income and expenditure. However, over the years, it also reflects a statement of intent and direction of change. A strong mandate – like the Ruling Benches got this year – further provides that added comfort and confidence to take measures for a much faster trajectory of growth.

When I think of some of the pathbreaking Budgets in the last three decades, three Budgets come to my mind. The first on the list is the historic Budget presented by Dr. Manmohan Singh*ji* in 1991. It changed India for ever by dismantling avoidable controls and lowering of tariffs.

The next on my list is what is still known as the Dream Budget, presented by Mr. Chidambaram in 1997. No one expected that the tax rates would be lowered so drastically and yet the revenues would be increased.

(1515/SRG/GG)

Lastly, the Budget of 2004 that made our country take huge strides to transform health, education and social justice. All these Budgets came from coalition Governments and they were all followed by long periods of high growth and the periods that are now acknowledged as the golden periods of Indian economy.

Budget 2019-20 will be dealing with nearly Rs. 28 lakh crore of money. Seen in parts, there are bound to be areas that please a section here or there. Politics is also an art of the possible and lately of projection. I do not wish to find faults with individual doles here or there as long as they are backed by funds and are finally delivered to the promised sections.

My concerns are at three levels. The first is a series of announcements that are not backed by fund allocations. The most serious concern is the outlay on Defence and more particularly on Defence acquisitions. This will perhaps be the first time that a Finance Minister has failed to make an announcement on the issues of Defence in the Budget Speech. I would have liked to believe that her immediately previous position as Minister, In-charge of Defence, would have given her enough insights into the need for quick upgradation of the Defence capabilities. The total outlay of Defence capital is up by a meagre 10 per cent. Adjusted for inflation, it means that we are spending less than even last year even while the threat perception presented to the nation just a few months back was an entirely different story.

Expenditure in Animal Husbandry and Dairying is lower than last year by about 11 per cent. This is when we are talking of increasing and doubling farmers' income in three years. Expenditure in MSMEs, another high priority area, is up by a meagre seven per cent. No wonder jobs remain non-existent. Expenditure in the power sector is up by less than two per cent. Expenditure in Electronics and IT Ministry, where we are talking of `Digital India', is up by just four per cent.

It is evident that with the slowing down of the economy and falling revenues, people of India are merely being given headlines which are likely to be replaced by new headlines in future, even while the economy is crying out for help.

Let me now come to the second area, which concerns all States and where I feel the Central Government is literally committing a fraud on the States. As per the 14th Finance Commission, States are entitled to a share of 42 per cent of the Central Taxes. Taxes collected as surcharges and cesses are not meant to be a part of the divisible pool. For decades, a delicate balance has been maintained in collecting money for exceptional needs as surcharges and cesses. This balance has been seriously breached and in recent years, this Budget has taken it to a new level. The entire increase in tax on petroleum and diesel this year will go to the Centre alone. This has been budgeted to give a revenue of Rs. 1,27,019 crore in 2019-20. The massive increase in surcharge on the super rich will go to the Centre alone.

(1520/KKD/KN)

From a meagre Rs. 15,000 crore of surcharges on personal income in 2017-18, the Centre is hoping to collect a mammoth Rs. 61,000 crore in 2019-20. The figures in the case of corporate tax are up from Rs. 37,000 crore in 2017-18 to Rs. 1,09,000 crore. In the eyes of the States, the Central Government is their superrich. The Budget proposes to tax them at 42 per cent and the share of the States is being reduced from the promised 42 per cent to almost 30 per cent.

So, let me clarify that these are not doles from the Centre. They are very much legitimate State taxes, which are collected centrally, and meant to be given to the States as per healthy conventions established over the years. If all this money is going to be kept by the Centre, the deficits of the States are going to grow higher.

I come from a State where the fiscal situation is extremely precarious. The Budget is making our life doubly difficult. I suggest that instead of raising money as surcharges and cesses, it should be collected as the main tax itself. This would make, at least, Rs. 2 lakh crore available for sharing with the States.

The Budget wishes to spend a never before amount of Rs. 100 lakh core on infrastructure in the next five years. Available resources are being shown as close to Rs. 1 lakh and Rs. 1.5 lakh crore *per annum*. Rest of the money of more than Rs. 90 lakh crore is meant to come from sources that are unknown at this stage.

The existing ratio of external borrowings of five per cent is planned to be tripled. At another front, the RBI reserves are proposed to be depleted even while there is bickering at the top echelons of the Bank on the prudence of parting with the money.

The disinvestment target of more than Rs. 1,00,000 crore is proposed as if everything is for ready sale.

We are now delicately placed where GDP has slowed down to 5.8 per cent in the previous quarter. Exports are stagnant for five years in real terms. Unemployment rate has doubled and investment climate is falling. We are facing an unprecedented volatility in global situations.

Our GST could be in the Guinness Book of records to be the most amended law in the last two years. We have enough indicators of the economy faltering. We have undone everything that the three best Budgets, I mentioned, tried to do. We are pushing the dirt of the Central fiscal deficit to the doorsteps of our States, and these are hardly the signs of a good Budget.

Madam, I am going to conclude, now. Headlines do not produce results by themselves. They have to be backed by actions that make everyone take note of India as a land of opportunity and efficient delivery. I would say that the Budget has failed to rise to the challenge despite no pressure from coalition politics.

With these words, I sit down with my fingers crossed and thank you for giving me the time to speak.

(ends)

***श्री अजय कुमार (खीरी):** महोदय, मैं 2019-20 के बजट का समर्थन करते हुए अपने लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी के लिए निम्नलिखित माँग करता हूँ:

1. प्रस्तावित नई रेल लाइन पलिया-निघासन-बेलरायां का शीघ्र सर्वे कराकर निर्माण कराया जाए,

2. प्रस्तावित नई हेरिटेज ट्रेन प्रारम्भ की जाए,

3. नेशनल हाइवे नम्बर 730 और 731 का शीघ्र निर्माण पूरा कराकर एसएच बेलरायां-पनवारी मार्ग (एसएच न. 21) को नेशनल हाइवे का दर्जा देकर उक्त मार्ग पर पचपेड़ी घाट के पुल का निर्माण कराया जाए,

4. प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और सौ-सौ बेड के दो अस्पताल, जिनको निघासन व पलिया में बनाने का प्रस्ताव किया जाए और शीघ्र बजट आबंटन कर निर्माण कार्य पूरा कराया जाए,

5. दो सौ बेड के नये मातृ-शिशु चिकित्सालय, जो केन्द्र निधि से निर्मित हुआ है, को शीघ्र प्रारम्भ कराया जाए,

6. कृषि विज्ञान केन्द्र व केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए,

7. सभी गाँवों को प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाए,

8. सभी पात्र व्यक्तियों को पक्का घर/शौचालय/बिजली/एलपीजी कनेक्शन व पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए,

9. प्रत्येक ब्लॉक में महिला विद्यालय बनाया जाए,

10. प्रत्येक ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाए,

11. मेरे जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगायी जाए।

मैं पुन: भारत सरकार की वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूँ।

इति)

---

* Laid on the Table.

1524 बजे

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं भारत की पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, अनुराग ठाकुर जी और उनकी टीम के सभी ब्यूरोक्रेट्स जो इस सुपर-डुपर बजट के साथ लगे, उनको मुबारकवाद देना चाहूँगी। अभी हमारी सांसद महोदया परनीत कौर जी एक ऐसी पिक्चर प्रस्तुत कर रही थी कि जैसे बजट में सब कुछ एकदम से धाराशायी हो गया हो as if every thing is shattered. इंडिया ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि जहाँ पर अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं यह कहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले पाँच सालों में 'Reform, Perform and Transform', यह जिस तरह से करके दिखाया है, पहले पाँच सालों में रिफॉर्म्स, क्योंकि आपको मालूम है कि 70 साल के जो पुराने घाव थे, अगर कोई घाव काफी पुराना हो जाता है तो उसके लिए उसको पहले बहुत ज़्यादा कुरेदना पड़ता है और कुरदते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।

(1525/CS/RP)

उसके बाद जब उसे अच्छी तरह से बैंडेज कर दिया जाता है तो वह घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वही स्थिति हमारे भारतवर्ष की है और हमने इसे महसूस किया। हमने पिछले 5 सालों में 70 सालों के घावों पर अच्छी तरह से बैंडेज लगाया। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए यह कहना चाहूँगी कि:

"हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।"

हमारी सरकार, हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिस तरह से सभी रिफॉर्म्स लेकर आई हैं, अब मैं उन्हें एक-एक करके बताना चाहूँगी। हम चाहे इसकी बात करें कि पैसा कहाँ से आएगा। आपने देखा होगा कि पिछली कांग्रेस की सरकारों में, चाहे हम बुढ़ापा पेंशन की बात करें, चाहे हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, चाहे हम एलपीजी गैस कनेक्शंस की बात करें, चाहे हम

किसी भी तरह की सब्सिडी की बात करें, वह पैसा इस तरह से लॉक था। मैं एक बात कहूँगी कि उसमें दलालों का जो एक सिस्टम चला हुआ था, आप यह देखिए कि वहाँ से करोड़ों रुपया बचा है। आप खुद इस बात को समझें कि वर्ष 2014 में हमारी जो इकोनॉमी 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, वर्ष 2014 से 2019 में वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई, यानी वह लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गई। हम लोग इसी चीज को टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगले 5 सालों में हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर करने वाले हैं और हम इसे करके दिखाएंगे। जैसा कि हमारे सोनकर जी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर आपकी नीयत साफ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।

अब मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक का ख्याल इस सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है। हम लोगों ने कहा है कि जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, गगनयान, चंद्रयान, सैटेलाइट के प्रोग्राम हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो के साथ मिलकर उन्हें पीपीपी मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

इसके बाद हम पृथ्वी पर क्रांति की बात करते हैं, बिल्डिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 30 हजार किलोमीटर रोड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत वेस्ट प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बनाई जाएंगी। इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया कि जो वेस्ट प्लास्टिक है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। 1 लाख 25 हजार किलोमीटर रोड्स को अगले 5 सालों में अपग्रेड करने की योजना है। हम भारतमाला-2 की बात करें। किसी समय में यहाँ पर हमारे आदरणीय लालू जी होते थे, उन्होंने अपने बिहार के लिए कहा था कि हम सड़क ऐसी बना देंगे, हमारी आज सांसद महोदय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार ने वह करके दिखाया है। हमारी सरकार की आगे की प्लानिंग है कि 1,700 जगहों पर यात्री सुविधा सड़क के किनारे पर मिलने वाली है। ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें जनसाधारण को बताने की बहुत सख्त जरूरत है। 1,700 जगहों पर यात्री सुविधा सड़क किनारे मिलने वाली है, जिसमें से 180 जगह 2 वर्ष के अंदर-अंदर पूरी कर ली जाएंगी।

महोदया, मैं सिरसा लोक सभा से चुनकर आती हूँ। दिल्ली से डबवाली तक अगर आप एन.एच.10 को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो सफर किसी समय में चार से पाँच घंटे में पूरा होता था, आज आप ढाई से तीन घंटे के अंदर दिल्ली से डबवाली तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पर इतना अच्छा नेशनल हाइवे बना हुआ है।

अब मैं "उड़ान" स्कीम की बात करती हूँ, जिसके तहत एयर कनेक्टिविटी को छोटे शहरों तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलें, यह प्रावधान हमारी मंत्री जी ने किया है, ताकि एक ब्रिज रूरल और अर्बन के बीच में बन सके। आपको ध्यान होगा कि शशि थरूर जी कह कर रहे थे कि वे किसान की बात करते हैं। वे हमारे बहुत ही आदरणीय, वरिष्ठ सांसद हैं। वे यह भूल जाते हैं कि किसी समय में उन्होंने हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में बैठने वाले लोगों के लिए कहा था कि यह कैटल क्लास है। शायद वे भूल गए थे कि वह कैटल क्लास ही आपको संसद तक पहुँचाती है।

(1530/RV/RCP)

इस तरह की बातें हमारे सांसद महोदय बीच में कहते रहते हैं। अभी तेलंगाना के माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि तेलंगाना इतना तरक्की कर गया, तो मैं यह चाहूंगी कि अगर उनके पास पानी या कुछ भी सरप्लस है तो वे उसके लिए आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की मदद क्यों नहीं करते, क्योंकि 'या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।' हम सब एक-दूसरे की मदद करने से ही आगे बढ़ेंगे, एक-दूसरे की आलोचना करने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा है कि आपने तेलंगाना में अच्छा काम किया। इसलिए तो आप जीते, इसलिए तो आप सरकार में आ गए और हमारी सरकार भी इसीलिए वापस आ गयी क्योंकि हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक जो काम किया, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, उसी के आधार पर दोबारा और इतना जबर्दस्त मैनडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।

अब हम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो 657 किलोमीटर के मेट्रो के रेल प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो गए हैं। आप देखिए कि एक 'वन नेशन वन कार्ड' सरकार शुरू करने वाली है। ये छोटी-छोटी बातें ऐसी हैं, जिनके बारे में मिडिल क्लास के लोगों को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हैं क्योंकि अपनी बात को रखने की एक समय-सीमा होती है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आया है। अगर आप विदेश जाते हैं, अगर बस से यात्रा करें तब वह कार्ड आपके काम आएगा, टोल टैक्स देने में वह कार्ड काम आएगा, पार्किंग चार्ज देने में वह कार्ड काम आएगा। अगर आप रिटेल शॉपिंग करते हैं, वह कार्ड आपके काम आएगा। यहां तक कि पैसा विदड्रॉ करने में भी वह कार्ड आपके काम आएगा।

सागरमाला प्रोजेक्ट्स के तहत जलमार्गों का विकास होगा। इसमें इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इससे एक्सटर्नल ट्रेड्स होंगे। इसके साथ-साथ जो इंटर्नल ट्रेड है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा इनलैंड वाटरवेज मिलने वाला है। इससे हमें रोड, रेल के कंजेशन से राहत मिलेगी।

अगर हमारी काँग्रेस की सरकार ने भी कोई अच्छा काम किया है तो हम उसे भी एप्रीशिएट करते हैं। आप तो दिल्ली में रहती हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले दिल्ली में कितना जबर्दस्त प्रदूषण रहता था, लेकिन सी.एन.जी. आने के बाद दिल्लीवासियों ने काफी राहत महसूस की है। उसी तरह से, अगर हम जल के माध्यम से कार्गो सिस्टम शुरू करते हैं तो उसके अन्दर हमें बहुत अच्छा एक प्रदूषण-मुक्त सिस्टम मिलने वाला है।

अगर हम गांव, गरीब और किसान की बात करें तो आप देखिए कि उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं हैं और अगर हम इन सब योजनाओं को एक साथ क्लब करते हैं तो आप देखिए कि हम एक इन्सान को क्या देने वाले हैं? हम उसे रहने के लिए एक अच्छा घर देने वाले हैं, टॉयलेट देने वाले हैं, बिजली देने वाले हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाले हैं, साफ पानी देने वाले हैं। आप सोच कर देखिए कि एक गरीब इन्सान कभी इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता था और ये सब चीजें उसे एक ही जगह पर मिलने वाली हैं।

किसानों के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र में किसानों के खातों में पेन्शन योजना के तहत करोड़ों रुपये आए हैं। काँग्रेस की सरकार के समय तो दो-दो, ढाई-ढाई रुपये के चेक आते थे। वे बहुत हैरान होते हैं कि आप की सरकार इतने पैसे दे रही है, उनके खाते में इतने पैसे आ रहे हैं, इसका उन्हें यकीन नहीं होता। मैं जिस इलाके से आती हूं, वह कृषि का इलाका है।

किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार
जीना इसी का नाम है।

यह हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने करके दिखाया है।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय सभापति महोदया, मैं पहली बार बोल रही हूं।

माननीय सभापति: मैंने पता किया था तो उन्होंने कहा कि आप ज़ीरो आवर में बोल चुकी हैं।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): महोदया, ज़ीरो आवर में तो पूरा एक मिनट भी बोलने नहीं दिया जाता है।

माननीय सभापति: अगर सभी माननीय सदस्य एग्री कर रहे हैं तो मैडम को दो मिनट का समय और दे दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): एक महिला के पास वित्त मंत्रालय है, एक महिला वहां बैठी हैं और एक महिला यहां बोल रही है तो आप लोगों को थोड़ा सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान)

महोदया, अगर हम जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय में 1592 ब्लॉक्स क्रिटिकल ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं और उनमें 256 जिले आते हैं।

(1535/MY/MMN)

मैं यह कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे हरियाणा के भी 18 जिले उसके अंदर आते हैं। कल हमारे आदरणीय सुखबीर बादल जी इसके बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने इसका जिक्र किया था।

*Today is hon. Member Shri Sukhbir Singh Badal Ji's birthday. His wife is sitting here. I request her to kindly convey my best wishes to Shri Sukhbir Singh Badal Ji.

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि बाकियों को प्रॉब्लम होगी। पंजाबी का नोटिस नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होगी। मुझे समझने की प्रॉब्लम नहीं है।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम यह चाहते हैं और आप भी देखिए कि हमारे वित्त मंत्रालय ने इसके लिए क्या प्रोविज़न किया है - creation of local infrastructure for source sustainability, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर है। जल जीवन मिशन है और इसके तहत सेन्ट्रल एवं स्टेट दोनों सरकारें मिलकर सप्लाई मैनेजमेंट एक्रॉस दी कंट्री करेंगी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई साइड भी है।

सभापति जी, मैं आपको बताती हूं कि जिस तरह से मैं गांवों में देखती हूं, मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी। माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रभावित होकर वर्ष 2014 में नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में आई। मैं यह बताना चाहूंगी कि जब मैं गांवों में जाती हूं, हमारे यहां एक छोटा-सी जगह नरमाना है, वहां पानी इस तरह से खुला चलता है, जब तक एक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, इस सिस्टम को लागू करने के लिए हमारी सरकार ने डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर ऐट लोकल लेवल, यह बहुत जरूरी है। जिनके पास यह सरपल्स है, वे इसकी कीमत को समझते नहीं हैं और जिनके पास नहीं हैं, वे एक-एक बूंद के लिए तड़पते हैं।

अगर मैं इसी तरह से यूथ के लिए बात करूं और आप देखिए कि 2 अक्टूबर, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और पूरे पांच साल के अंदर जबरदस्त तरीके से स्वच्छता के लिए उन्होंने काम किया। इस संबंध में 2 अक्टूबर, 2019 को हमारा गांधीपीडिया भी

---

* Original in Punjabi

आने वाला है। इसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें सूचित किया है। अगर मैं अभी यूथ के बारे में बात करूं तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है, जिसके तहत रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। इससे पहले आप देखिए कि हमारे जो 200 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर हमारा कहीं नाम नहीं था। अब तीन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें हमारा नाम आ गया है।

इसके बाद अगर हम 'खेलो इंडिया' की बात करें, 'खेलो इंडिया' के तहत आप देखिए कि उसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है। …(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने जल, थल और अंतरिक्ष में सब जगह पर काम किया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी सब कुछ किया है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारा जो शांति मंत्र था, उसको मैं अब कह रही हूं-

"ऊँ द्यौ: क्रांतिरन्तरिक्षँ क्रांति:,
पृथ्वी क्रांतिराप: क्रांतिरोषधय: क्रांति:।
वनस्पतय: क्रांतिर्विश्वेदेवा: क्रांतिर्ब्रह्म क्रांति:,
सर्वक्रांति:, क्रांतिरेव क्रांति:, सा मा क्रांतिरेधि॥
ऊँ क्रांति:, क्रांति:, क्रांति:"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

(इति)

1538 hours

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you Madam Chairperson for giving me this opportunity to comment upon the Budget.

First of all, as a student of Dravidian school of thought, I have to congratulate the hon. Finance Minister on becoming the first exclusive full-fledged woman Finance Minister of this country.

At the same time, with all my due respects to the hon. Finance Minister, let me say that I am not able to appreciate the Budget which was presented by her. What is the vision of the Government? You presented the Budget. But what are all the contemplations given in the Budget, what are all the assurances given in the Budget in order to fulfil them, there is no roadmap at all. I read the President's Address. I read *The Economic Survey* which was enunciated by the Chief Economic Advisor. In a triangular manner you are appraising the three documents, namely *The Economic Survey*, the President's Address and the Budget Speech. A lot of assurances were given with huge sound but there is no light at all. I can specifically say that there is no roadmap at all as to how you are going to fulfil what are all the assurances that have been given in the Budget documents.

(1540/SAN/CP)

Secondly, there is a big anguish over the Budget document from my side because I have listened to 15 Budget Speeches in this House as a Member of Parliament, as a Minister of State and as a Cabinet Minister, but I have not come across such a Budget where the central axis itself is fundamentally, drastically

and destructively changed. How? This country is agrarian-economy oriented country, but this Government believes that the real wealth creators are the corporates. Where do you have to create the taxation and other resources for the Budget? It must be from the domestic investment; it must be from the agriculture; and it must be from the domestic industry. But this Government exclusively relies upon the foreign investment. They believe that the corporate world in this country can create wealth for our people and our country. It is fundamentally wrong. I will come to these points one by one.

Madam Chairperson, I charge that until and unless this mindset is going to change, this Budget will not give any single deliverance in this country in the near future. For example, I can tell you that this Budget wants to rely upon two components – FDI and FPI. They have extended a lot of concessions to FPI. Now, I come to FDI. What they are claiming is that the present economic scenario of this country is of three trillion dollars and they want to make it five trillion dollars within five years. For that, they are almost exclusively relying upon the FDI. In the Budget itself, it has been claimed that there is going to be an inflow of 68 billion dollars in this country, In order to achieve the target of five trillion dollars, they are exclusively relying upon the FDI, but compared to five trillion dollars, which this country wants to achieve, 68 billion dollars come to only two per cent. The entire Budget is relying upon this two per cent and they want to project before the country and this Parliament that they are going to achieve five trillion dollars target. Where is the roadmap? Where is the plausible approach? It is not there at all.

The Finance Minister quoted during her Budget Speech Pisirandaiyar and Purananuru. Pisirandaiyar gave a very valid and valuable advice to King Pandiyan. I read the verses again and again. That is about the mode of collection of tax. What we are worrying about is means of collection of tax – where it has to be obtained from, where people have to be left out and where people have to be taxed. That is not relevant. Of course, I am entitled to correct the hon. Minister by saying the correct Tamil version in Thirukural. What does Thiruvalluvar say? He says,

"Iyatralum Eetalum Kaathalum Kaaththa
Vaguthalum Valla Tharasu".

It is the king who should do this – produce, acquire, conserve and dispense. With all my sincerity, I can tell that this Budget miserably fails on these four counts. I will demonstrate it one by one.

Before speaking about that, I may be permitted to say something about allotment to Tamil Nadu Government because Tamil Nadu Government is almost your Government. You are running from here as *de jure* Government the Government of Tamil Nadu. The Government is already completely … *(Not recorded)* In spite of that, you are running the Government.

It is alright, but I want to say that between the intermit Budget and the full Budget presented on 5th July, there is a decrease of Rs. 7,424 crore in Tamil Nadu's share of tax. Not only that, its GST share of Rs. 7,214 crore has not been released so far. They are in your alliance. You wanted to accommodate them in

the Cabinet itself. Is it fair on your part to treat Tamil Nadu Government like this? Not at all. We are weeping, though we are not in power.

Another thing is, I am really surprised, that the Budget Speech does not disclose for the first time in India – I have been in the Parliament for more than 15 to 18 years – total revenue, total expenditure, fiscal deficit and additional revenue mobilisation.

(1545/RBN/NK)

On the contrary, the Finance Minister suggests, 'Go to the document and read'. There is a convention. Is it fair on the part of the Minister to say that? There is acute water scarcity throughout the country. There is no single word about this drought. Then, Prime Minister made a long statement about jobs. Even your election manifesto says that you are going to create 10 crore jobs. With all sincerity I would like to tell you the word 'job' is missing in this document. Is it the way to present the Budget?

Then coming to the mode of taxation, you are claiming that for those companies which have a turnover of Rs. 400 crore, the tax will be reduced from 30 per cent to 25 per cent. Then the Minister herself is saying that by this scheme 93.30 per cent of the companies will be covered. So, what is left out? Only 0.7 per cent of the companies has been left out. In other words, I can say the entire corporate world has been given substantial tax concession without any accountability to this country. What does it mean? It is not a matter of pride.

Coming to the disinvestment, what does the Budget document say? …(*Interruptions*) I will just need three or four minutes. I have some very important points to make. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKSHI LEKHI): Shri Raja, you have already exceeded your time. So, please conclude within two more minutes.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Please give me three or four minutes. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is an hon. Member who wants to speak from your Party.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): *… (Not recorded)* But I am exclusively confining myself to the boundaries of the Budget.

HON. CHAIRPERSON: Shri Raja, if you want to seek time, it is one thing. Please take your words back. It will not go on record. Others will also have the same opinion about you. Let us not use these words.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I will abide by your order.

The fiscal deficit is 3.3 per cent.

… (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): The National Flag on the top of the Parliament is damaged. It should be replaced.

HON. CHAIRPERSON: We take note of that.

SHRI A. RAJA: Madam Chairperson, the time spent on this conversation may kindly be deducted.

The Government wants to reduce the fiscal deficit to 3.3 per cent of the GDP through non-tax revenues, including disinvestments since your tax revenue is not good. You are not able to collect revenue. To reduce the fiscal deficit to 3.3 per cent of the GDP, you want to have investments from abroad. This is not good to the economy.

There is not a single word about the debt that was written off. I have been told that Rs. 5.55 lakh crore have been written off owed by the defaulters. Rs. 5.55 lakh crore have been written off to the benefit of corporate people. But for loans taken by the middle class by way of education loan, loans taken by Scheduled Castes and Scheduled Tribes, OBCs to the extent of Rs. 10,000 or Rs. 1 lakh or Rs. 2 lakh, their properties are being attached. But on the other hand, Rs. 5.55 lakh crore have been written off for the corporates. What is the justification?

HON. CHAIRPERSON: Shri Raja, it has been more than eleven minutes.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I will just take one or two minutes.

HON. CHAIRPERSON: One more minute and that is it.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Finally, I would like to say ours is an agrarian economy. You want to paint a rosy picture to the world by saying that Rs. 75,000 crore has been allotted to agriculture. When I heard it from the mouth of the Finance Minister, I, as the son of a farmer, was also happy. But going through the document, I found that this Rs. 75,000 crore is not for waiving the loan; it is not for promoting agricultural research; it is not for stabilising the market; it is not

for setting up godowns and cold storages; it is not for rural connectivity; and it is not for Minimum Support Price.

(1550/SM/SK)

The purpose of giving individually to the farmers, to those who are having lands or those who are landless is that you want to get the political mileage by giving Rs.6,000 to each and everyone and you want to bring everything under the head, 'agriculture'. Is it not a dubious step? …(*Interruptions*) Madam, I am just concluding. Please give me one minute.

With folded hands, I want to advise my young colleague. …(*Interruptions*). This Government came to power not because of its performance. You promised that black money will be returned to India. It has not been done. Your promised ten crore jobs. It has not been done at all. You promised double digit GDP. It did not happen at all. Then, for what purpose did you come here?

Some people are thinking that this is a Hindutva or religious-oriented phenomenon. I am not believing this. This Government came to power because you projected that you are the only saviour/chowkidar who could protect this country. I can say that ultimately what has happened is there is slow-down in growth, rise in unemployment, rise in NPAs in the banks etc. Rural distress is the real face of this Government.

I want to quote one sentence from our mentor, Shri C.N. Annadurai *alias* Anna which he said in the Rajya Sabha about the performance of the Government, "Democracy is distorted, socialism is emaciated, nationality is misinterpreted." The same is applicable to you. Thank you.

(ends)

***श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा):**

* Laid on the Table.

1552 hours

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Madam, I thank you for this opportunity.

I will speak in Tamil.

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri K.Subbarayan in Tamil,
please see the Supplement. (PP 398A to 398D)}

(1555/AK/MK)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): इतने महत्वपूर्ण बजट पर डिस्कशन चल रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं।

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Please listen to me. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI) : The Parliamentary Affairs Minister is taking notes.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is a collective responsibility. The other Ministers are here.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude as your time is up.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Parliamentary Affairs Minister is here.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to conclude his speech.

… (*Interruptions*)

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Madam, I will conclude within three minutes. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your time is already up.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri Sisir Kumar Adhikari.

… (*Interruptions*)

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Madam, kindly give me two more minutes to speak, and I will conclude my speech.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Please give him some more time to speak. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Baalu, I have already extended his time by two minutes.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The time has to be allocated accordingly. His time has already been extended.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): He is speaking about the issues being faced by Tamil Nadu. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I know, but the time has already been extended.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker to speak is Shri Sisir Kumar Adhikari.

… (*Interruptions*)

1558 hours

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Madam, it was announced that the current Budget is laying a 10-year roadmap of the economy. A dream projection of making India a $5 trillion economy by 2024-25 is shown by the Government. In its own admission, India's GDP must grow at a rate of 8 per cent per annum to achieve the target. Like a typical totalitarian Government, it is shifting goal posts and changing its projections just to fool the people.

Now, after completion of five years in the Government, no Minister or Government document is talking about achieving a double-digit growth. Now, the new buzzword is $5 trillion economy. Even the former Economic Adviser of the Government -- who wrote about achieving double-digit growth -- is now admitting that real GDP growth was merely 4.5 per cent during the last five years. Does this Government think that it can announce anything and get away without providing any evidence?

If you ask any person in the street or in the locality of the country or anywhere else, there will be a uniform answer that lack of employment is the biggest concern of the country, especially, among the youth.

(1600/SPR/YSH)

India is a country of young people. We find failure of the Government to generate employment. Rather we find a concerted effort on the part of the Government is made to take away employment of the people through whimsical action like demonetization, which has created a grave situation where unemployment has reached a 45 year high as per Government's own statistics. This Government had tried very hard to suppress the NSSO data before the election. In fact, they discredited their own officials who were involved in preparing the NSSO Report. Have we seen any acknowledgement of the fact of highest unemployment in the last 45 years in the Budget speech? The answer is a big no.

In the entire Budget speech, there is only one paragraph – paragraph 47 – where some definite number of employment to be generated by Government action has been provided. It says that the Schedule of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) should enable 50,000 artisans to join economic value chain. Further, the Schedule contemplates to set up 80 Livelihood Business Incubators (LBIs) and 20 Technology Business Incubators (TBIs) in 2019-20 to develop 75,000 skilled entrepreneurs in agro-rural industry sector. Even if we accept these figures as gospel truth, only 1,25,000 employment may be generated in a best case scenario. In a country of a population 130 crore, is it a figure even worth mentioning?

Time and again this Government has shifted goalposts, manipulated figures, suppressed independent evaluation, and cast aspersion on independent

economists and thinkers. Institutions have been attacked; their independence undermined; and any voice of dissent muzzled in the name of nationalism.

Even the Reserve Bank of India that always maintained the highest standard of independent decision making was not spared. In the last five years, we have seen two of the RBI Governors were forced to move out of the RBI. Recently, a Deputy Governor, who consistently opposed Government interference in RBI matters, left prematurely before completion of his term. What message does this Government wants to convey to the nation and to the world?

Coming back to data and figures, this Government's reliability has hit the rock bottom. Many times, the GDP growth rate figures were revised retrospectively to show that things were well despite the world wide acknowledgement that Indian economy has been passing through a serious downturn. The Government cannot fool everybody all the time. One of the major areas of concern is the figure of fiscal deficit.

(1605/UB/RPS)

This time, *The Economic Survey* and the Union Budget Speech portray very different pictures.

I would like to draw attention of this august House to Chapter-2, Volume-II of the Economic Survey which was tabled in this House one day before the Budget Speech.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Please conclude.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Table 1 of the Chapter shows that revenue receipts as a percentage of GDP is 8.2 per cent. In Medium Term Fiscal

Policy-cum-Fiscal Policy Strategy Statement of the Union Budget (page 12), the total revenue receipts for Budget Estimates 2019-20 as a percentage of GDP has been shown as 9.3 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Sisir ji, the time has already been extended. Please conclude. I have told you three times. Just put your last word.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): What magic has been done in one day that the revenue receipts of the Government increased by 1.1 per cent of the GDP? I demand a thorough probe into the fudging of numbers in the Union Budget.

HON. CHAIRPERSON: He has many papers left. Please conclude, Sisir ji, in last one line.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Madam, I will conclude in one minute. I oppose the move of disinvestment of forty-four PSUs. I have serious objection on this issue.

The prices of petroleum products have been raised. This move should be withdrawn. *Kaju* import has now gone up from 40 per cent to 70 per cent because of which, at least, one crore *kaju* workers will be unemployed.

(ends)

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):

*Laid on the Table.

1608 बजे

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि 2019 के बजट पर जो चर्चा चल रही है, आपने उसमें मुझे हिस्सा लेने की अनुमति दी है।

मैडम, आम तौर पर बजट पूरे भारत की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, लेकिन 2019 का बजट काफी अलग है। जब मैं अपोजिशन बेंचेज से सुनता हूं कि वे किस तरह से इस बजट की कमियां गिनाते हैं, तब मेरा मन करता है कि मैं इस बजट का सार रखूं। हमारे बजट में सरकार की सब योजनाओं का सार है। विकास का मजबूत आधार दिया है। बजट हमारे लिए नहीं चमड़े का एक थैला, इस बार हमने भारतीय संस्कार दिया है। इस बजट के अंदर किस तरह से भारत की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, किस तरह से भविष्य का रास्ता तय करना है, वह सारा कुछ इस बजट में दिया हुआ है। पिछले पांच सालों में भारत की सरकार, प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, पूरे भारत ने देखा है और काम करने का तरीका देखा है। पिछले पांच सालों में आपने कई बार सुना होगा कि सब कहते थे – आपने बड़े हाई एक्सपेक्टेशन्स बना दिए। कुछ लोग यह भी कहते थे कि इन एक्सपेक्टेशन्स को आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। यह बहुत दुख की बात है कि इतने मजबूत राष्ट्र के अंदर इतने बजट हुए, लेकिन किसी ने इतने हाई स्टैंडर्ड्स ही नहीं रखे। हमने हाई एक्सपेक्टेशन्स को एचीव किया और पूरे देश का विश्वास जीता। यह विश्वास हमने मात्र एक मूल मंत्र से जीता कि देश के हित को सबसे ऊपर रखना है। “Country comes first, always and every time”.

अगर हम भारत को पिछले कई दशकों में देखें कि किस तरह विश्व में हम अलग मापदण्डों में पीछे रह जाते हैं तो क्या हमारी काबिलियत में कमी थी? क्या हमारे रिसोर्सेज में कमी थी? क्या किसी नॉलेज की कमी थी?

1609 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर कमी थी तो भारत के जो नेता थे, लीडर्स थे, उनकी इच्छा में कमी थी।

(1610/RAJ/KMR)

उनके कमिटमेंट में कमी थी और उनके विजन में कमी थी, लेकिन पिछले पांच साल ने यह सब कुछ बदल कर रख दिया। जनता ने प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का काम देखा और देख कर उनको सराहा और उनका विश्वास पाया। अब जब इतना बहुमत मिला है तो जरूरत है कि हम देश को नई ऊँचाईयों तक लेकर जाएं। यह सबसे युवा देश है तो जाहिर-सी बात है कि नई उम्मीदें होंगी, नई आशाएं होंगी। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि यह बजट क्या है तो मोदी सरकार का मकसद 2019 के बजट से नए भारत की नींव रखना है। मोदी सरकार का विजन क्या है, वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को तैयार करना है।

विपक्ष के बहुत-से वक्ताओं ने कहा है कि रेवेन्यू कहां से जेनरेट होगा, पैसा कहां से आएगा। उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की है। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज इच्छाशक्ति, कमिटमेंट है। मैं इस तरह से इस बात को रखता हूं :-

बेशक साधन कम हैं, लेकिन हम उम्मीद जगा लेंगे,
बेकारी, बेरोजगारी को कोसों दूर भगा लेंगे।
अगर सिंधु में घोर प्रभंजन उठते हैं तो उठने दो,
हम हिम्मत की पतवार से कश्ती पार लगा देंगे।

सबसे जरूरी जो बुनियादी चीजें व्यक्ति को जीवन जीने के लिए है, हम ने वह देने की प्राथमिकता रखी है। हम ने हर व्यक्ति को गांव तक सड़क दी है। हम ने हर व्यक्ति को घर में पानी देने का संकल्प कर लिया है और लक्ष्य भी रख दिया है कि वर्ष 2024 तक यह संभव होगा। हम हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाएंगे। वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति के पास घर हो और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो। इतने दशकों के बाद हम ने बुनियादी लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू किया है। यह पहली सरकार है जो अपने लिए खुद लक्ष्य रखती है और उसका ऐलान पब्लिकली करती है। यह लक्ष्य के तारीख से पहले लक्ष्य पूरा कर देती है। अगर आप 'उज्ज्वला योजना' पर ध्यान देंगे तो हम ने जो लक्ष्य रखा था, हम ने उससे पहले पांच करोड़ कनेक्शंस दे दिए। फिर, यह सरकार ऐसी है कि उसके बाद नए लक्ष्य रख देती है, उसे और बढ़ा देती है। यह काम करने वाली सरकार है। आज भारत की

अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। We were the 11th largest economy in the world in 2013. In mere five years we have taken it from the 11th largest to the 6th largest in the world. While doing this, we have also kept in mind the regulations by which the Budget has to be put across to the House. We have maintained the discipline mentioned in the FRBM Act 2003. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 says that you must take into consideration the fiscal deficit, the current account deficit and the government debt. We have taken that into account and we have maintained the discipline.

जब करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट की बात होती है तो सीधी बात यह है कि भारत में कितना पैसा आ रहा है और भारत के बाहर कितना पैसा जा रहा है। हम ने भारत में पैसे लाने की पूरी कोशिश की है। Foreign Direct Investment 64 Billion dollars in 2018-19, अभी तक का सबसे ज्यादा है। एफडीआई सबसे ज्यादा क्यों होता है?

महोदय, सीधी-सी बात है कि अगर कोई पूरी दुनिया में पैसा लगा रहा है, चाहे वे वित्तीय संस्थान हों या बिजनेसमेन हों, वे एक ही कारण से पैसा लगाते हैं। उन्हें पता है कि भारत में पैसा लगाने से उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, यहां की सरकार स्टेबल है, यहां की ग्रोथ रेट हाई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इनवेस्टर फ्रेंडली है। यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलप हो रहा है। ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसी उभरती हुई इकोनॉमी है, जहां दुनिया पैसा लगाना चाहती है। हम ने एफडीआई को और खोल दिया। हम ने उसको मीडिया के लिए खोल दिया, एनिमेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत की युवा पीढ़ी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी हुई है। हम ने इनके लिए फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट खोल दिया है। हम ने सिंगल रिटेल ब्रांड के अंदर यह खोल दिया। हम ने इंश्योरैंस सेक्टर के लिए खोल दिया। जिस कारण से सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है - पेट्रोलियम, डीजल, हमने उसको एक चुनौती समझ कर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की एक संभावना खोली है। जब एक मजबूत सरकार निर्णय लेती है तो इंडस्ट्री तुरंत उस रास्ते

पर चल देती है। मैं दो-तीन दिन पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि एक मेजर कार मैन्युफैक्चरर ने ऐलान कर दिया, दो साल के अंदर एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार भारत के अंदर उपलब्ध होगी।

(1615/IND/SNT)

यह भारत की ताकत है। मैं एक अफ्रीकन ऑथर को क्वोट करता हूं। मैं इसलिए अफ्रीकन ऑथर को क्वोट कर रहा हूं क्योंकि वह भी एक बढ़ता विकासशील रीजन है। उन्होंने लिखा है कि - "Prayers do not build good infrastructure. They do not develop countries; they do not improve poor health system or education system. God has placed man in charge of all." मैं इसे यदि हिन्दी में कहूं तो सिर्फ प्रार्थनाओं से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, सिर्फ प्रार्थनाओं से देश विकसित नहीं होता, वे हेल्थ केयर सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव नहीं कर सकतीं, क्योंकि भगवान ने उसके लिए इंसान को जिम्मेदार ठहराया है। इस देश के 130 करोड़ लोगों ने उस इंसान को पहचान लिया है और चुनकर संसद के अंदर हमारा नेता बनाकर भेजा है। यह इस सरकार की ताकत है कि जो तय कर लेती है, वह करके दिखाती है। पिछले पांच साल को हम लोग ट्रेलर कहते थे। अब तो विपक्ष को भी रट गया होगा कि साठ साल में क्या काम हुआ और साठ महीनों में क्या काम हुआ। मैं आपका समय इस बात में ज़ाया नहीं करूंगा, लेकिन हर दिशा में बहुत तेज़ गति से काम हुआ है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सौ लाख करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, तो एक नई उम्मीद जगती है, क्योंकि जहां-जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां अपने आप विकास होना शुरू हो जाता है।

महोदय, जहां सड़कें बनने लगती हैं, वहां अपने आप तरक्की होने लग जाती है। मकान, एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज, रेलवेज जहां-जहां जाते हैं, वहां अपने आप विकास होने लग जाता है। मैं अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी को क्वोट करना चाहता हूं। जब सड़कों की बात होती है, तब उन्होंने कहा था कि - "American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good." आज बड़े गर्व से हम कह सकते हैं

कि ग्रामीण भारत के अंदर डेढ़ लाख किलोमीटर सड़कें बना चुके हैं और अब हमने अगले पांच साल के लिए 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कें और बनाने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए हमने 80 हजार करोड़ रुपये अलग से रख दिए हैं।

महोदय, जब मैं शूटिंग करता था, तब मुझे अमरीका जाने का अवसर मिलता था। वहां गांवों में सड़कों पर नाम नहीं लिखा होता था, लेकिन एफएम और एक आंकड़ा लिखा होता था। मैंने अपने मित्र से पूछा कि एफएम लिखा है, उसका क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि एफएम का मतलब फार्म टू मार्केट है। यह कितना शानदार आइडिया है। यह आइडिया भारत के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब ले कर आए, इसी कांसेप्ट से लेकर आए कि जहां आप खेतों को मंडी से या शहर से जोड़ देंगे, तो अपने आप विकास शुरू हो जाता है। हमने यह मुहिम वहीं से शुरू की थी और आज 1 लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का हमने लक्ष्य रख दिया है। Ours is the third largest aviation market in the world. We have also developed 100 airports.

महोदय, अब इनलैंड वॉटर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन इज़ वॉटर ट्रासपोर्टेशन। इस पर काम चल रहा है। रेलवे को इंप्रूव करने के लिए पीपीपी मोड पर काम चल रहा है। गैस ग्रिड्स, पॉवर ग्रिड्स, वॉटर ग्रिड्स, आई-वेज, रीजनल एयरपोर्ट्स इन सब को एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिलिकॉन वैली में कहा था कि भारत को आई-वेज की हाई-वेज से ज्यादा जरूरत है। आज हर भारतीय के हाथ में मोबाइल है, जिसमें इंटरनेट है। देश का गवर्नेंस उनके हाथ में है। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आती है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पिछले साठ साल में यदि 60 ग्राम पंचायतों के अंदर फाइबर ओप्टिक केबल लगी थी, तो आज करीब एक लाख पंचायतों के अंदर लग चुकी है। इसी तरह से हमने पिछले पांच साल में हाउसिंग का लक्ष्य पूरा किया। अब दो करोड़ घरों का नया लक्ष्य रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2015 में जब हम एक ग्रामीण मकान बनाते थे, तो 314 दिन का समय लगता था, लेकिन वर्ष 2019 तक आते-आते 214 दिनों में ही वह लक्ष्य

पूरा कर लेते हैं। विपक्ष ने बार-बार यह बात रखी कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। मैं कहता हूं कि एक लीडर में यह काबिलियत होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके साधन भी जोड़े जाएं। हमने पहली बार लाँग टर्म बाँड्स, जो विदेश में भी दिए जाएंगे, उन्हें ऑफर करने का एक प्रोसेस शुरू किया है। इसके साथ-साथ क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कार्पोरेशन को सेट-अप किया है। एफआईआई सीधे डेट सैक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एमएसएमई की अभी बात कर रहे थे।

(1620/GM/VB)

अभी राजू साहब एमएसएमई की बात कर रहे थे, वे चले गए हैं, एमएसएमईज के साथ भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इंट्रेस्ट पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। इसके लिए साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये रखे हैं। और तो और, भारत की सरकार यह मानती है कि एनजीओज और सोशल सेक्टर का काम भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को विकसित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण है। एनजीओज के लिए, सोशल एंटरप्राइजेज़ के लिए पहली बार स्टॉक एक्सचेंज बन रहा है। आप अच्छा काम करते हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में दिखेंगे और फण्ड इकट्ठा करना और आसान हो जाएगा। हमने स्टार्ट-अप्स को प्रमोट किया, मेक इन इंडिया के लिए कस्टम ड्यूटी वेव-ऑफ की।

अगर आप रूरल सेक्टर को देखें, तो ग्रामीण भारत के अंदर 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है ताकि एक इकोनॉमिक स्केलेबिलिटी आ सके। अगर ट्रैक्टर है, तो एक ही ट्रैक्टर को सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनके प्रोड्यूस को मण्डी तक ले जाना है, तो केवल एक ही साधन से ले जाया जा सकता है ताकि सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर लागत को कम कर सकें।

'ज़ीरो बजट फार्मिंग' की बात हुई। यहाँ पर शशि थरूर जी ने कहा कि उनको तो यह समझ ही नहीं आता है। 'ज़ीरो बजट फार्मिंग' के बारे में उनको समझ ही नहीं आती। उनको कैसे समझ में आएगी? …(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, जो सांसद यहाँ पर नहीं हैं, उनके बारे में कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप प्लीज बैठिए। I too know the rules.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई आपत्तिजनक बात होगी, तो रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: Now sum up, please.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए। कौन-सा नियम है?

…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): As per Rule 352, a Member while speaking shall not make a personal reference by way of making an allegation. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is no allegation. Everyone knows the rules.

… (*Interruptions*)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Here in this Session itself, Dr. Shashi Tharoor's name was previously used by a very senior and learned Member.

माननीय सभापति: कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: राज्यवर्धन जी, आप कंटिन्यू कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई एलिगेशन हो, तो नाम निकाल दीजिएगा और नहीं है, तो नाम कंटिन्यू रह सकता है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत बाबू, आप बैठिए प्लीज। आप तो चेयर की पावर का सम्मान कीजिए। You are a very senior Member. प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): सर, जो मेंबर्स यहां उपस्थित हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। …(व्यवधान) मैडम परनीत कौर जी यहां बैठी हैं, उन्होंने भी जीएसटी के विषय पर बोला। …(व्यवधान) उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि सब से ज़्यादा अगर कोई गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा, तो वह जीएसटी जाएगा, क्योंकि बार-बार उसके अंदर बदलाव किया गया। …(व्यवधान) यही तो इस सरकार की खासियत है कि यह सरकार जनता की बात सुनती है। …(व्यवधान) हर महीने उसके अंदर बदलाव किया गया। …(व्यवधान) पहली बार जीएसटी आया था। …(व्यवधान) यह रिकॉर्ड है कि जिस देश के अंदर जीएसटी आया, वहाँ की सरकार गिर गई, लेकिन हमारे देश में जब जीएसटी आया, तो हमारी सरकार और बढ़कर यहाँ पर उपस्थित हो गई। …(व्यवधान) यह इस सरकार की ताकत है कि यह जनता की बात सुनती है। …(व्यवधान) कोई भी कमी हो, तो यह सरकार उसे दूर करने में कभी भी पीछे नहीं हटती। …(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात न कहकर, यहीं खत्म करता हूँ।

दलित, किसान, मज़दूर हमारा आधार है,
अल्पसंख्यक और महिलाओं के हितों से प्यार है,
हर एक परिवार जुड़ रहा है देश के विज़न से,
अब भारत का हर नागरिक मोदी सरकार है।

(इति)

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA):

*Laid on the Table.

(1625/RK/PC)

1625 hours

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak, in this august House, on the Union Budget. Sir, this is my maiden speech.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य का पहला संबोधन है, उन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): At the outset, I would like to congratulate the first woman Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitaraman, for outstandingly presenting the maiden Budget of the Government for more than two hours without sipping a drop of water.

We welcome the aspirations and the vision of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to restructure and develop the concept of New India. Under his dynamic leadership, we are confident enough that our country will achieve $ five trillion economy. We are also proud that our hon. Prime Minister has set our great nation on the global pedestal.

The people of Andhra Pradesh are completely disappointed with this Union Budget. Our people anxiously waited for a favourable announcement from the Government of India, the hon. Finance Minister, but we are left in deep despair. I would like to say that promises are like clouds. When they are fulfilled, it touches our soul like rain.

मैं इसे हिंदी में भी बताना चाहता हूं :

'ये वादे जो होते हैं, बादल जैसे होते हैं,
और जब ये वादे निभाए जाते हैं,
तो ये बरसात के रूप में आते हैं।'

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूं that in the year 2014, the Prime Minister candidate, Shri Narendra Modi, at the time of his election campaign, made a promise at the foothills of Lord Tirupati Balaji that when the NDA Government will come to power the bifurcated Andhra Pradesh will be given Special Category Status. But that promise is yet to be fulfilled. The then Prime Minister, Shri Manmohan Singh, made a promise on the floor of the Parliament that bifurcated Andhra Pradesh will be given Special Category Status. The then senior BJP Leader and now the Vice-President of the country had also demanded the UPA Government to give Special Category Status to Andhra Pradesh for ten years. None of the promises made by the leaders has been fulfilled. We are left in vain and neglected. Therefore, the majority of the people of united Andhra Pradesh opposed the bifurcation of Andhra Pradesh. The people were wretched in a political foul play.

Sir, for the past 70 years, Andhra Pradesh is considered to be a very rich State as far as the agriculture sector is concerned. The people of Andhra Pradesh invested huge amounts in building the great Hyderabad.

(1630/RC/SPS)

They thought that their investments would be safe, but all the infrastructure, industries and IT companies went to Telangana State.

The UPA Government divided Andhra Pradesh unscientifically for their political gains and left us in the lurch. The NDA Government also left Andhra Pradesh high and dry.

Our hon. Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu supports every move of the hon. Prime Minister. I would like to say that the Budget has maintained focus on infrastructural development. There is a vision of 'one nation one grid' for electricity. Similar is the plan for gas grids, water grids, highways, and regional airports. This is indeed ambitious and would be transformational.

I welcome the decision to reduce corporate tax by 25 per cent for the companies with a turnover of Rs.400 crore. The proposal to improve the railway infrastructure through Public-Private Partnership model is well advised. Almost Rs.50 lakh crore investment would be required over the years for this purpose. We welcome Bharat Mala with an investment of Rs.80250 crore to build 1,25,000 kilometres of village roads. It is a good initiative for transportation and its maintenance by the Government. The introduction of loan of Rs.1 crore for MSME would be a great relief to the small business. Making easier accessibility of processing loans through single portal is also a welcome thing.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude now.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, this is my maiden speech.

The hon. Finance Minister has proposed further consolidation of the Centre's holding in PSUs both in the financial and non-financial sectors. We also welcome the National Research Foundation. Some institutions of higher learning were set up in Andhra Pradesh under the AP Reorganisation Act, but

they are yet to have their own buildings, infrastructure and the funds are not flowing by. They are trickling drip-by-drip.

The hon. Member, our Olympic shooter who won the silver medal, was quoting that our economy is the 6th largest in the world. But I would like to mention here the National Sports Education Board. The Government committed to expand 'Khelo India' theme. In 2016 Olympics, India had achieved only two medals and ranked 64th. We do not want to take a dig on it because your Government had come two years before the Olympics. I would like to know whether you have any roadmap for the 2020 Tokyo Olympics. Can India win gold medals? Can India be in the top ten in this coming Olympics?

The prices of petroleum products have been increased. This will be a great deficit to *aam aadmi*. Hon. Prime Minister was talking about 'one nation, one election'; 'one nation, one card' and 'one nation, one grid'. Why can we not have 'one nation, one tax'? Why do you not bring petroleum products under GST? We are buying crude oil at cheaper prices than before.

(1635/SNB/KDS)

Sir, coming to our State, we are in a crisis; we do not even have enough funds to pay salaries to employees. We are in a huge crisis. My leader and our hon. Chief Minister, Shri Y S Jaganmohan Reddy Garu always says `*Devudu Unnadu'*, which means God is there and God is great. We, the people of Andhra Pradesh honour our God; love our people and defend our country. The State of Andhra Pradesh is the mother to our soul.

Therefore, I urge upon the hon. Prime Minister to take care of the State of Andhra Pradesh by caressing and nurturing it with love and compassion. I humbly submit to the hon. Prime Minister not to see the State of Andhra Pradesh with the prism of …(*Interruptions*) The people of Andhra Pradesh rejected him in the General and State Elections of 2019 and TDP is in deep crisis ever since the party was established.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : नाम मत बोलिए। नाम हटा दीजिए। आप अभी नए हैं, अभी सीखिए।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Our State is in deep crisis *… (Not recorded)* Therefore, with deep respect YSRCP wants to put the demands of our State before this august House through you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Mohan Naidu.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I am concluding. I will take one minute.

I would like to request the hon. Prime Minister to sanction special category status to the State of Andhra Pradesh without any further delay. The Government may kindly implement the provisions of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 in the right spirit. The Government may also allocate funds to wipe out the deficit Budget by timely release of funds. As the State is reeling under severe financial crisis, I would like to request the Central Government to show big brother's faith towards its younger brother.

Sir, our State of Andhra Pradesh is having 13 districts. I would like to request the hon. Prime Minister and the Government of India to sanction 13

major industries in these 13 districts in this Budget. The Government should consider setting up the All India Institute of Medical Sciences at Mangalgiri which is there in the capital area; the coastal corridor from Vizag to Chennai; a steep plant in Kadapa; a petro-chemical industry in Visakhapatnam; and Dugarajapatnam port in Nellore which have all been promised in the State Reorganisation Act. The Government may also consider setting up an Aqua Park in West Godavari. More than 50 per cent of seafood is produced …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: आपकी पार्टी के और भी सदस्य हैं। आप कृपया अंतिम वाक्य बोलें।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I will just conclude. The hon. Prime Minister has really coined a great slogan `*Sabka sath, sabka vikas aur sabka bishwas'*. But how come the hon. Prime Minister justify this when we are left alone. Are we not an integral part of Hindustan*?* …(*Interruptions*)

Thank you …(*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (Not recorded)

***श्री पी. पी. चौधरी (पाली):**

---

* Laid on the Table

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):

*Laid on the Table

(1640/RU/MM)

1640 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Union Budget of 2019.

First of all, like every Member has done, on behalf of the Telugu Desam Party, I would like to congratulate hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, for being the first exclusive Finance Minister to present the grand Budget for this country. We also respect the position she is in right now. We have also elected her as a Rajya Sabha Member from Andhra Pradesh. So, it means a lot to us that she has presented a full-fledged Budget.

Other than this, the rest of the points that I am going to make are very disappointing on the part of the Central Government, looking the way that they have presented the Budget.

First of all, whenever a Budget is to be presented, it is preceded by the President's Address. After the President's Address, *The Economic Survey* will be released. The President's Address gives the vision of the Central Government. It shows the direction in which it is supposed to proceed. Then *The Economic Survey* comes in, which depicts the strategy on how to go about the vision. Then comes the Budget. The Budget gives out the numbers, the allocations on strengthening the path that the Government wants to take on achieving its strategy and its vision. But it is missing this time. It has totally gone out of convention. What is very disappointing is that, in the Budget Speech,

there are no numbers at all. It has just words in it. It was just like an extension of the President's Address itself. This is not the convention just in the history of our country but it is there in other countries as well. The convention of the Budget is that it has to be supported by proper numbers.

Now, there is a leading confusion because of non-mentioning of numbers. When it was pointed out to the hon. Finance Minister, she has clarified that we have to look into the books. We did as she said. We looked into the books but then it was more confusing. In the books, especially *The Economic Survey* and the Budget, there have been discrepancies in numbers.

For example, I would start by mentioning the discrepancy between the Budget allocations and the actual figures for Central expenditure and revenue which is contained in *The Economic Survey*. Also, there has been a dubious representation of the nominal GDP. In some places, the numbers are presented from the same Financial Department. At one place, it is mentioned as 12 per cent and in the other place, it is mentioned as 11 per cent. If we take the inflation rate as four per cent, the real GDP amounts to eight per cent in one case and seven per cent in the other case. Which is right and which is wrong? What is to be believed? This is the kind of confusion that is arising from the documents that have been presented through the Budget.

I would like to provide another example. According to the actual figures of receipts and expenditure, when it was asked to the hon. Finance Minister, she mentioned that the fiscal deficit was 3.3 per cent. But it is stated in the Revised Estimates that Rs.10,963 crore amounts to 3.45 per cent. Figures about fiscal

deficit are different, figures about GDP are different. This kind of discrepancies in numbers is leading to a lot of confusion. So, we cannot really understand what the Budget is actually saying.

There have been talks about five trillion dollars economy. That is not the solution for everything. That is not the solution especially for the ground level problems that we are facing today.

One of the problems that we are facing today is unemployment. One of them is job crisis. There are many similar problems because of which the people of the country are facing huge difficulties. I would like to mention some points regarding unemployment crisis.

Again, I would like to stress that the numbers that have been presented through the Budget are not right and there are many discrepancies.

There are other points which are to be taken up on priority. Our hon. Member from YSRCP also spoke about them. He spoke about the rights of Andhra Pradesh. You have been a witness of how we have been fighting for our rights for the last five years. These are the rights which have been promised to us on this very floor of the House and Parliament.

One of them is the special status for Andhra Pradesh. Then we have other issues like Railway Zone, funds for building our new capital, Amaravati and funds for Polavaram and backward districts. My district, Srikakulam, was supposed to receive a special grant. That also has not been granted.

On deficit budget, what we were stating to the Central Government was Rs. 16,000 crores and what they have stated to us was Rs. 4000 crore. At that

point of time, we thought that they had something against the TDP or the State Government of Andhra Pradesh and that is why, they were mixing up the numbers. But now, we have seen that they are doing this with the whole country itself. All numbers are being misjudged; all numbers are being fudged. Even regarding the Report of the NSSO on unemployment, they said that it was a draft Report. But after the elections, they have released it which said that unemployment is at the highest in the country in 45 years.

(1645/NKL/SJN)

Then, they did not release the suicide data of the farmers since 2015. I wanted to do some research on the agricultural crisis. I wanted to see how many suicides are happening across the country. But no report has been published since 2015. So, there is a serious concern regarding the data which is coming out from the Central Government. There is a lot of confusion, especially there seems to be no statistical integrity with this Government, and that is what we are questioning today.

Now, I come back to AP rights. I have already mentioned about the special status. Now, all eyes are on the YSRCP because they have won with a huge mandate. What he is saying is right in the sense that we have come down to three. But we are not in a crisis. I again want to mention that TDP is not in a crisis. We take this as an opportunity to come back. But today, they have won with a huge mandate of having 22 Members in this House. Now, all eyes are on them. How are they going to achieve the special status?

I would like to pose this question to the Central Government also because we are listening through various mouths, especially, from the hon. Prime Minister Sir, hon. Home Minister Sir and also the hon. Finance Minister. They are all saying that the special category status cannot be granted. So, we also want to see how the YSRCP, which has convinced the people that they are going to achieve the special category status, is going to achieve it. You tell the people of Andhra Pradesh how you are going to achieve this. We will be very happy if we are getting the special category status. You have also seen how we have fought for it.

The other point is this. This Government does not have any right to speak about cooperative federalism. I am sorry to say this. But we also have proof right now. This Government speaks about cooperative federalism. I also want to give an example. Even after repetitive demand for the rights of Andhra Pradesh, what they have done today is this. The GIFT City has been proposed in Gujarat. You know about Gujarat. Many of the Members present here also know that it is supposed to be the model State. Why is it so? It is because Narendra Modi*ji,* our hon. Prime Minister, has been the Chief Minister of Gujarat for four times. Whenever the development of this country had been talked about, Gujarat was taken as an example. So, it was one of the leading and the most developed States in this country, and to such a State, even today, you are extending your favouritism by granting special tax benefits in a bid to boost investments at the International Finance Service Centre near Gujarat International Finance Tec-City….(*Interruptions*) Sir, please grant me four minutes. I will complete my speech.

Sir, now, we are a divided State. You know what financial crisis Andhra Pradesh has been facing. We are not just demanding for something out in the

open. Whatever we have been asking are our rights. But now, Gujarat has been favoured in such a way that it is being given tax benefits, it is being given additional budget. But if we talk about a State like Andhra Pradesh, how can we compete with the States like Gujarat tomorrow if everything will go to Gujarat? There is no way that this Government can use cooperative federalism. This is totally cooperative favouritism that is being done to only BJP-ruled States.

I will come back to the issue of five trillion dollars economy. This is being provided as an example, as a solution to all the problems that the country is facing today. If our economy, today, is 2.7 trillion dollars, we are expecting it to grow to 5 trillion dollars in five years. I am not being a pessimist. Everybody here knows that I am very optimistic. I am saying this because whenever someone questions anything said by the hon. Prime Minister*ji,* he says that he is a professional pessimist. I am not trying to be a pessimist. I am just being a maths student. If today's 2.8 trillion-dollar economy has to be 5 trillion-dollar economy in five years, our GDP has to grow, at least, at 10 per cent but we are saying that the GDP is going to grow at 8 per cent. Even that is also debatable because somewhere it says 7 per cent. Nothing is to be believed. What is going on in this country with the numbers is that nothing is to be believed. In five years, you want it to be 5 trillion dollars. In 2025, you will want it to be even more.…(*Interruptions*)

Now I come to the most important point. Being a young Member, I have to talk about the unemployment situation in this country. 'Make in India' is a failure. Other than that, 'Mudra Yojana' is also a failure. About 53 per cent of Mudra loans are NPAs today. At least, Rs. 22,000 crore are depicted as non-performing assets under the 'Mudra Yojana'.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आप समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I will say 'Make in India' is a failure. A lot of people might debate with me but I will keep saying that until the hard facts are placed on the Table.…(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, यह एलिगेशन है।…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Yes, Sir, I am putting an allegation.…(*Interruptions*) I am putting the allegation on the Central Government.…(*Interruptions*) I will keep putting this allegation.…(*Interruptions*) I will keep saying that 'Make in India' is a failure.…(*Interruptions*)

माननीय सभापति : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : जवाब देने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I am just concluding.…(*Interruptions*) Nishikant*ji,* please let me finish.…(*Interruptions*) Sir, they are taking away my time.…(*Interruptions*)

(1650/SRG/GG)

`Make in India' is a failure until the Central Government proves it is not that. They have to place hard facts on the table. …(*Interruptions*) They have to display to the country how many companies have come through `Make in India'; how many jobs have come through `Make in India'; how many people are employed through `Make in India'. Until a special report is released under `Make in India', I cannot say it is a hit; it is a failure. …(*Interruptions*). They have to come out with straight

facts. Whenever the youth is asking for employment, they will question back to the youth: `Are you national or anti-national?' Whenever they ask for jobs, they will ask: `Are you for Pulwama or are you for Balakot?' They pose all these questions. …(*Interruptions*). They divert their mind from unemployment. They bring all other things into the mind of the young people. …(*Interruptions*). You can divert these issues for some time, maybe for the elections, but it will come back and it will grip your neck. That is why, I am warning you that unemployment is a major problem. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): बैठिए, आप बैठ जाइए।

श्री वरुण गांधी जी।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, nothing is going on record.

…(Interruptions) …(Not recorded)

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (पीलीभीत): सर, क्या मैं शुरू करुं? सर, इनको एक मिनट में खत्म करने दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: नायडु जी, आपका समय समाप्त हो गया है, प्लीज़ बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: वरुण जी, सिर्फ आपका माइक ऑन है, बाकी सबका ऑफ है।

…(व्यवधान)

(ends)

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):**

---

* Laid on the Table

1652 hours

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I rise to support the Union Budget. …(*Interruptions*). I rise to support the Union Budget in letter and spirit. I want to put my observations forthwith. …(*Interruptions*).

माननीय सभापति: आपका समय पूरा हो गया है। Nothing is going on record.

…(*Interruptions*)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): The Budget has always been a consultative process. …(*Interruptions*). सर, हम लोग कोई दंगल तो कर नहीं रहे हैं। …(व्यवधान) आप इनसे आग्रह कर लीजिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: पुन्नुस्वामी जी, आप क्यों खड़े हो रहे हैं, बैठ जाइए। Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): The Budget has always been a consultative process. …(*Interruptions*). Sir, I cannot speak like this. …(*Interruptions*). I am sorry. …(*Interruptions*).

माननीय सभापति: नायडु जी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप अनुभवी सांसद हैं। समय की सीमा समाप्त होने के बाद आपको स्वयं बैठना चाहिए। आपको चार बार समय दिया गया। आप प्लीज़ बैठ जाइए। Naidu Ji, you are a very senior MP now. गल्ला साहब आप भी बैठ जाइए, नेनी साहब आप भी बैठिए। वरुण जी आप बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): The Budget has always been a consultative process and whether it is industry leaders, whether they are

experts, whether they are social scientists, important voices have cooperated in the presentation of this document.

(1655/KKD/KN)

Sir, seventy-two countries, all over the world, are indulging in participatory budgeting today, which basically means that citizens prevent their Governments from unilaterally putting forth a Budget and they present their civil policy preferences and priorities to negotiate local budget allocations.

I was recently in Brazil and I was in the city of Porto Alegre, which is supposedly the best governed city in the world where neighbourhood assembly's community organisers work with participants to identify proposals for capital investment.

My question is this. Can the Government initiate a new kind of budgetary process slowly with pilot projects expanding forth where we share our economic and financial position with certain sections, with delegates who have been elected by community organisers, from several parts of the country, and then offer them a forum for some kind of public demand? Is it possible? It is because I think that the Government's budgetary spending would be more closely tied to actual needs. Were that to happen, it would make the Budget more representative and accountable.

My next point is on wage inequality, which remains a serious obstacle towards social and inclusive growth. In *India Today*, I was looking at the

fact that we were the first developing country in the world to put the Minimum Wages Act in 1948. But till date, there is no directive to the Minimum Wage Act. If, for instance, we look at the fact that 30 per cent of workers are not really protected by the law in any manner, it is a fact that there is no provision in the Minimum Wage Act, 1948 to cover all workers. If we go deeper into this, there is a scheduled employment and a scheduled job category. Scheduled employment is a sector including tea plantation, mining etc. Scheduled employment refers to a job type for unskilled workers. Now, in the State of Mizoram, there are only three scheduled employments whereas in the State of Assam, there are 102 scheduled employments. Does that mean that in the State of Mizoram, people are only doing three kinds of work? It is something for us to think about.

There is a significant variation in the minimum wage rates. In Delhi, it is Rs. 538 and in Nagaland, it is only Rs. 115. Assuming that the costs of living etc., are different, even then, the range difference between highest and lowest minimum wage rate in a given State is wide. In Kerala, it is Rs. 905 and in Nagaland, it is only Rs. 16, which means whatever kind of job you do in Nagaland, the minimum wage rate is only just Rs. 16. How do you standardise this?

My request to the Government is that we declare a national floor level minimum wage rate and incorporate it into the Minimum Wages Act, 1948 through revision because this will make it statutory; it will act as a benchmark

for increasing minimum wage; and it will give workers rights to agitate and protect their demands at will.

Can we have a universal basic income in our country? I would quote two studies of SEWA that were done in Dindori and Alirajpur in Madhya Pradesh where it showed that in the 62 villages that were taken, 90 per cent of them escaped informal debt by becoming producers – whether it is of cloth, whether it is of *kulhars*, whether it is of milk etc. Some unconditional basic income has served to reduce child labour, to produce sustainable increases in income and to reduce informal debt from moneylenders, which is a vicious trap that we all know about.

The British Economic Gazette says that in the time of *Rajas* and *Maharajas* in 1925, one per cent of India owned 25 per cent of India's wealth. Today, one per cent of India owns 73 per cent of national wealth; and the poorest minimum wage labourer will take 941 years to achieve what a top executive earns in one year.

While I wanted to discuss compensatory afforestation, I congratulate the Government on the success of UJALA Yojana, which has entailed distribution of 35 crore LEDs. But I would like to add: can we replicate the same model for solar stores and battery chargers?

(1700/RP/CS)

There are millions of people who are living off-the-grid electricity today. It will prove a major boost to them, both, in terms of light and fuel. It will also reduce our LPG burden, etc.

When we talk of afforestation, the environmental laws are old. About 90 per cent environmental laws were made before 1947, the ones we are carrying on with. They are confusing. Many of them contradict each other. Can we have the best minds in our country who sit and write one law for the forest, wild life and the forest people. Another set of best minds can write a codified law for the environment which is increasingly becoming an urban issue today. Can we have an institutional restructuring? The forest in India accounts for 21 per cent but the Forest Service is demoralised and in decline. The working mechanism of the Forest Service must be similar to the Army or to the police in terms of training and new methodology. We can have specialisations for wild life tourism or protection and it must be a specialised service. You can not have a forestry service official working in the passport office or in the RTO. It does not make any sense to me.

Sir, when we talk about financial independence, in the CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) the Supreme Court has collected Rs. 54,000 crore today in terms of what we call NPVs, which is, net present value of forests that have been used for non-forestry purposes. Today, all of this is lying with an *ad hoc* CAMPA Authority. Not a single penny has been spent. If we can, once again, bring the best minds into

this and do a National Afforestation Programme together, I think, there would be a lot of value-add in this.

1702 hours (Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

The wildlife towns need to be boosted. The Ranthambore National Park in Sawai Madhopur had zero revenue before 1985. Today, it has a revenue of about Rs. 500 crore a year. It is just one district. If we look at Bharatpur, Chandrapur, Chikmagalur, Jabalpur, etc., across the country, can we not convert these into model green towns and mix them with the Swachh Bharat Abhiyan to put the best waste cycling processes in these towns and, of course, by tourism in that?

Sir, we need a National Employment Policy to lay out the kind of good quality jobs that the Government seeks to generate through investment and skilling methods. We may have a roadmap for these quality jobs with tax incentives of entrepreneurs and reduced regulatory burdens. The statistics is this. It costs Rs. 26 lakh to create one steel job in the country and it also costs Rs. 1 lakh to create nine textile jobs in the country. What we should be investing in is very clear to me. Look at the facts of employment guarantee. Europe was almost completely bankrupt in 2013. Countries like Greece had 60 per cent unemployment; Italy had 50 per cent; and Spain had 45 per cent unemployment. In Europe, they spend € 3.5 billion for putting an employment guarantee scheme where they said: “We will do three things: Either we will pay for your further education till you get skilled or whatever skill you have, according to that, we will give you a job or we will give you an apprenticeship according to which you can

get a job later." Can we do the same thing? Can we create a National Employment Grid? If a construction company in Patna needs 300 welders, can we not create a National Employment Grid where welders from Bhubaneshwar go and work there? I mean, we need, now, to start thinking of big solutions.

I want to end by talking about agriculture. It is true that the MSP hike is and fixed at 50 per cent over A2+FL cost of production. It is a good step for Kharif crop of 2018-19. However, the Economic Survey itself says that only 29 per cent of crops are sold at MSP. Can we do two things? Can we introduce a landmark legislative intervention on Right to Sell at MSP? If we do this, I think, it will save a lot of lives.

(1705/RCP/RV)

Consistently over the last 10 years, I read reports that over 20 per cent of farmers, particularly in areas like Bundelkhand etc. are not aware of MSP etc. Can we do something about that?

I just want to end with two points. One is, we have spent a lot of time talking about water. But we reward States for behaviour that is not the best practice. Madhya Pradesh has got double the water footprint for wheat of Uttar Pradesh. Punjab has got double the water footprint for paddy of the next State which have procurement. But we do maximum procurement for these crops from these States. Can we work with these States and the farmers to try and institute a different kind of aligned cropping process?

I just want to end by saying two things. There is a lot of talk about organic agriculture. Firstly, the decreased capacity of farm produce for organic

agriculture has to be dealt with; otherwise nobody is going to do it. Second is the increase in the cost of base nutrients when compared to NPK fertilizer; you need three times the amount of organic manure than for an inorganic farming. How do we deal with this? Lastly, for the rural population, to escape money lending, we need penetration of formal credit through rural finance corporations.

I want to end by just saying that this is a Government which, I believe, believes in emphatic social transformation rather than incrementalism. Together, let us build a new India. I hope that with this Budget, we start a new pathway.

Thank you, Sir.

(ends)

1706 बजे

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, आम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह बजट एक संतुलित बजट है। यह बजट किसानों की समृद्धि और गरीबों को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक रहेगा। यह बजट सभी वर्गों के हित में है तथा नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला बजट है। माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य देश को समृद्ध बनाना है, इसे ध्यान में रखा गया है। इस नए बजट से देश में एक नई आशा का संचार हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तथा आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के मॉडल 'घर-घर बिजली' को अपनाकर सफलता पाई है। इस बजट में बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 'सात निश्चय योजना', जिसमें घर-घर नल जल उपलब्ध कराने तथा चप्पे-चप्पे को बेहतर सड़कों से सुसज्जित करने की विकास योजना के मॉडल को केन्द्र सरकार लागू करने जा रही है।

महोदय, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार की एन.डी.ए. सरकार सदैव न्याय के साथ विकास करने की बात करती रही है और माननीय नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बात करती है। दोनों का आशय एक ही है। बिहार भारत का दिल है। अत: बिहार का विकास भारत के लिए और भारत का विकास बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार का निरन्तर विकास हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि बिहार को बाढ़ और अन्य आपदाओं से हमेशा के लिए मुक्त किया जाए।

महोदय, मैं बिहार के कोसी इलाके से आता हूं जहां बाढ़ की विभीषिका सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। बिहार में कृषि और उद्योग का विकास देश के अन्य राज्यों की तरह ही जरूरी है। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बजट है। विश्व की छ: बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत भी सम्मिलित हुआ है।

महोदय, केन्द्रीय बजट में की गई कई घोषणाओं से बिहार को काफी फायदा मिलने वाला है। ग्रामीण सड़कों पर खर्च करने वाले बजट को पिछले साल 15.5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 19 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की तादाद बढ़ी है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला को एक लाख रुपये लोन देने का प्रावधान किया गया है। बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी अधिक है। मनरेगा में भी पैसा बढ़ाया गया है। बिहार की बहुत पुरानी मांग विशेष राज्य का दर्जा देने की है। अगर यह मांग पूरी हो जाती है तो बिहार अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा।

महोदय, इस बजट में रेलवे में नई रेल लाइन निर्माण तथा आमान परिवर्तन के हेड में 47,997.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सुपौल संसदीय क्षेत्र, जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां सुरक्षा की दृष्टि से तीन परियोजनाएं लम्बित हैं - सहरसा से फारबीसगंज आमान परिवर्तन, सुपौल-अररिया-गलगलिया नई लाइन निर्माण तथा सकरी से सरायगढ़ तक के कार्य। इन लम्बित कार्यों का पूरा कराया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है।

(1710/MY/MMN)

अत: निवेदन है कि इस मद में व्यय की आवश्यक राशि का आबंटन कर इन लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा की जाए, जिससे देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सकें। अंत में, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को इस आम बजट के लिए धन्यवाद करता हूं।

(इति)

1711 hours

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, first of all, I would like to thank Shri KCR Sir, the Chief Minister of Telangana, and my Zahirabad constituency people who gave me this opportunity.

Coming to the financial sector, providing Rs.70,000 crore for the bank capitalisation is welcome. What is needed is more effective implementation of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) provisions. In spite of the strict time limits imposed by the IBC, many cases are taking more time for resolution. This would defeat the very purpose of IBC. More efforts need to be put into early recovery of Non-Performing Assets. While there is a downward trend of NPAs, the Government cannot keep on using tax payers' money to subsidise the inefficient allocation of credit decisions of Public Sector Banks. By reducing the Government ownership of the banks to less than 51 per cent, the market forces would be allowed a greater play in weeding out poor performing banks. Further, re-capitalisation of banks cannot go on forever and a strict outer time limit should be provided beyond which no further infusion would be done.

As the hon. Minister emphasised on the teachings of Lord Basveshwara, the social reformer, in particular on the principles of 'Kayakave Kailasa' and 'Dasoha'. Kayakave Kailasa means work is worship and Dasoha refers to giving back to the society. The schemes like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Stand-Up India Scheme, giving up of LPG subsidy and other pension schemes are welcome as they will not only help the human dignity and self-esteem to go up but also work for the wellness of the society.

Coming to rural economy, formation of 10,000 new farmer producer organisations is a welcome move. What is most needed on the marketing side is a more effective implementation of MSP system by extending the procurement by Central agencies to more crops and expanded coverage. Taking up cold storage and godown infrastructure on a massive scale would enhance capital investments in rural areas. In Telangana, we have effectively utilised warehousing infrastructure fund of NABARD and have increased the godown capacity by eight times in four years.

Setting up of 100 new clusters for traditional industries and 80 livelihood business incubators and 20 technology business incubators are welcome measures for rural artisans and rural entrepreneurs.

Expansion of Swachh Bharat Mission to undertake sustainable solid waste management in every village is welcome but there seems to be not sufficient Budget outlays for this.

The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to address the critical gaps in value chain is welcome. In Telangana, we have taken up similar measures to increase the production and productivity of freshwater fish. With the completion of Kaleshwaram Lift Irrigation Project, which is claimed as the world's largest multi-stage and multi-purpose lift irrigation scheme, estimated cost is more than Rs.80,000 crore, the State now will have some of the largest reservoirs in the country. It delivers two TMC of water per day and it is working to increase the fish production in these reservoirs. The project is intended to irrigate over 45 lakh acres of new and existing *ayacut.* It is providing drinking water to Hyderabad and villages *en route* and supplying 16 TMC of water for industrial needs. But here I would also like to request and state that though the cost of the mega project, Kaleshwaram had been met from

borrowing by the Kaleshwaram Corporation but the debt servicing burden has been huge.

(1715/SAN/CP)

Hence, I would like to request the hon. Minister and the Government of India to grant national status to Kaleshwaram Project and also release additional funds so that the debt burden of the State can be eased. NITI Aayog has also recommended special assistance of Rs. 19,205 crore to Mission Bhagirathi intended to supply piped drinking water to every household and Rs. 5,000 crore to Mission Kakatiya which is meant to restore over 45,000 tanks in the State. I also seek an assistance of Rs. 50 crore to each of the backward districts as promised under the AP Reorganisation Act and that the package should be extended to all districts of the State as the erstwhile nine districts have been divided into 32 districts.

Pradhan Mantri Karamyogi Maandhan Scheme aimed at providing pension benefits to three crore retail traders and shopkeepers is a welcome move. It is requested to increase the budgetary allocation to national social assistance programme where a measly Rs. 200 per month is being provided to old-age persons, that too only to around 6.67 lakh persons in Telangana. The State with its own resources provides Rs. 2,016 per month to all old-age persons and Rs. 3,016 per month to all differently-abled persons, in all benefitting 47.88 lakh persons. The State outlay for the scheme is Rs. 11,843 crore *per annum*, out of which only Rs. 203 crores are received from Government of India. To provide security to old-age people, this amount may be enhanced to at least Rs. 1,000 crore.

Now, I come to the new India to be built on cooperative federalism. Upgradation of 1,25,000 kilometres of roads under PMGSY is a welcome move. The

Government of India is insisting that the funds released under PMGSY are transferred into the bank account of the executing agency. This is leading to avoidable idling of resources in bank accounts and is against the basic principles of prudent public finances. This matter may please be looked into.

Providing 1.95 crore houses under PM Awas Yojana is a welcome measure, but the insistence on using only beneficiaries from SECC data is creating a hurdle for the States to access these funds. This condition may be relaxed as Telangana has taken up a massive 2-BHK programme to provide dignity and privacy even to the poorest Indians.

There are a number of positive measures which have been announced in the Budget, which would propel India towards being a five trillion dollar economy by 2024. While all these are necessary, certain fundamental reforms which require major engagements with the States, in the area of factor markets, such as land, labour, credit, agriculture, services such as education and healthcare, are missing. While the fiscal maths and the growth assumptions made appear to be optimistic, we urge the Government of India to encourage States like Telangana, the youngest and dynamic State of the country, so that the nation can progress in the true spirit of cooperative federalism.

(ends)

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर):

* Laid on the Table

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर):

* Laid on the Table

1718 बजे

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति जी, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं सबसे पहले आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति जी, मैं देश के प्रधान मंत्री, देश के वित्त मंत्री और उनके राज्य मंत्री तथा पूरी कैबिनेट को भी हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं।

महोदय, यह वास्तव में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं के विकास का बजट है और वास्तव में यह धरती पर उतर रहा है। वर्ष 2014 से 2019 तक यह दिखाई पड़ा है। वर्ष 2014 में जब देश के प्रधान मंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का नाम आया, तो देश के लोगों में एक आशा जागी कि एक ऐसी सरकार से हमें निजात मिलेगी, जिसने पूरे देश में लूट मचाई हुई है। एक अच्छे शासक के रूप में नरेन्द्र मोदी आएंगे, यह आशा नरेन्द्र मोदी से बंधी थी। वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2019 में जब चुनाव हुआ, तो लोगों के अंदर यह विश्वास आया कि वही नरेन्द्र मोदी, जो हमारी आशा पर पूर्णरूपेण खरे उतरे हैं और देश का पुन: नेतृत्व करने के लिए सामने आए हैं। लोगों ने उसी का परिणाम वर्ष 2019 के लोक सभा के चुनाव में दिया। लोगों के मन में यह विश्वास है कि गांव, गरीब, किसान और मजदूरों का कल्याण जो नरेन्द्र मोदी जी के माध्यम से चल रहा है, वह होगा।

(1720/NK/RBN)

महोदय, छोटी-छोटी बातों, जिसे कोई नहीं देखता था, गांव में इज्जत घर यानी शौचालय का निर्माण किया। हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। माताओं व बहनों के कष्ट और पीड़ा को महसूस करते थे। माताएं और बहनें शौच के लिए संध्या या अंधेरा होने का इंतजार करती थीं, इसकी वजह से कई सारी बीमारियां पाल लेती थीं। देश के प्रधान मंत्री धन्य हैं, जिन्होंने पूरे देश में शौचालय निर्माण का मिशन के तौर पर एक अभियान चलाया। आज करोड़ों घर इज्जत घर से आच्छादित हो रहे हैं। आज गांव-देहात में भी माताओं व बहनों को संध्या का इंतजार नहीं करना पड़ता है। वे आवश्यकता पड़ने पर इज्जत घर का इस्तेमाल करने का काम कर रही है। आज हर घर में जल नल की व्यवस्था अलग

से हो रही है। देश में अलग से जल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया है। गांव, गरीब, किसान और मजदूर भी नल का जल पिएं, शुद्ध जल पिएं, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने सोचने का काम किया है। काश, इसके पहले सोचा जाता, आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, वे अगर गांव के गरीब, किसान और मजदूरों के बारे में सोचते, तो हमें लगता है कि आज उसे और आगे बढ़ाकर नरेन्द्र मोदी जी उसे आच्छादित करने काम किए रहते।

महोदय, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा नहीं। चाहे सड़क की बात हो, ग्राम सड़क योजना की बात हो, आज 1,25,000 नई सड़कों के निर्माण का टारगेट है। आज गांव में भी सड़कों का जाल दिख रहा है। सड़क निर्माण के माध्यम से गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है, ताकि यातायात की अच्छी सुविधा मिले। चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, रेल की बात हो, चाहे हवाई मार्ग की बात हो या चाहे जल मार्ग की बात हो, सभी पर विशेष रूप से इस देश के बजट में प्रावधान किया गया है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा।

सदन के माध्यम से देश के सामने जो बजट आया है, इस बजट के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में विकास में क्रांति आएगी, विकास में बड़ा इजाफा होगा और गांव विकसित होंगे। आवास की बात, सभी को आवास की बात किसी ने नहीं सोची होगी, उसके लिए धरती पर काम हो रहा है। करोड़ों लोगों को आवास मिला है और आगे आने वाले दिन, यानी वर्ष 2022 तक देश के सभी लोगों को आवास मिले, किसानों की आय दोगुनी हो जाए, देश की सरकार ने क्रांति लाने का काम किया है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो। पूर्व के माननीय सदस्यों द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है। वास्तव में छह हजार रुपये एक साल में किसान के खाते में जाना, इसमें पहले कुछ पाबंदी थे, कुछ स्तर बनाए गए थे, तमाम स्तर को समाप्त किया गया है। जो किसान खेती कर रहा है, जो कृषक है उसके खाते में छह हजार रुपये जाएंगे।

महोदय, चुनाव के समय लोग इसका मखौल उड़ा रहे थे, जब यह योजना आई। लोग प्रति दिन सत्रह रुपये जोड़ रहे थे। आप उस किसान से जाकर पूछिए, जिसके पास एक रुपये भी नहीं है। आज अगर उसे दो हजार रुपये भी मिल रहे हैं, ट्रैक्टर वाले खेती कर रहे हैं, खाद वाले उनको खाद-बीज दे रहे

हैं। चूंकि यह उनके ध्यान में है कि नरेन्द्र मोदी का दिया हुआ पैसा खातों में आएगा और पुन: किसान उससे पेमेंट कर देगा। वह किसान खेती के मामले में आगे बढ़ चला है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पशुपालन के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर एक ऐसे माननीय नेता को उसकी जिम्मेवारी दी, जिन्होंने जब राज्य में भी पशुपालन क्षेत्र में जिम्मेवारी मिली थी तो उसमें उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर कर काम किया था। पशुपालन कृषकों की आय को दोगुना करने में मील का पत्थर साबित होगा। उसमें मत्स्यपालन हो या मुर्गी पालन हो, अन्य चीजों के माध्यम से करने का काम प्रधान मंत्री जी ने किया है। उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है। कौशल विकास मंत्रालय अलग से बनाया है। नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार से जोड़ना, आज बहुत सारे लोग रोजगार खोजने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने के लायक बन गए हैं। उनको मुद्रा लोन के माध्यम से बैंक से ऋण मिल रहा है और वे रोजगर देने लायक रोजगार खड़े कर रहे हैं। वे गांव के किसानों और नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। उनको लाभ मिल रहा है।

(1725/SK/SM)

उज्ज्वला योजना के बारे में माताओं और बहनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे धुँआ रहित चूल्हे पर खाना बना पाएंगी। उन माताओं, बहनों और उनके परिवार के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि गरम रोटी और सब्जी खाएंगे। आज उनके घर तक उज्ज्वला योजना माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहुंचाई है।

अब मैं आयुष्मान भारत की बात करता हूं। आज आंकड़ा है कि प्रति वर्ष 6 करोड़ से ज्यादा लोग एपीएल से बीपीएल चिकित्सा के कारण हो जाते थे। प्रति परिवार को पांच लाख रुपये देकर उनके लिए चिकित्सा का काम आसान कर दिया है।

माननीय सभापति जी, मैं ऐसा क्रांतिकारी बजट लाने के लिए देश के माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और सरकार को हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं।

(इति)

1726 hours

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, Sir, I rise in this august House to register my views on the present Budget as well as the performance of the Government in the last five years. Before going on to the topic, I sincerely thank Madam Sonia Gandhi Ji and Rahul Gandhiji for enabling me to enter this House and to make this presentation. …(*Interruptions*). Not only that, Hon. Speaker, Sir, the Congress President and Sonia Gandhiji have also made me to function as National Secretary of the Indian National Congress for 15 long years. I also thank the people of my constituency who have given their votes to me and helped me to win by a margin of 3.6 lakh votes to enter this House.

I was a bit hesitant in the beginning to make some remarks or intervene in the debate. I found on the day of oath taking itself that there was a certain kind of unfriendly and non-congenial atmosphere. Therefore, I thought that I should watch for a while and learn what to do and then rise to speak.

This is going to my first speech. I have a word for my friends on the other side. I wish you all the best. I wish all the best for all the Members in this House particularly the Members of the ruling party for having come with a vast mandate and for having a brute majority. On some occasions, it has been exhibited in this House. You have every reason to be jubilant, enjoy your victory and pursue your points. At the same time, you should also learn to be humble, magnanimous, liberal and, all the more, democratic as this is the Temple of Democracy.

Hon. Speaker, Sir, coming to the Budget, it reads more like a prospectus of a company. Many of the Members, particularly the DMK Member, Shri Raja and also Shri Naidu mentioned about the Budget. They have said enough about the gaps in the Budget or inadequacies in the Budget. Anytime, whether we walk out or sit when the Budget is presented, at the end of it, one comes to know about the size of the Budget, for example, what is the total revenue, what is the total expenditure, whether it is a deficit budget or a surplus budget, wherefrom the funds are going to come etc. But none of these things are available in this Budget. When we want to know about these things, we have to read the replies which have come from the Ministries. There is a large volume of papers where every detail is given, and one can see these things from these papers. It is humanly impossible to read all the documents that are given. Everybody should be honest in their hearts to say that it is just not possible. It is difficult to go through all the papers and get the things.

(1730/AK/MK)

Anyway, I would like to start with the past performance of this Government. The BJP fought the elections in 2014 on the issue of development, but what had happened to that development now? In 2019, when you went to the people, you did not talk about employment. You have no strength to talk about it. You were rather ashamed to talk about employment of the people in this country as you had said that you would give 10 crore jobs whereas I would say that you have not even reached a figure of a crore.

It was also stated that you would eradicate black money, and you will bring that money from abroad and deposit Rs. 15 lakh in each account. None of you has talked about it in the last elections. I would say in this Hall that you have no courage to open your mouth. As regards the Rs. 15 lakh deposit in each account, many people in my Constituency have voted for you because if there are three bank accounts, then Rs. 45 lakh would come into their account. You have totally cheated the people of this country. So, you cannot open your mouth on this subject.

As regards the agriculturists, you had said that the MSP would be 1.5 times the cost of production plus 50 per cent profit, and you have cheated the agriculturists and you did not talk about it in this election. Nobody dared to talk about it. Further, why was there no promise about price rise to come down or commodity prices and oil prices to come down within 100 days? There is no mention about the petrol prices in this campaigning anywhere. You have not promised not to do the bank scams. You have not promised that you will not do any bank scams. The largest bank scam has taken place in this country.

Finally, I thought about why you have not spoken about it. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I am speaking for the first time in the House. …(*Interruptions*) Finally, you have generated Balakot and Pulwama.

These are the main things that you have done. The hon. MoS, Finance is sitting over here. He should know that you have tried to reach the $5 trillion economy. How are you going to do $5 trillion economy? I do not know about it. The minimum thing to understand here -- for those people who do not know a little bit of finance -- is that their last track record is very bad. The GDP was coming down from 8.2 per cent to 7.2 per cent to 6.8 per cent, which is the current GDP percentage. …(*Interruptions*) In this situation, it is impossible for you to achieve 8 per cent. I wish that you should achieve it. I very much wish that this country should achieve $5 trillion economy, but it is just not going to be possible.

As regards demonetization, do it and I am not coming in the way if it is for the good of the people. Demonetization is the single largest scam conceived and implemented in this country.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, please give me some time.

This Government has slept on this issue. They had brought demonetization, but when they withdrew 2,326 crore pieces of Rs. 500 and Rs. 1,000 denomination notes, then to print similar number of notes of Rs. 500 and Rs. 1,000 you would require eight months, but you have bluffed the people to the core and you have said that in 50 days you would achieve demonetization; everything will be over; the country will be back to normal; and black money will be brought from abroad. What a scandal it is? …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, is it not the largest scam in the country ever? …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I have not even spoken for five minutes. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, your time is already exceeded. Please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, please give me five minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, I cannot give you five minutes. You should conclude by mentioning a few more sentences.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): What is the situation of unemployment in this country? When we left power in 2014, the unemployment rate was only 2.2 per cent. Today, the unemployment rate is the largest in 45 years, and the unemployment figure is close to 8.3 per cent. You have let down the people so badly.

What is the agricultural growth? The agricultural growth, when we left power, was 3.8 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Today, it is a paltry 2.8 per cent. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now, otherwise I would be compelled to call the name of the next speaker.

… (*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Further, they have been claiming all the credit for the schemes that we have implemented.

(1735/SPR/YSH)

You said that you have done 100 per cent electrification. Who has done it? Sir, 90 per cent of electrification was done in September, 2014. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Can you conclude your speech in few sentences?

…(*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): They are taking credit. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: भगवंत खुबा जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री भगवंत खुबा (बीदर): आदरणीय महोदय, आपने मुझे सत्रहवीं लोकसभा में बजट पर बोलने का मौका दिया है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Excuse me. Let him conclude his speech in one or two sentences.

…(*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, allow me to say a few words about my constituency. I come from a constituency which is having a coastal area. It has the seafront. It needs a seafront creek to be built. I would request the hon. Minister to note this. The Government is coming up with a very large port at Kattupalli, which would affect the entire environment. It is also hazardous. There would be a huge scale of displacement. The party which is coming over here is close to the Government. Please safeguard the people and the environment. There is a company called Hindustan Motors, which has been sold. Employees of this company are not taken care of. Sir, 17 places have been recently declared as national tourist places. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Put your demands please.

…(*Interruptions*)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Kanyakumari has to be added to the list of national tourist places. When Winston Churchill, the Prime Minister of England, was travelling, press people have asked him as to who is the best politician. Winston Churchill has answered, "The one who makes tall promises to the people, go to them, and win the elections."…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Thank you.

…(*Interruptions*)

(ends)

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN):

* Laid on the Table

*श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर):

* Laid on the Table

*श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे):

* Laid on the Table

*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI):

* Laid on the Table

1736 बजे

श्री भगवंत खुबा (बीदर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र के सत्रहवें दिन बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं जिनके नेतृत्व में दूसरी बार चुनकर आया हूं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्र कल्याण के बारे में सोचने वाले परम आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने क्षेत्र के साढ़े 17 लाख मतदाता बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यहां बोलने का मौका दिया है।

सभापति महोदय, वर्ष 2014 में सेन्ट्रल हॉल का मोदी जी का भाषण आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार किसानों को समर्पित है, मेरी सरकार महिलाओं को समर्पित है, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित हैं, मेरी सरकार दीन-दलित और पिछड़ो को समर्पित है। उसी दिशा में वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। यह बहुत ही दूरदृष्टिकोण, क्रांतिकारी और मोदी जी की भावनाओं को लेकर जो लक्ष्य है, उसी के आधार पर बजट पेश किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर विश्व गुरु बश्वेश्वरा जी का जिक्र किया है। 12वीं शताब्दी में विश्व गुरु बश्वेश्वरा जी सामाजिक, शैक्षिणक और आर्थिक क्रांति के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए। (1740/RPS/UB)

बसवेश्वर जी के 'कायक कैलाशा,' 'कायक' और 'दासोहा' तत्वों के ऊपर मोदी जी की सरकार चल रही है। 12वीं शताब्दी में कायकि के नाम पर कर्मयोगी को बहुत गौरव मिलता था, उसी कारण से 12वीं शताब्दी में उनके राज्य में देने वाले थे, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं था। उसे 'कल्याण राज्य' कहते थे। वित्त मंत्री जी ने पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले पांच सालों के अंदर निश्चित रूप से हम पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2014 में हमारी इकोनोमी 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, पांच साल के भीतर वर्ष 2019 तक तीन ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी तक पहुंच पाए तो निश्चित रूप से आने वाले पांच सालों के अंदर पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी तक हम पहुंच पाएंगे। जब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी को इस देश की 130 करोड़ जनता के ऊपर

भरोसा है, 130 करोड़ जनता के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा है। देश की 130 करोड़ जनता के कर्म और इच्छा शक्ति के ऊपर भरोसा होने के नाते निश्चित रूप से आने वाले पांच सालों में भारत की इकोनोमी पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी होगी, मैं यह विश्वास जताता हूं।

16वीं लोक सभा में और अभी 17वीं लोक सभा में विपक्ष की बेंचेज से हमें सुनने को मिलता है कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सपनों को बेचा था और अभी सुनने में आ रहा है कि करनी और कथनी में फर्क है। यह भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी बहुत बढ़िया ढंग से मार्केटिंग करते हैं। मैं विपक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूं कि मोदी जी ने सपने बेचा नहीं है, मोदी जी ने लोगों को सपने दिखाए और उन सपनों को पांच साल में साकार किया है। देश की जनता को सपने दिखाने के लिए भी 56 इंच की छाती चाहिए। वह 56 इंच की छाती सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नरेन्द्र भाई मोदी जी की है। जितना मोदी जी की सरकार ने बोला है, उससे भी ज्यादा हमने पांच साल के अंदर करके दिखाया है। इसके कारण, मैं देश का तो नहीं बोलूंगा, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोलूंगा कि जहां यूपीए-2 के अंदर मेरे क्षेत्र में केवल 40 हजार शौचालय बने थे। पिछले पांच साल के अंदर मेरे लोक सभा क्षेत्र बीदर के अंदर करीब दो लाख 40 हजार शौचालय बन चुके हैं। इसके अलावा, गरीब महिलाओं के लिए जो मुफ्त में गैस दी जाती है, मेरे संसदीय क्षेत्र बीदर के अंदर एक लाख 85 हजार गरीब महिलाओं को गैस मिल चुकी है। इसके साथ ही, मेरे लोक सभा क्षेत्र बीदर के अंदर मुद्रा योजना के तहत एक लाख 25 हजार युवा और युवतियों को करीब 458 करोड़ रुपये का मुद्रा लोन मिल चुका है। 'आयुष्मान भारत' के अंदर करीब दो लाख 35 हजार गरीबों के लिए हमने कार्ड बांटे हैं और आज तक करीब 25 हजार लोग उसका लाभ ले चुके हैं। इसलिए मैं विपक्ष के सदस्यों, खासकर कांग्रेस के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। हमने जितना बोला है, उससे ज्यादा कर दिखाया है। यह बात आपकी समझ में आनी चाहिए। यह मैं बोलना चाहता हूं।

(1745/RAJ/KMR)

सभापति महोदय, मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे उस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। विपक्ष के सदस्य 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' के बारे में सदन के अंदर और सदन के बाहर भी बहुत अफवाहें फैलाते हैं। जब 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'

वर्ष 2016-17 में लागू हुई थी, तब से लेकर वर्ष 2018-19 तक मेरा लोक सभा क्षेत्र, बीदर देश में नम्बर वन है। केवल एनरॉलमेन्ट में ही नहीं बल्कि वर्ष 2018 और 2019 में एक लाख, 85 हजार किसानों ने बीमा का एनरॉलमेन्ट किया था।...(व्यवधान) टोटल दो लाख 56 हजार किसानों ने एनरॉलमेन्ट किया था।...(व्यवधान) सूखे के कारण मेरे क्षेत्र में इस साल 1,29,903 किसानों को 126 करोड़ रुपये तक पैसा मिल रहा है। इसके अलवा न्यूनतम समर्थन मूल्य के केन्द्र से हर साल उड़द, मूंग, सोयाबिन, ज्वार, इतर धान, कम से कम उससे डेढ़ लाख किसान मेरे क्षेत्र में फायदा उठा रहे हैं। मैं सभी विपक्षी सदस्यों को अपने क्षेत्र बीदर आने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप वहां आइए। दो लाख किसानों को लाभ मिल चुका है।...(व्यवधान) आपके समक्ष किसानों की सभा कर देता हूं। सभी विपक्ष मेरे आमंत्रण को स्वीकार करिए, मैं आपसे यह विनती करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): कृपया आप कनक्लूड कीजिए।

श्री भगवंत खुबा (बीदर): सभापति महोदय, नए बजट में नए भारत की बात कही गयी है, गांव के लिए रास्ता, हर घर को नल से पानी, हर घर के लिए बिजली, हर गरीब के लिए घर, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा, ऐसे कई योजनाओं की बात कहीं गई है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने यहां पर 60 सालों तक राज किया है। इसके ऊपर 125 वर्ष की एक पुरानी दीवार के ऊपर एक वृक्ष और कांग्रेस कहती है कि मैंने वह किया, यह किया। उस दीवार के ऊपर कोई बीज बोआ नहीं, कोई पानी नहीं डाला, कोई संरक्षण नहीं, लेकिन वृक्ष बड़ा हुआ है। कांग्रेस देश के विकास में बाधा बन चुका था। इसलिए वर्ष 2019 में लोगों ने कांग्रेस को नकारा है।...(व्यवधान)

मैं कांग्रेस और विपक्ष वालों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक वाक्य को याद दिलाना चाहता हूं कि

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।

यह समझ कर विपक्ष आने वाले पांच साल सकारात्मक सोच से सहयोग करें।...(व्यवधान)

(इति)

1749 बजे

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री, जिन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन बजट में उनके लिए बहुत कम प्रावधान किया गया है। ये एससी और एसटी की बात करते हैं, उन्हें गुमराह करने की भी बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके लिए बजट का प्रावधान करें, उसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

दूसरी बार यह सरकार बनी है। पिछली सरकारों ने इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से योजनाएं संचालित करने का काम किया लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जो योजनाएं चल रही थीं, उन योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है।…(व्यवधान) सभापति जी, बाबा साहब के नाम के पुस्तकालय बंद करने का काम किया है।…(व्यवधान)

(1750/IND/SNT)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): आप बैठ जाएं। केवल माननीय सदस्य की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

…(व्यवधान)*… (Not recorded)*

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नाम से पुस्तकालय था, उसे भी बंद करने का काम सरकार ने किया है।…(व्यवधान) महोदय, बजट में गरीब, गांव और किसान की बात का जिक्र किया गया है। आज गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। गांव से लोग पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। जब गांव में विकास होगा, जब गांव में बिजली की व्यवस्था होगी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उस गांव में चिकित्सा की व्यवस्था होगी, वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी और रोजगार मिलेगा, तब गांव सम्पन्न होगा। सरकार ने कहा कि हम गरीबों का उत्थान करने का काम करेंगे। गरीब के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब लोग शिक्षित बनेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी देश मजबूत

बनेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो उसे पिएगा, वह दहाड़ने का काम करेगा। मैं सरकार से चाहता हूं कि गांव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का काम करे।

सभापति जी, सरकार ने कहा कि हम शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र नगीना है। वहां पांच राजकीय विद्यालय बने हुए लगभग दो साल हो गए हैं। राजकीय बालिका विद्यालय तहसील धामपुर में है, जिसका भवन बने लगभग ढाई साल का समय हो गया है। दूसरा अल्पसंख्यक राजकीय बालिका विद्यालय मुकरपुरी में है। तीसरा बालिका राजकीय विद्यालय ननसावली में है। एक बालिका पॉलिटेक्नीक स्कूल मुकरपुर में है, जो आज तक शुरू नहीं हुआ है। आपकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें तो करने का काम करती है, लेकिन घरातल में मेरे नगीना क्षेत्र में चार विद्यालयों की बिल्डिंग तैयार खड़ी है, सरकार वहां शिक्षा देने का काम नहीं कर रही है। मैं मांग करता हूं कि वहां शिक्षा देने की शुरूआत करने का आप काम करेंगे।

महोदय, जिस तरह से सरकार ने किसान की बात कही है कि जिस देश का किसान मजबूत होगा, वह देश तरक्की करेगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। हमारी सरकार ने गन्ने के किसान का भुगतान करने का काम किया।...(व्यवधान) हमारी सरकार ने गन्ना किसान के बकाया भुगतान पर ब्याज देने की शुरूआत की। आज उत्तर प्रदेश में किसान का जो बकाया है, उसका भुगतान सरकार करने का काम नहीं कर रही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, यदि सरकार किसान को मजबूत करना चाहती है, तो खेती के जो उपकरण हैं चाहे ट्रैक्टर हो, हैंड पम्प हो या दूसरे उपकरण हों, वे सस्ते करने की जरूरत है। यदि किसान को बिजली महंगी मिलेगी, तेल भी महंगा मिलेगा, तो किसान की आय कैसे दोगुनी हो सकती है? अगर आप चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत हो, तो इसके लिए मैं मांग रखता हूं कि खेती को उद्योग से जोड़ देना चाहिए। जिस दिन आप खेती को उद्योग का दर्जा दे देंगे, उस दिन देश का किसान मजबूत हो जाएगा।

(इति)

1754 बजे

श्री के. नवसकनी (रामानाथपुरम):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri K. Navaskani in Tamil,
please see the Supplement. (PP 467 to 467)}

(1755/GM/VB)

Hon. Chairperson, Sir, I have never been a Member of Legislative Assembly. I have been directly elected to Lok Sabha for the first time. Tamil Nadu is facing acute water shortage and the State Government is not taking any steps to solve this crisis. I want to know how much money has been allocated by the Central Government to solve this crisis. The Government says that *Har Ghar Jal* Scheme would be implemented by 2024, but that is five years away from now. What about today? People are facing difficulties now. I request the Government to take urgent steps on war footing and issue instructions to the State Government to solve this crisis.

The Government has formulated a scheme called Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for the welfare of fishermen, but no specific proposal has been mentioned under the scheme. I want to know from the Government whether this scheme would cover fishing equipments, boats, insurance cover, health facilities for the fishermen and also GPS-fitted boats in case they lose their way during fishing. The Government should come out with specific proposals under the Scheme. I also want to know whether the housing facilities at subsidized rates would be constructed for fishermen.

There is no provision for agriculturists and minorities in this Budget. There is no mention about scholarships, increase in scholarships for students belonging to Muslim community or increasing the allocation for minorities or setting up of camps of Aligarh Muslim University at different locations where there is a huge concentration of Muslim population.

Post-Matric Scholarship for Minorities declined to 28.3 per cent. The National Minorities Development and Finance Corporation Fund declined to 64 per cent. The Maulana Azad Education Fund declined to 28 per cent.

There is no mention about protection of minorities. The incidents of assaults on minorities are increasing day by day. Has the Government allocated any funds or given any financial assistance for the improvement Waqf Boards? I am really disappointed.

I request the Government to allocate funds for the education of girls belonging to Muslim community by appropriation of money earmarked for Haj subsidy, which has now been withdrawn.

1759 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

I represent Ramanathapuram Lok Sabha constituency which has the longest coastline in Tamil Nadu and where around 200 villages consist of mainly fishermen. The fisheries sector could not find new hopes in the Union Budget 2019 despite the announcement of a new scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. While the Budget says it will address critical gaps in the value chain, including infrastructure, modernisation, traceability, production, productivity, post-harvest management and quality control, I think it can bring no substantial change in the life of fishermen. The Budget has not addressed any of their long-standing grievances. One of the major demands, that is, GST cut on fishing equipment, was totally ignored. Subsidy on kerosene and diesel also received no attention. Since fishing community is vulnerable to natural calamities

including cyclones, they should be allowed to get relief from the National Disaster Relief Fund. None of their demands were met in the Budget. It is my request to also include fishermen in loan waiver scheme, just like farmers.

(1800/RK/PC)

The Finance Minister mentioned in her speech about fisheries framework development, possibly under the new Department of Fisheries created recently, but again there are no details. The allocation for Blue Revolution has dropped by about 15 per cent from BE of 2018-19.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल बजट पर डिसकशन चल रहा है। अगर हाउस की सहमति हो, यदि आप सेंस ऑफ हाउस ले लें तो हम लंबे समय तक बैठकर बजट पर पूरी चर्चा समाप्त कर दें, तो बेहतर रहेगा। इसलिए हाउस को दस बजे तक के लिए बढ़ा दें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बताइए कितने बजे तक के लिए हाउस को बढ़ाएं?

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, दस बजे तक के लिए बढ़ा दें। …(व्यवधान)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : महोदय, भोजन की व्यवस्था भी करा दें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, मैक्सिमम टाइम के लिए आप हाउस का सेंस ले लीजिए। अगर आप हाउस दस बजे तक के लिए बढ़ाएं, तब भी प्रॉब्लम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : अभी सभा को नौ बजे तक के लिए बढ़ा देते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन पर विचार करेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): What about the dinner?

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Sir, in spite of the devastation recent years has seen due to floods and other disasters, allocations have dropped 31 per cent for infrastructure for disaster management.

There is also reduction in fund allocation for MGNREGA. It has actually dropped from RE of 2018-19. This certainly needs to be increased. The funding, to the Employment Guarantee Scheme, saw a 1.7 per cent decrease.

The overall Budget of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, now part of the new Ministry of Jal Shakti, has seen a drop from Rs.22,357 crore in BE of 2018-19 to Rs.20,016 crore in BE of 2019-20.

I would now like to talk about the UDAN Scheme. The Government says with great pride that UDAN Scheme is successful. My constituency Ramanathapuram is a pilgrim and tourist destination. Lakhs of people are visiting every year. Has the Government any plan to set up an Airport at Rameswaram so that it could be connected to Madurai, Chennai and Tuticorin under the UDAN Scheme?

In this Budget, there is no scheme for poor. There is no scheme for women, minorities, and middle-class people. For whom has this Budget been prepared? Is it for corporates alone? I once again reiterate that this Budget is anti-poor, anti-public, anti-common man, anti-minorities, and anti-workers. With these words, I thank you very much for giving me this opportunity.

(ends)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)